

भाग 'ख'
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

अध्याय-II

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

अध्याय - II

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

2.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

2.1.1 प्रस्तावना

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) को आर्थिक प्रकृति के कार्यकलाप करने एवं राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए स्थापित किया जाता है। 31 मार्च 2017 को दिल्ली के रा.रा.क्षे. में 17 सा.क्षे.उ., सभी कार्यशील थे। इनमें से कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2016-17 के दौरान कोई भी सा.क्षे.उ. निगमित या बंद नहीं किया गया। 31 मार्च 2017 को दिल्ली के रा.रा.क्षे. में राज्य सा.क्षे.उ. की स्थिति का विवरण तालिका 2.1.1 में दिया गया है:

तालिका 2.1.1: 31 मार्च 2017 को कुल सा.क्षे.उ. की संख्या

सा.क्षे.उ. के प्रकार	कार्यशील सा.क्षे.उ.	कुल
सरकारी कंपनियाँ	15	15
सांविधिक निगम	2	2
कुल	17	17

कार्यशील सा.क्षे.उ. ने उनके 30 सितंबर 2017 को नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 7,718.33 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर 2016-17 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.24 प्रतिशत था। कार्यशील सा.क्षे.उ. ने उनके 30 सितंबर 2017 को नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 2,520.95 करोड़ की हानि वहन की। मार्च 2017 के अंत में उनके पास 0.36 लाख कर्मचारी थे।

2.1.2 उत्तरदायित्व संरचना

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143(6) द्वारा शासित होती है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के पास होता है और जिसमें सरकारी कंपनी की अनुषंगी कंपनी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 143(7) के अनुसार केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक तौर पर धारित किसी भी अन्य कंपनी के मामले में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) एक आदेश द्वारा ऐसी कंपनी के लेखों की नमूना जांच करा सकते हैं और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान इस नमूना लेखापरीक्षा पर लागू होंगे। 1

अप्रैल 2014 से पहले आरंभ हुए वित्त वर्षों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से शासित होती रहेगी।

2.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों (जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित है) के वित्त लेखों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है। अधिनियम की धारा 143(6) के अनुसार यह वित्तीय लेखे, धारा 143(5) के अंतर्गत प्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होंगे।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित कानूनों के अधीन है। नि.म.ले.प. दिल्ली परिवहन निगम का एकल लेखापरीक्षक है। दिल्ली वित्तीय निगम की लेखापरीक्षा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत नियुक्त किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा एवं पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है।

2.1.4 सरकार और विधानमंडल की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासकीय विभागों द्वारा इन सा.क्षे.उ. के मामलों पर नियंत्रण रखता है। मुख्य कार्यपालक एवं बोर्ड निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।

राज्य विधानमंडल सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की भी निगरानी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में, वार्षिक प्रतिवेदनों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और नि.म.ले.प. की अभ्युक्तियां और सांविधिक निगमों के संबंध में, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, उनको अंतिम रूप दिये जाने के तीन महीने के भीतर या संबंधित अधिनियमों के अनुसार विधायिका में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

2.1.5 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का अंश

रा.रा.क्षे.दि.स. का इन सा.क्षे.उ. में उल्लेखनीय वित्तीय अंश है। यह अंश मुख्यतः तीन प्रकार का है:

- **शेयर पूंजी और ऋण:** शेयर पूंजी में योगदान के अतिरिक्त रा.रा.क्षे.दि.स. सा.क्षे.उ. को ऋणों के माध्यम से समय-समय पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

- **विशेष वित्तीय सहायता:** रा.रा.क्षे.दि.स. आवश्यकतानुसार सा.क्षे.उ. को अनुदानों और सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **गारंटी:** रा.रा.क्षे.दि.स. सा.क्षे.उ. द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए सब्याज ऋण के पुनर्भुगतान की भी गारंटी देती है।

2.1.6 राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश

31 मार्च 2017 को 17 सा.क्षे.उ. में निवेश (प्रदत्त पूंजी, निर्बाध आरक्षित निधियाँ एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 30,433.81 करोड़ था, जैसा कि तालिका 2.1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.2: सा.क्षे.उ. में निवेश

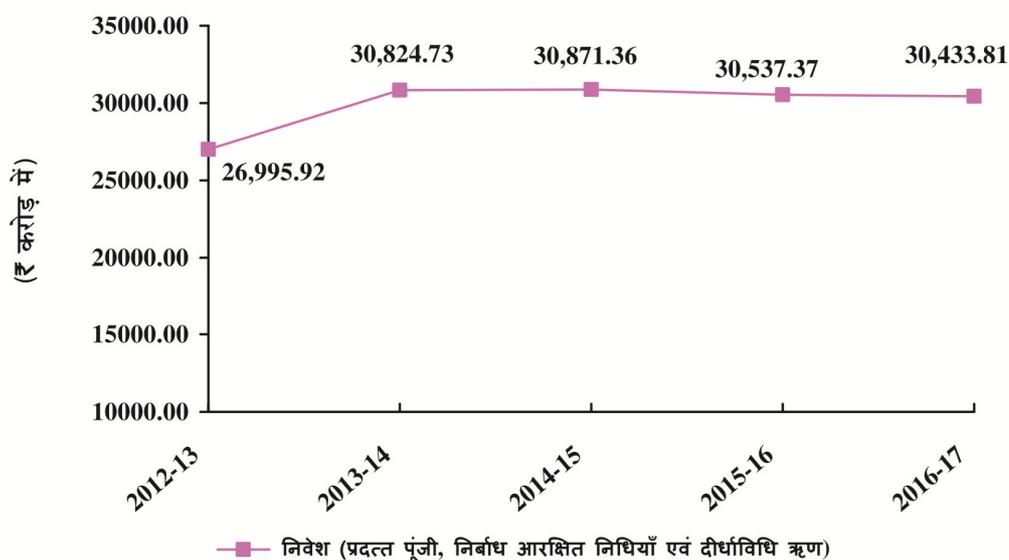
(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. का प्रकार	सरकारी कंपनियां				सांविधिक निगम				कुल योग
	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	निर्बाध आरक्षित निधियाँ	कुल	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	निर्बाध आरक्षित निधियाँ	कुल	
कार्यशील सा.क्षे.उ.	7,588.43	5,897.97	3,207.38	16,693.78	2,010.27	11,723.14	6.62	13,740.03	30,433.81

स्त्रोत: सा.क्षे.उ. एवं वार्षिक लेखों से एकत्रित सूचना

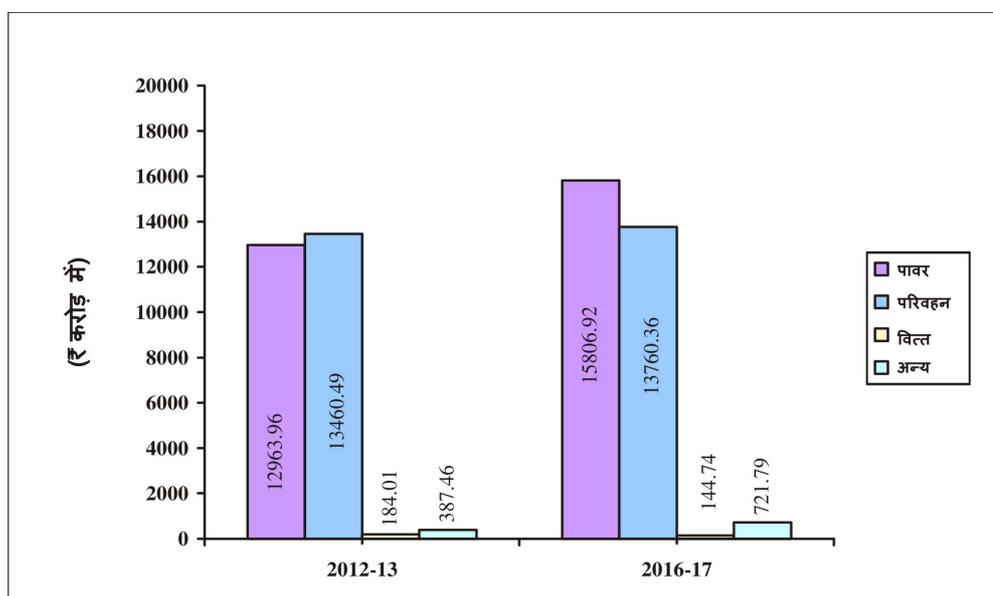
31 मार्च 2017 को, कुल निवेश में 31.54 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी, 10.56 प्रतिशत निर्बाध आरक्षित निधियाँ एवं 57.90 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण थे। यह निवेश 2012-13 में ₹ 26,995.92 करोड़ से 12.73 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹ 30,433.81 करोड़ हो गया, जैसा कि चार्ट 2.1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1.1: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश



चार प्रमुख क्षेत्रों में 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2017 के अंत में निवेश चार्ट 2.1.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1.2: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश



यह देखा जा सकता है कि पावर क्षेत्र¹ में निवेश 2012-13 में ₹ 12,963.96 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 15,806.92 करोड़ हो गया और परिवहन क्षेत्र² में यह 2012-13 में ₹ 13,460.49 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 13,760.36 करोड़ हो गया।

2.1.7 वर्ष के दौरान विशेष सहायता और रिटर्न

रा.रा.क्षे.दि.स. सा.क्षे.उ. को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सा.क्षे.उ. के संबंध में इक्विटी, अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के प्रति बजटीय व्यय का सारकृत विवरण, 2016-17 को समाप्त तीन वर्षों के लिए, तालिका 2.1.3 में दिया गया है:

तालिका 2.1.3: सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	धनराशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	धनराशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	धनराशि
1.	बजट से अंश पूँजी पर व्यय	-	-	-	-	-	-
2.	बजट से प्रदत्त ऋण	2	200.00	3	565.00	3	469.98
3.	बजट से अनुदान/ सब्सिडी	6	1,603.35	4	1,339.41	5	1,744.77
कुल व्यय (1+2+3)			1,803.35		1,904.41		2,214.75

स्त्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्रित सूचना

¹ डीपीसीएल, डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड।

² दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड एवं दिल्ली परिवहन निगम।

2.1.8 वित्त लेखों से मिलान

राज्य के सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार अंश पूंजी और बकाया ऋण के आंकड़े राज्य के वित्त लेखों के आंकड़ों के समान होने चाहिए। यदि आंकड़ें समान नहीं हैं तो संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2017 को इस संबंध में स्थिति तालिका 2.1.4 में दिया गया है।

तालिका 2.1.4: सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के सापेक्ष वित्त लेखों के अनुसार अंश पूंजी व बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

निम्नोक्त का बकाया	वित्त लेखों के अनुसार धनराशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार धनराशि*	अंतर
अंश पूंजी ³	9,297.92	9,197.64	100.28
ऋण ⁴	18,084.93	15,612.23	2,472.70

*स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्रित सूचना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये अंतर आठ⁵ सा.क्षे.उ. के संबंध में थे। इन आंकड़ों का गैर-मिलान, विधानमंडलीय परिप्रेक्ष्य एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के प्रयोग के लिए सही सरकारी व्यय उपलब्ध नहीं कराता है। सरकार और सा.क्षे.उ. को इन अंतरों का मिलान समयबद्ध तरीके से करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

2.1.9 लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के साथ धारा 129(2) के अनुसार, प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्त वर्ष के अंत से छः माह के भीतर अर्थात् सितंबर के अंत तक अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर इस अधिनियम की धारा 99 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाना, उनकी लेखापरीक्षा एवं विधानमंडल में प्रस्तुति संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

तालिका 2.1.5 में 30 सितंबर 2017 को लेखों को अंतिम रूप दिया जाने में सा.क्षे.उ. द्वारा की गई प्रगति का विवरण दिया गया है:

³ पूंजी आंकड़ों में सिर्फ राज्य सरकार का अंश शामिल है।

⁴ ऋण के आंकड़े कंपनी के अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं और वे.ले.का. के द्वारा प्रदत्त सूचना से मिलाए गए हैं।

⁵ डीएससीएफडीसी, पीपीसीएल और डीटीआईडीसी इक्विटी आंकड़ों के लिए और डीएससीएफडीसी, पीपीसीएल, डीटीआईडीसी, डीटीएल, आईपीजीसीएल, डीपीसीएल, डीएससीएससी और डीटीडीडीसी ऋण आंकड़ों के लिए।

तालिका 2.1.5: कार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या	17	17	17	17	17
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखों की संख्या	21	15	9	12	15
3.	बकाया लेखों की संख्या	12	14	22	27	29
4.	कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या, जिनमें बकाया लेखे हैं	3	4	11	14	15
5.	बकाया की स्थिति (संख्या वर्षों में)	1 से 9	1 से 10	1 से 11	1 से 12	1 से 13

जिन सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे हैं, उन्हें पिछले बकायों के निपटान और अपने लेखों को अद्यतन करने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सा.क्षे.उ. को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम एक वर्ष के लेखों का निपटान कर दें, जिससे बकाया संचित न हो।

प्रशासकीय विभागों के पास इन निकायों की गतिविधियों की निगरानी और यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है कि सा.क्षे.उ. लेखों को निर्धारित अवधि के भीतर निपटाए और अंगीकार करें। यद्यपि वित्त विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा मासिक रूप से लेखों के निपटान के बकाया के बारे में सूचित किया गया, लेकिन पर्याप्त उपचारी कार्यवाही नहीं की गई। इसके फलस्वरूप इन सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं हो सका। इस मामले को मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समक्ष भी नवम्बर 2017 में उठाया गया।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने उन वर्षों के दौरान जिनके लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, सात सा.क्षे.उ. में ₹ 2,373.31 करोड़ {अंश पूँजी: ₹ 19.28 करोड़ (एक सा.क्षे.उ.), ऋण: ₹ 522.47 करोड़ (चार सा.क्षे.उ.) और अनुदान/सब्सिडी ₹ 1,831.56 करोड़ (छः सा.क्षे.उ.)} का निवेश किया, जैसा कि **अनुलग्नक 2.1 (i)** में विवरण प्रस्तुत है। लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने और इसके पश्चात लेखापरीक्षा न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि क्या लेखों में, किए गए निवेश व व्यय को उचित प्रकार से अंकित किया गया है और क्या जिस प्रयोजन से धनराशि का निवेश किया गया था, वह प्राप्त हुआ या नहीं। इस प्रकार इन सा.क्षे.उ. में सरकार का निवेश राज्य विधायिका के नियंत्रण के बाहर रहा।

2.1.10 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

तालिका 2.1.6 सांविधिक निगमों के लेखों पर नि.म.ले.प. द्वारा जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को विधायिका में प्रस्तुत करने की स्थिति दर्शाता है।

तालिका 2.1.6: विधायिका में एसएआर की प्रस्तुति की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक के एसएआर विधायिका में प्रस्तुत हो चुके हैं	जिस वर्ष के एसएआर विधायिका में प्रस्तुत नहीं हुए हैं	
			एसएआर का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि/वर्तमान स्थिति
1.	दिल्ली परिवहन निगम	2014-15	2015-16	17.05.2017
2.	दिल्ली वित्तीय निगम	2014-15	2015-16	15.11.2016

2.1.11 लेखों को अंतिम रूप न दिये जाने का प्रभाव

लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण संबंधित कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे एवं जनधन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है। उपरोक्त बकाया लेखों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-17 में सा.क्षे.उ. का राज्य जीडीपी में योगदान भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका और उनका राज्य राजकोष में योगदान विधानमंडल को भी सूचित नहीं किया गया।

2.1.12 अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार सा.क्षे.उ. का निष्पादन

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति और कार्यशील परिणामों का विवरण अनुलग्नक 2.1(ii) में है। राज्य जीडीपी से सा.क्षे.उ. टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. की गतिविधियों का विस्तार बताता है। तालिका 2.1.7 2016-17 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि का कार्यशील सा.क्षे.उ. और राज्य जीडीपी का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 2.1.7: कार्यशील सा.क्षे.उ. टर्नओवर का राज्य जीडीपी के सापेक्ष विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
टर्नओवर ⁶	8,465.57	8,415.09	8,210.02	8,597.77	7,718.33
राज्य जी.डी.पी.*	3,91,238	4,43,783	4,92,424	5,51,963	6,22,385
राज्य स.घ.उ. से टर्नओवर की प्रतिशतता	2.16	1.90	1.67	1.56	1.24

स्त्रोत: सा.क्षे.उ. से संकलित सूचना एवं राज्य जी.डी.पी. आंकड़े

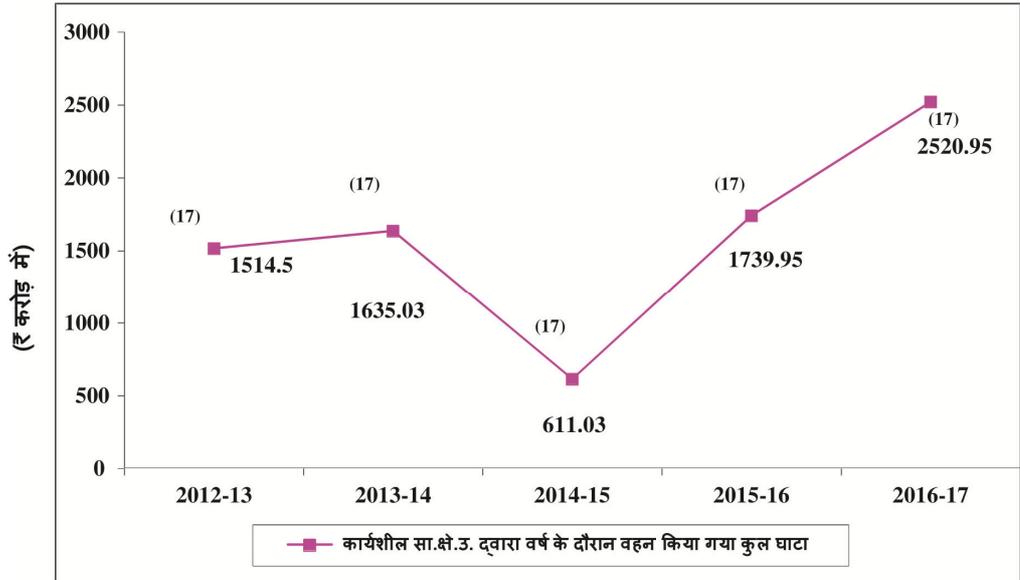
यह पाया गया कि राज्य सा.क्षे.उ. के टर्नओवर से राज्य जीडीपी का प्रतिशत 2012-13 में 2.16 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 1.24 प्रतिशत हो गया।

2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य के कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा वहन किया गया कुल घाटा चार्ट 2.1.3 में दिया गया है:

⁶ 30 सितंबर को अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार टर्नओवर

* राज्य जीडीपी आंकड़े आधार वर्ष 2011-12 की वर्तमान दरों के आधार पर हैं।

चार्ट 2.1.3: कार्यशील सा.क्षे.उ. का घाटा



(कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित वर्ष में कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते हैं)

यह देखा जा सकता है कि सा.क्षे.उ. द्वारा वहन किया गया कुल घाटा 2012-13 में ₹ 1,514.50 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 2,520.95 करोड़ हो गया।

अंतिम लेखों के अद्यतन वर्ष के सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के सारकृत वित्तीय परिणाम **अनुलग्नक 2.1(ii)** में दिए गए हैं। 01 अक्टूबर 2016 से 30 सितंबर 2017 की अवधि के दौरान 17 कार्यशील सा.क्षे.उ. में से एक कार्यशील सा.क्षे.उ.⁷ ने लेखों को 'न लाभ, न हानि' के आधार पर बनाया, दस सा.क्षे.उ. ने ₹ 967.60 करोड़ का लाभ कमाया और छः सा.क्षे.उ. को ₹ 3,488.55 करोड़ की हानि हुई, जैसा कि **तालिका 2.1.8 (क) और (ख)** में दर्शाया गया है:

⁷ शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम

तालिका 2.1.8 (क): लाभ दर्ज करने वाले कार्यशील सा.क्षे.उ. का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया	निवल लाभ
दिल्ली अजा/अजजा/अपिव अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय व विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2013-14	5.57
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	38.46
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	2015-16	2016-17	81.91
दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	2015-16	2016-17	545.31
प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	2016-17	250.75
दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	8.49
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	2.48
जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	2015-16	2016-17	4.77
दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2016-17	28.16
दिल्ली वित्तीय निगम	2015-16	2016-17	1.70
कुल			967.60

तालिका 2.1.8 (ख): हानि दर्ज करने वाले कार्यशील सा.क्षे.उ. का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया	निवल लाभ
इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	2015-16	2016-17	77.45
डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.00 ⁸
दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स लिमिटेड	2015-16	2016-17	0.00 ⁹
डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड	2015-16	2016-17	0.00 ¹⁰
डीएसआईआईडीसी मॅटनेस सर्विसेज लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.00 ¹¹
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन	2015-16	2017-18	3,411.10
कुल			3,488.55

- लाभ में प्रमुख भागीदार थे दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (₹ 545.31 करोड़), प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 250.75 करोड़), दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (₹ 81.91 करोड़) और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 38.46 करोड़)।
- दिल्ली परिवहन निगम (₹ 3,411.10 करोड़) और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (₹ 77.45 करोड़) द्वारा हानि वहन की गई।

सा.क्षे.उ. के अन्य प्रमुख मानदंड तालिका 2.19 में दिये गए हैं।

⁸ ₹ 17,410

⁹ ₹ 29,500

¹⁰ ₹ 29,500

¹¹ ₹ 28,750

तालिका 2.1.9: राज्य सा.क्षे.उ. के प्रमुख मानदंड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
इक्विटी	-8,263.37	-9,614.56	-10,964.73	-13,043.99	-15,873.47
निवेश	26,995.92	30,824.73	30,871.36	30,537.37	30,433.81
कर, ब्याज एवं लाभांश से पहले निवल लाभ	965.65	1,167.13	2,636.33	1,796.98	1,489.39
कर एवं अधिमान लाभांश के बाद निवल लाभ	-1,775.79	-2,034.72	-942.44	-2,049.74	-2,867.88
निवेश पर प्रतिफल ¹²	0.04	0.04	0.09	0.06	0.05
पूंजी पर प्रतिफल ¹³	मापन योग्य नहीं है क्योंकि सभी वर्ष की इक्विटी नकारात्मक है।				
ऋण	16,554.03	18,776.68	18,809.72	17,789.86	17,621.11
टर्नओवर ¹⁴	8,465.57	8,415.09	8,210.02	8,597.77	7,718.33
ऋण/टर्नओवर अनुपात	1.96:1	2.23:1	2.29:1	2.07:1	2.28:1
ब्याज भुगतान	2,478.64	2,801.25	3,243.56	3,537.25	4,010.34
संचित लाभ (घाटा)	(16,907.61)	(19,211.44)	(20,561.61)	(22,642.63)	(25,470.56)

स्त्रोत: सा.क्षे.उ. के अद्यतन अंतिम वार्षिक लेखों के अनुसार

अपने अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार, 10 सा.क्षे.उ. ने ₹ 967.60 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया और एक सा.क्षे.उ. अर्थात् दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने ₹ 0.50 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष नौ सा.क्षे.उ. ने ₹ 959.11 करोड़ का लाभ अर्जित करने के बाद भी कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

2.1.13 लेखा अभ्युक्तियाँ

चौदह कार्यशील कंपनियों ने अक्टूबर 2016 से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान 19 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को भेजे। इनमें से 14 कंपनियों के 15 लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए और चार लेखे नॉन रिव्यू सर्टिफिकेट जारी करने के लिए चुने गए। इनमें से 12 लेखों (दस¹⁵ सा.क्षे.उ.) को अंतिम रूप दिया गया और शेष सात¹⁶ लेखों को 30 सितम्बर 2017 को अंतिम रूप दिया जाना था। दस कंपनियों के दस लेखों को, जो 30 सितम्बर 2016 तक प्रक्रियाधीन थे, उक्त अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया गया।

¹² निवेश पर प्रतिफल= लाभांश, कर एवं ब्याज से पहले लाभ/ निवेश जहाँ निवेश= प्रदत्त पूंजी+ निर्बाध आरक्षित निधियाँ+ दीर्घावधि ऋण।

¹³ इक्विटी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद निवल लाभ)/ इक्विटी जहाँ इक्विटी =प्रदत्त पूंजी +निर्बाध आरक्षित निधियाँ- संचित घाटा- आस्थागत राजस्व व्यय

¹⁴ 30 सितम्बर 2017 को कार्यशील सा.क्षे.उ. के अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार टर्नओवर

¹⁵ डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल, डीएससीएससी, डीपीसीएल, डीएसआईआईडीसी, डीएसआईआईडीसी मेंटनेंस सर्विसेज लि., दिल्ली क्रिएटिव आर्टस् लिमिटेड डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड वर्ष 2015-16 हेतु और डीएसआईआईडीसी मेंटनेंस सर्विसेज लिमिटेड और डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड वर्ष 2016-17 हेतु।

¹⁶ जीएसडीएल, एसआरडीसी, डीटीडीडीसी, डीएसआईआईडीसी, डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड और दिल्ली क्रिएटिव आर्टस् लिमिटेड वर्ष 2016-17 हेतु और डीटीआईडीसी (2014-15)।

नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा से इंगित होता है कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में बहुत सुधार आवश्यक है। लेखापरीक्षित लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की अभ्युक्तियों का कुल मूल्य तालिका 2.1.10 में दिया गया है।

तालिका 2.1.10: कार्यशील कंपनियों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17 ¹⁷	
		लेखों की सं.	धनराशि	लेखों की सं.	धनराशि	लेखों की सं.	धनराशि
1.	लाभ में कमी	-	-	6	359.42	6	716.74
2.	लाभ में वृद्धि	2	0.25	3	339.47	2	433.77
3.	घाटे में कमी	-	-	-	-	2	230.00
4.	घाटे में वृद्धि	1	2.59	-	-	1	91.04
5.	महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट न होना	1	3.15	1	57.43	4	153.54
6.	श्रेणी विभाजन में त्रुटि	1	3.54	2	31.36	-	-

- वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों¹⁸ हेतु बिना शर्त प्रमाणपत्र, बारह लेखों¹⁹ के लिए सशर्त प्रमाणपत्र और एक लेखे²⁰ को प्रतिकूल (अर्थात् लेखों में सत्य व निष्पक्ष स्थिति नहीं दर्शाई गई है) प्रमाणपत्र जारी किए।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अर्हता प्रदान करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 हेतु डीपीसीएल द्वारा सूचित लाभ (₹ 81.91 करोड़) में ₹ 690.02 करोड़ की कमी हुई। नि.म.ले.प. द्वारा अर्हता प्रदान करने के परिणामस्वरूप इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2015-16 के लिए सूचित घाटा (₹ 77.45 करोड़) ₹ 91.04 करोड़ तक बढ़ गया।
- कंपनियों द्वारा लेखांकन मानदण्डों की अनुपालना में कमी रही। छः लेखों में अनुपालना न होने के 15 मामले थे।

¹⁷ डीटीआईडीसी की लेखा अभ्युक्तियों का प्रभाव वर्ष 2013-14 के लिए है।

¹⁸ डीएससीएससी, डीसीएल, डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड (2015-16) और डीटीटीडीसी, जीएसडीएल, एसआरडीसी (2016-17)

¹⁹ डीपीसीएल, डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल, डीएसआईआईडीसी, डीएसआईआईडीसी मॅटनेस सर्विसेज लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड (2015-16) और डीएसआईआईडीसी मॅटनेस सर्विसेज लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्टस् लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड और डीएसआईआईडीसी (2016-17)।

²⁰ डीटीआईडीसी (2013-14)

इसी प्रकार, दो सांविधिक निकायों ने लेखापरीक्षा के लिए अपने दो लेखे अक्टूबर 2016 से सितंबर 2017 की अवधि में भेजे। इनमें से दिल्ली परिवहन निगम का एक लेखा नि.म.ले.प. द्वारा एकल लेखापरीक्षा के संदर्भ में था, जो समाप्त की गई और वर्ष 2015-16 हेतु एस.ए.आर. जारी किया गया। शेष वर्ष 2016-17 हेतु दिल्ली वित्तीय निगम के एक लेखे को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया जो 30 सितंबर 2017 तक प्रक्रियाधीन थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा और नि.म.ले.प. की एकल/पूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से यह संकेत मिलता है कि लेखों के अनुरक्षण में सुधार आवश्यक है। सांविधिक लेखापरीक्षकों व नि.म.ले.प. द्वारा दी गई पिछले तीन वर्षों की अभ्युक्तियों की कुल धनराशि का विवरण तालिका 2.1.11 में दिया गया है।

तालिका 2.1.11: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17 ²¹	
		लेखों की सं.	धनराशि	लेखों की सं.	धनराशि	लेखों की सं.	धनराशि
1.	लाभ में कमी	-	-	1	0.16	1	3.79
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	घाटे में कमी	1	24.56	-	-	1	15.10
4.	घाटे में वृद्धि	1	2,695.74	1	1,978.50	1	2,389.34
5.	महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट न होना	-	-	1	964.04	2	127.94
6.	श्रेणी विभाजन में त्रुटि	-	-	-	-	1	25.24

2.1.14 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के प्रतिवेदन हेतु संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को एक निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) और आठ अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ (एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित) छः सप्ताह के भीतर जवाब देने के अनुरोध के साथ जारी किये गए। यद्यपि निष्पादन लेखापरीक्षा और छः अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ के संबंध में राज्य सरकार के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2018)।

2.1.15 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) यह निर्धारित करता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद, विभाग लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे और इसपर सरकार द्वारा

²¹ डीटीसी एवं डीएफसी के लेखा अभ्युक्तियों का प्रभाव वर्ष 2015-16 के लिए है।

कार्रवाई नोट (एटीएन) प्रतिवेदन की प्रस्तुति के चार माह के भीतर सीमिति के विचार हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यद्यपि 30 सितंबर 2017 तक 20 प्रतिशत निष्पादन लेखापरीक्षाओं और 33 प्रतिशत लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर कार्रवाई नोट प्राप्त नहीं हुए थे, जैसा कि तालिका 2.1.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.12: 30 सितंबर 2017 तक प्राप्त नहीं हुए कार्रवाई नोट

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तिथि	समीक्षा/पैराग्राफों की संख्या			
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत		लंबित एटीएन	
		नि.ले.प.	पैराग्राफ	नि.ले.प.	पैराग्राफ
2012	02.04.2013	1	3	1	शून्य
2013	01.08.2014 (संसद में)	1	7	शून्य	शून्य
2014	30.06.2015	1	2	शून्य	2
2015	13.06.2016	1	6	शून्य	3
2016	10.03.2017	1	6	शून्य	3
कुल		5	24	1	8

2.1.16 सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में प्रस्तुत किए गए नि.ले.प. और लेखापरीक्षा पैराग्राफ और इन पर कोगू द्वारा चर्चा की 30 सितंबर 2017 की स्थिति तालिका 2.1.13 में दी गई है:

तालिका 2.1.13: 30 सितंबर 2017 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत समीक्षा/पैरे और इनपर चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	समीक्षा/पैराग्राफों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत		चर्चा किए गए	
	नि.ले.प.	पैराग्राफ	नि.ले.प.	पैराग्राफ
2012	1	3	शून्य	शून्य
2013	1	7	1	3
2014	1	2	1	शून्य
2015	1	6	शून्य	शून्य
2016	1	6	शून्य	शून्य
कुल	5	24	2	3

2.1.17 सा.क्षे.उ. का विनिवेश, पुनर्संरगठन और निजीकरण

राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान किसी भी राज्य सा.क्षे.उ. में विनिवेश, पुनर्संरगठन व निजीकरण की गतिवधि नहीं की।

2.1.18 अध्याय का क्षेत्र

इस अध्याय में आठ पैराग्राफ (दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित) और 'दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के कार्य' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा है जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 102.38 करोड़ का है।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

2.2 दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली

दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की राज्य द्वारा शासित कंपनी है जो एक प्रोत्साहक एवं अभिकर्मक के रूप में कार्य करते हुए आर्थिक विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर और संस्थागत क्रेडिट के संगठन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/सफाई कर्मचारियों और अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों के सर्वतोमुखी विकास और आर्थिक उन्नयन हेतु आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्त पोषण, प्रोत्साहन और सहायता करती है। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्राप्तियों का सार निम्नवत है:

मुख्य बिन्दु

कंपनी ने लक्षित समूहों की पहचान के लिए न तो कोई सर्वेक्षण किया और न ही अभीष्ट लाभार्थियों का कोई डाटाबेस बनाया।

(पैराग्राफ 2.2.2)

कंपनी ने नियमित रूप से अपने वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया। वर्ष 2004-05 तथा उसके बाद के वर्षों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

(पैराग्राफ 2.2.3.1)

ऋण के संवितरण का प्रतिशत जो 2012-13 में कुल उपलब्ध निधियों का 45.41 प्रतिशत था, कम होकर 2016-17 में 12.90 प्रतिशत रह गया।

(पैराग्राफ 2.2.3.2)

कंपनी की ऋण गतिविधियों के भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति में काफी कमी रही। यह प्राप्ति 2012-17 की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक से 61 प्रतिशत तक रही।

(पैराग्राफ 2.2.4.1)

वित्तीय सहायता को बढ़ाने में कमियाँ थीं और ऋणों के संवितरण में काफी विलंब हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.4.4)

लाभार्थियों से वसूली के बाद की कार्रवाई की प्रणाली संतोषप्रद नहीं थी क्योंकि वर्ष 2016-17 के दौरान की गई कुल वसूली मात्र 11 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2017 तक अधिक लंबितता वाले मामलों के संबंध में ₹ 23.77 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई।

(पैराग्राफ 2.2.5)

5,192 मामलों में से अधिकतम 3,533 मामले जिन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे, वसूली प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई।

(पैराग्राफ 2.2.5.2)

शिकायत निवारण प्रणाली अपर्याप्त थी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर और अप्रभावी थी।

(पैराग्राफ 2.2.7)

2.2.1 प्रस्तावना

दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को 1983 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित किया गया और इसका नाम बदलकर दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) कर दिया गया। इस कंपनी की स्थापना उन अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यक तथा विकलांग वर्ग के सदस्यों जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, संस्थागत क्रेडिट हेतु वित्त प्रदान करके व संग्रह करके, आर्थिक गतिविधियों को सरल तथा उन्नत बनाकर, युवाओं को विभिन्न आय उत्पत्ति तथा रोजगार परक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देकर तथा उनके सर्वतोमुखी विकास व आर्थिक उत्थान के लिए प्रोत्साहक तथा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके सहायता प्रदान करने हेतु किया गया।

इस कंपनी को राष्ट्रीय शीर्ष निगमों अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) और राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) द्वारा वित्तपोषित योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह कंपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु शीर्ष निगमों से निधियां प्राप्त करती है जिस पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाती है। कंपनी अपने लाभार्थियों से छः प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित करती है। इससे कंपनी की ऋण गतिविधियों पर तीन प्रतिशत की सीमा तक आय सृजित करती है। इसके अतिरिक्त कंपनी बैंकों में डिपोजिट निधियों पर ब्याज से और अपने कार्यालय भवन में खाली स्थानों को किराए पर देकर भी आय अर्जित करती है।

2.2.1.1 संगठनात्मक ढाँचा

कंपनी का प्रबंध 12 निदेशकों के निदेशक मंडल (बीओडी) से गठित किया जाता है जिसका अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) कंपनी का मुख्य कार्यपालक होता है। सीएमडी के अतिरिक्त बीओडी में रा.रा.क्षे.दि.स. और भारत सरकार से दो नामांकित सदस्य, एनएचएफडीसी, एनएमडीएफसी और एनबीसीएफडीसी से प्रत्येक से एक सदस्य और लक्षित लाभार्थियों के समूहों में से चार सदस्य होते हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री अध्यक्ष होता है और प्रधान सचिव/सचिव (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक) और विशेष सचिव (वित्त विभाग) रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2.2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करना थे कि:

- (i) कंपनी ने निर्धारित वित्तीय सहायता योजनाओं की योजना, निर्माण व कार्यान्वयन प्रभावी, मितव्ययी तथा कुशल रूप से किया था और
- (ii) लक्षित लाभार्थियों को प्रदान किए गए क्रेडिट के चयन, निर्गमन और वसूली के लिए प्रभावी पर्यवेक्षण व निगरानी प्रणाली थी।

2.2.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि

यह निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 के दौरान कंपनी की अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक पाँच वर्ष की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए आयोजित की गई। इस अवधि के दौरान कंपनी ने शिक्षा ऋण योजना, परिवहन ऋण, दिल्ली स्वरोजगार योजना, संयुक्त ऋण और बड़ा ऋण योजना के अंतर्गत क्रमशः 89, 72, 173, 501 और दो ऋण संवितरित किए जिनमें से लेखापरीक्षा के लिए क्रमशः 23, 22, 25, 60 और दो ऋण मामले चुने गए, जिससे इस अवधि के दौरान संवितरित कुल ऋणों के 16 प्रतिशत मामले शामिल हुए। कंपनी के मुख्यालय और तीन जोनल कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गई।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा कार्यविधि, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंड की चर्चा हेतु कंपनी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन किया गया (मई 2017) था। लेखापरीक्षा प्राप्तियों से प्रबंधन को अवगत कराया गया (सितंबर 2017) था और एक समापन सम्मेलन भी किया गया (सितंबर 2017) था जिसमें कार्यकारी निदेशक के साथ कंपनी के अधिकारियों ने भाग लिया। दिनांक 30 जनवरी 2018 के कंपनी के जवाबों को इस प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित से प्राप्त मानदंडों पर परखा गया:

- (i) कंपनी के बोर्ड की बैठकों का एजेंडा और कार्यवृत्त और शक्तियों का प्रत्यायोजन;
- (ii) राज्य/केंद्र सरकार/राष्ट्रीय शीर्ष निगमों द्वारा निर्धारित नीति/नीतिगत ढांचा/मानदंड/दिशानिर्देश;
- (iii) ऋणों की संस्वीकृति, संवितरण, वसूली और निगरानी हेतु कंपनी की प्रक्रियाएं; और
- (iv) कंपनी द्वारा जारी कार्यालय अभिलेख/आदेश/परिपत्र/अनुदेश।

लेखापरीक्षा प्राप्तियां

2.2.2 अपर्याप्त योजना

योजना में अपर्याप्तताएं थीं। कंपनी ने अपने उद्देश्यों की सूचना देते हुए प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार किया और उन्हें प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किया परन्तु उनको कार्यान्वित नहीं किया जा सका। प्रस्तावित एमओयू उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रशासनिक मंत्रालय से वापिस प्राप्त किए गए। परिणामस्वरूप एमओयू को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

कंपनी ने अपनी वार्षिक योजनाओं के साथ-साथ पंचवर्षीय योजना (2012-17) भी तैयार की यद्यपि ऋण गतिविधियों का लक्ष्य प्राप्त करने में 2012-17 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 38.80 और 99.04 प्रतिशत के बीच की रेंज में अत्यधिक कमियां थीं। यह दर्शाता है कि कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन कमजोर था जिससे लक्षित लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रहे जैसाकि निष्पादन लेखापरीक्षा में चर्चा की गई।

इसके अतिरिक्त कंपनी को रा.रा.क्षे.दि.स. में रह रहे लक्षित समूहों की जनसंख्या की रूपरेखा तैयार करने तथा कथित योजनाओं के अंतर्गत सहायता संवितरित करने तथा कथित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए

कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए प्रगामी लक्ष्यों के नियत करने की आवश्यकता थी। लाभार्थियों की पहचान इसलिए महत्वपूर्ण थी कि विकास योजनाओं ने समाज की गिरती हुई स्थिति को लक्षित किया जिसमें उनकी जागरूकता की कमी के कारण अपवर्जन का जोखिम बहुत अधिक था। इसे उचित सर्वेक्षण के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व/अल्पसंख्यक/विकलांग लोगों के विश्वसनीय डाटाबेस के अनुरक्षण हेतु किया गया जो वित्तीय सहायता की योजना तथा विस्तार के लिए आधार प्रदान करेगा तथा समस्त लक्षित जनसंख्या को चरणबद्ध तरीके से कवर करेगा। कंपनी ने जबकि लक्षित समूहों की पहचान के लिए तथा व्यवहार्य व्यवसायों व व्यापारों जिनको ऋण दिया जा सकता है, की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया। इसने अभीष्ट लाभार्थियों का कोई डाटाबेस भी नहीं रखा।

कंपनी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि लक्ष्यों को मुख्यतः 2013 और 2015 के बीच चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन, एक वर्ष से अधिक संस्वीकृति प्राधिकारी की गैर-उपलब्धता, दिल्ली स्वरोजगार योजना में संशोधन करने के लिए जाने वाले समय के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसाकि कंपनी को इन मामलों का प्रबंधन करने के लिए पहले ही अधिक सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी लेखापरीक्षा में सम्मिलित सभी पांच वर्षों में ऋणों के संवितरण के अपने प्रत्यक्ष लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

2.2.3 वित्तीय प्रबंधन

2.2.3.1 वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

कंपनी ने केवल वर्ष 2003-04 तक अपने वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दिया है। 2004-05 तथा इसके बाद की अवधि के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अभाव में वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभाविता और प्राप्ति, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं का जिसमें कथित प्रयोजन हेतु निधियों का निवेश व उपयोग भी शामिल है, लेखांकित नहीं किया जा सका। कंपनी के पास 31 मार्च 2011 को अलेखापरीक्षित लेखों के अनुसार ₹ 5.20 करोड़ की अचल परिसंपत्ति थी लेकिन इसने अचल संपत्ति पंजिका का रखरखाव नहीं किया और न ही इसकी परिसंपत्तियों का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन इसके आरंभ से किया गया था।

कंपनी ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा कि योग्य अधिकारियों की गैर-उपलब्धता के कारण लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2015-16 के लेखों को अब अंतिम रूप दे दिया गया है

और कंपनी अधिनियम के अनुसार स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार किया जा रहा है तथा प्रत्यक्ष सत्यापन जल्दी ही किया जाएगा। प्रबंधन के उत्तर को प्रमाणों के समर्थन के किसी अभिलेख के अभाव में सत्यापित नहीं किया जा सका। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लेखों को 30 जनवरी 2018 तक सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है।

2.2.3.2 प्राप्तियां तथा संवितरण

कंपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ऋण प्रदान करती है जैसाकि नीचे बताया गया है:

संयुक्त ऋण योजना: इस योजना के अंतर्गत ₹ 50,000 से केवल ₹ दो लाख तक की रेंज में ऋण सहायता अनुसूचित जातियों के सदस्यों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, सफाई कर्मचारियों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए संस्वीकृत किया जाता है तथा दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी) द्वारा अनुमोदित विभिन्न व्यापारों जैसे सब्जियां/फल/फूलों की दुकान, बेकरी उत्पाद, किराना/जनरल स्टोर, डेयरी उत्पादों/फोटोस्टेट/साइबर कैफे, दवाई की दुकान, पान की दुकान, सिलाई की दुकान, आटा चक्की, लौंड्री इत्यादि में किसी आय उत्पन्न गतिविधि के लिए वितरित किया जाता है।

परिवहन ऋण योजना: इस योजना के अंतर्गत कंपनी अनुमोदित वाणिज्यिक वाहनों के लिए ऋण प्रदान करती है। वितरित ऋण की धनराशि वाहन की लागत की राशि पर निर्भर करती है। इस लक्षित श्रेणी में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, सफाई कर्मचारियों तथा शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य आते हैं।

शिक्षा ऋण योजना: इस योजना के अंतर्गत कंपनी लक्षित समूहों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान करती है। कंपनी भारत में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को अधिकतम ₹ 7.50 लाख तथा भारत से बाहर के लिए ₹ 15.00 लाख तक के ऋण अग्रिम प्रदान करती है।

बड़ी ऋण योजना: इस श्रेणी के अंतर्गत लघु उद्योग (₹ पांच लाख तक की लागत की परियोजना) में आर्थिक गतिविधियों की स्थापना हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत ऋण कृषि तथा संबंध क्षेत्र, पारंपरिक व्यवसायों तथा लघु व सूक्ष्म उद्योगों में प्रदान किया जाता है।

दिल्ली स्वरोजगार योजना: इस योजना के अंतर्गत ₹ पाँच लाख तक का ऋण अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, सफाई कर्मचारियों तथा

शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए संस्वीकृत किया जाता है तथा एम.सी.डी. द्वारा अनुमोदित विभिन्न व्यापारों में किसी आय उत्पन्न गतिविधि के लिए संवितरित किया जाता है। यह योजना कंपनी द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ₹ 50 करोड़ के संग्रह के प्रति प्राप्त ब्याज आय से चलाई जाती है।

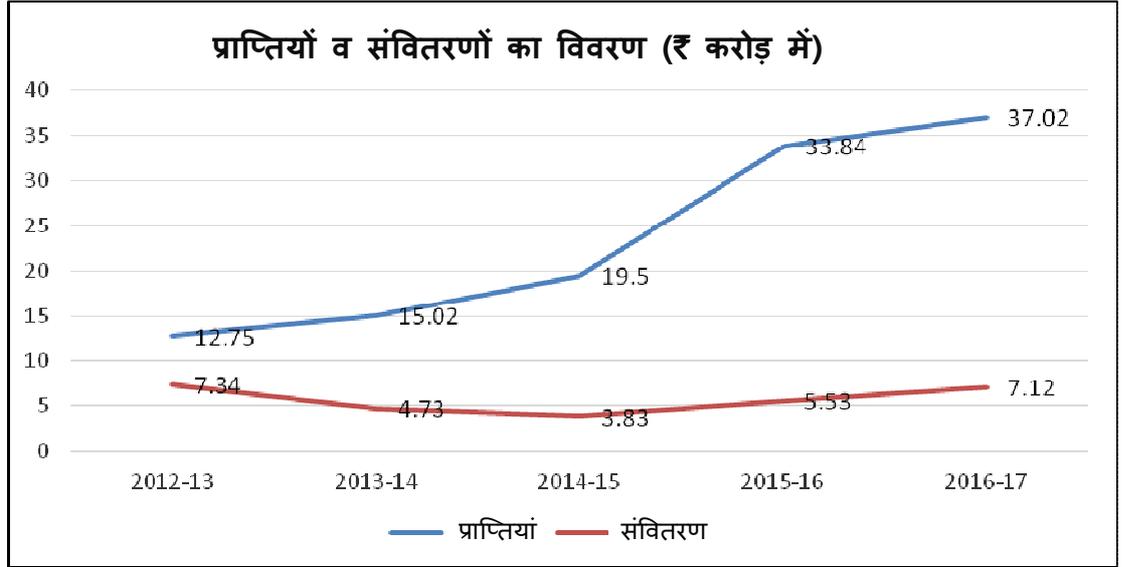
प्राप्तियों की वर्षवार स्थिति जिसमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शीर्ष निगमों²² से प्राप्त निधियां तथा ऋण वसूलियां और कंपनी के संवितरण शामिल हैं, तालिका 2.2.1 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.2.1: प्राप्तियों व संवितरणों का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्राप्तियां	आरंभिक शेष	161.31	541.62	1029.04	1567.3	2831.25
	संयुक्त ऋण योजना	209.75	8.50	0.00	1080.00	110.00
	परिवहन ऋण योजना	323.30	0.00	0.00	0.00	54.36
	शिक्षा ऋण योजना	0.00	9.25	16.53	4.65	1.65
	बड़ा ऋण योजना	0.00	0.00	0.00	4.00	3.90
	दिल्ली स्वरोजगार योजना	200.96	455.00	450.00	388.56	397.25
	वसूलियां	379.89	487.48	454.24	339.65	303.37
	कुल प्राप्तियां	1275.21	1501.85	1949.81	3384.16	3701.78
संवितरण	संयुक्त ऋण योजना	173.70	67.70	20.70	45.55	238.92
	परिवहन ऋण योजना	221.98	3.48	0.00	0.00	15.73
	शिक्षा ऋण योजना	10.87	40.45	29.74	36.93	18.69
	बड़ा ऋण योजना	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	दिल्ली स्वरोजगार योजना	0.00	4.50	41.10	173.45	165.02
	पुनर्भुगतान/शीर्ष को वापसी	327.04	356.68	290.97	292.98	273.74
	कुल संवितरण	733.59	472.81	382.51	552.91	712.1
	अंत शेष	541.62	1029.04	1567.3	2831.25	2989.68
	उपलब्ध निधियों का संवितरण %	57.52	31.48	19.62	16.34	19.24

²² एनएसएफडीसी, एनएसटीएफडीसी, एनबीसीएफडीसी, एनएमडीएफडीसी, एनएसकेएफडीसी तथा एनएचएफडीसी ।



उपरोक्त तालिका के साथ रेखाचित्र को पढ़ने से यह देखा जा सका कि:

(क) ऋणों के संवितरण के लिए पर्याप्त निधियां थीं और वे वर्ष प्रतिवर्ष संचित हो रही थीं। 2012-17 के दौरान सभी शीर्ष निगमों/रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त कुल निधि केवल ₹ 37.18 करोड़ थी, जिसपर कंपनी इस अवधि में ₹ 13.13 करोड़ का ही संवितरण कर सकी। वर्ष के अंत में अधिशेष 2012-13 में ₹ 5.42 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 29.90 करोड़ हो गया। ऋण संवितरण का प्रतिशत 2012-13 में 45.41 प्रतिशत था, जो 2016-17 में 12.90 प्रतिशत हो गया।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि रियायती ऋणों के संवितरण हेतु योग्य लाभार्थी ढूंढने के बजाय कंपनी ने अधिशेष निधियों को बैंकों में निवेश कर दिया और ब्याज अर्जित किया। कंपनी ने बैंकों में जमा निधियों पर ₹ 35.53 करोड़ ब्याज के रूप में अर्जित किया जो इसकी कुल आय का 91 प्रतिशत था।

(ख) 2012-17 के दौरान 'परिवहन ऋण' की योजना के अंतर्गत ₹ 3.78 करोड़ प्राप्त किया गया, जिसमें से ₹ 1.36 करोड़ का उपयोग नहीं हुआ। 2014-16 के दौरान कोई संवितरण नहीं किया गया।

(ग) 2012-17 की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा दिल्ली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ₹ 18.92 करोड़ प्राप्त किया गया जिसमें से मात्र ₹ 3.84 करोड़ का संवितरण किया जा सका।

(घ) 2012-17 के दौरान कंपनी द्वारा संयुक्त ऋण योजनाओं के अंतर्गत ₹ 14.08 करोड़ प्राप्त किया गया, जिसमें से मात्र ₹ 5.46 करोड़ का संवितरण किया जा सका।

लाभार्थियों को ऋणों के उल्लेखनीय रूप से कम संवितरण के कारण लक्षित लाभार्थियों का डाटाबेस बनाने के लिए उनकी रूपरेखा को तैयार न करना, पर्याप्त जागरूकता कार्यक्रम की कमी, आय मानदंड का गैर परिवर्तन जो रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियत न्यूनतम वेतन की अपेक्षा से भी कम है, समयबद्ध ढंग से लक्षित लाभार्थी समूह को शामिल करने हेतु हो सकते हैं।

प्रबंधन ने कहा कि ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें बोझिल थी तथा निदेशक मंडल ने उत्तम संभव सुधारक उपायों के सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि संवितरण के लिए उपलब्ध निधियों के संवितरण की प्रतिशतता 2012-13 में 45.41 प्रतिशत से तेजी से कम होकर 2016-17 में मात्र 12.90 प्रतिशत रह गई थी जो लेखापरीक्षा विचारधारा का समर्थन करती है। यहाँ तक कि यदि प्रबंधन की बोझिल प्रक्रियागत मामलों की विचारधारा स्वीकार की जाए तब भी यह लाभार्थियों की रूपरेखा तैयार न करने तथा इसकी योजनाओं की जागरूकता की कमी के कारण लक्षित जनसंख्या तक पहुँचने में समर्थ नहीं हो सका है।

2.2.3.3 निधि का अवरोधन और अनुवर्ती ब्याज की हानि

भारत सरकार (भा.स.) के सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय ने गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अ.जा. हेतु आर्थिक विकास की पूर्ण वित्तपोषित परिवार केंद्रित योजनाओं को आरंभ किया (1986-87)। इस योजना के अनुसार भा.स. से प्राप्त निधि में से कंपनी को अ.जा. लाभार्थी को दिए जाने वाले ऋण के 50 प्रतिशत की सीमा तक या ₹ 10,000, जो भी कम हो, गैर-वापसी रियायत के रूप में प्रदान करना था। अ.जा. अभ्यर्थियों को विभिन्न रोजगार-केंद्रित व्यवसायों के अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिया जाना था। इस योजना के अंतर्गत कंपनी को 1997-98 से 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 9.68 करोड़ की निधियाँ प्राप्त हुईं, जबकि प्रशिक्षण और रियायत भुगतान पर ₹ 18.05 करोड़ धनराशि व्यय की गई थी। जिससे 31 मार्च 2017 तक ₹ 8.37 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। अतिरिक्त व्यय की पूर्ति कंपनी की अधिशेष निधियों पर अर्जित ब्याज से की गई। अधिकांश व्यय 2001-05 की अवधि के दौरान किया गया जब कंपनी को भा.स. से ₹ 3.68 करोड़ की निधियाँ प्राप्त हुईं जबकि इसने कंपनी की निधियों का उपयोग करने के लिए ₹ 13.39 करोड़ व्यय किया जिसमें अतिरिक्त व्यय के लिए बोर्ड की पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की गई। कंपनी ने अतिरिक्त व्यय की वापसी की मांग भी नहीं की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 को छोड़कर कंपनी को 2007-08 के बाद भा.स. से निधि प्राप्त नहीं

हुई, जबकि योजना के अंतर्गत व्यय अब भी जारी है। निधियां न प्राप्त होने का कारण कंपनी के लेखापरीक्षित लेखों और उपयोगिता प्रमाणपत्र को प्रस्तुत न करना बताया गया, जैसा कि इस निष्पादन लेखापरीक्षा के पैराग्राफ 2.2.3 में टिप्पणी थी। भा.स. से निधि न प्राप्त होना और अपने संसाधनों से व्यय करने के फलस्वरूप 2005-06 से 2016-17 के दौरान ₹ 8.37 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर ₹ 9.10 करोड़ के ब्याज की आय की हानि हुई। कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि भा.स. ने लेखों को अंतिम रूप देने तथा लेखों की सांविधिक लेखापरीक्षा में विलंब के कारण निधियां प्रदान नहीं की।

2.2.3.4 अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण ब्याज की हानि

कंपनी को वर्ष के आरंभ में शीर्ष निगमों से विभिन्न योजनाओं हेतु निधियों का वार्षिक आवंटन होता है, जिसके बाद निधियाँ संस्वीकृत और जारी की जाती हैं। कंपनी द्वारा कल्याण योजनाओं के खराब कार्यान्वयन के कारण अवितरित निधि संचित हो गई जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। हालांकि कंपनी के पास अधिशेष निधियों के उपयोग पर कोई निवेश नीति नहीं है और इसके फलस्वरूप बैंक जमा की अवधि का विस्तार सहित अन्य निवेश संबंधी निर्णयों में विलंब हुआ। अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब को तालिका 2.2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.2.2: निधियों के निवेश में विलंब के विवरण

अधिशेष निधि (₹ करोड़ में)		निवेश की तिथि	दिनों का विलंब	लागू ब्याज दर (%)	हानि (₹ लाख में)
राशि	निम्न तिथि को उपलब्ध				
50	19.10.2012	02.11.2012	14	9	17.26
20	23.12.2012	02.01.2013	9	9.25	4.56
7	23.12.2012	24.01.2013	32	9	5.52
15	26.06.2013	03.07.2013	7	9.10	3.69
45	02.11.2013	07.11.2013	5	9.10	5.6
5	02.11.2013	07.11.2013	5	9.25	0.63
7	11.04.2016	27.04.2016	16	7.5	2.30
5	11.04.2016	27.04.2016	16	7.55	1.65
5	11.04.2016	27.04.2016	16	7.60	1.66
10	09.11.2016	06.01.2017	58	6.9	10.96
10	09.11.2016	06.01.2017	58	7	11.12
कुल					64.95

कंपनी ने अधिशेष निधियों के निवेश के समय निर्णय प्रक्रिया में विलंब के कारण ₹ 64.95 लाख के ब्याज की हानि वहन की। कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा विलंब के लिए प्रशासनिक व प्रक्रियागत कारणों को उत्तरदायी ठहराया और सूचित किया कि प्रत्येक निवेश की परिपक्वता से कम से कम 30 दिन पहले निवेश प्रस्तावों को पेश करने का निर्णय लिया गया है।

2.2.3.5 किराया समझौता के विलंबित कार्यान्वयन के कारण ₹ 2.15 करोड़ की वसूली न होना

कंपनी ने जुलाई 2007 में कल्याण भवन, रायगड़ पुरा, नई दिल्ली में 227.05 व.मी. का परिसर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग (डीसीएसके) को किराया समझौता किए बिना आवंटित किया। कंपनी ने अप्रैल 2009 तक इस परिसर के किराये के निर्धारण का मामला लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के साथ आगे नहीं बढ़ाया। किराए का निर्धारण लो.नि.वि. की किराया निर्धारण समिति द्वारा जून 2015 में किया गया तथा किराया समझौते पर 23 मार्च 2017 में कंपनी और डीसीएसके के बीच हस्ताक्षर हुआ, जब इस स्थान पर कब्जे के दस वर्ष बीत गए थे। ₹ 2.29 लाख प्रतिमाह के किराए के आधार पर कुल किराया वसूली ₹ 3.53 करोड़ थी जिसमें से कंपनी ने मार्च 2017 में ₹ 1.38 करोड़ वसूल किया। किराया निर्धारण और वसूली में अनावश्यक विलंब के फलस्वरूप मार्च 2017 तक ₹ 1.69 करोड़ की ब्याज आय की हानि हुई। कंपनी ने कहा (जनवरी 2018) कि शेष राशि की वसूली के लिए नियमित अनुवर्तन किया जा रहा है।

2.2.3.6 स्टाफ कारों के क्रय/रखरखाव पर ₹ 98.66 लाख का अनावश्यक व्यय

बोर्ड ने अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए अधिकारियों समेत अधिकारियों को कार प्रदान करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई। कंपनी का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक और एकमात्र कार्यकारी निदेशक कार्यालयी कार के हकदार होंगे। 31 मार्च 2017 को अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक कार्यालयी कारों का उपयोग कर रहे थे। यद्यपि कंपनी के पास 31 मार्च 2017 को 10 स्टाफ कारों का जत्था था। इस प्रकार हकदारी के अनुसार कंपनी के पास आवश्यकता से अधिक आठ कारें थीं। यह भी पाया गया कि अतिरिक्त आठ कारों के प्रति कंपनी के पास निरीक्षण दलों तक जाने और किसी जागरूकता कार्यक्रम को करने के लिए कोई विशेष वाहन नहीं था। इन आठ कारों के लागत मूल्य और उनके रखरखाव का व्यय ₹ 98.66 लाख था। इसके अतिरिक्त फलदायी प्रयोग हेतु सामान्य पूल की कारों के प्रयोग की अनुमति नहीं है क्योंकि लक्षित समूहों की वित्तीय सहायता योजनाओं का क्रियान्वयन खराब था और कंपनी को शीर्ष निगम से प्राप्त निधियों का अधिकांश हिस्सा बैंकों में स्थायी जमा के रूप में रखा गया था।

इसके अतिरिक्त 29 जुलाई 2015 को नई कार के क्रय के समय यह दर्ज किया गया कि कार का क्रय वसूलियों और जागरूकता शिविर के लिए प्रयोग होने वाले एक ग्रामीण परिवहन वाहन (आरटीवी) के क्षतिग्रस्त होने के कारण किया जा रहा था जबकि कार को सीएमडी के लिए नियोजित किया गया था।

इस प्रकार कंपनी की योजनाओं की जानकारी फैलाने के प्रयोजन के लिए आरटीवी के स्थान पर स्टाफ कार का क्रय अनुचित था। अप्रैल 2016 में सीएमडी के लिए एक अन्य कार ₹ 6.88 लाख की लागत पर क्रय की गई जबकि कार 2015 में क्रय हो चुकी थी।

कंपनी ने कहा कि कारें निगम की आवश्यकता के अनुसार ही खरीदी गई हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के दो हकदार अधिकारियों के लिए केवल दो वाहन ही अपेक्षित हैं।

2.2.4 योजनाओं का कार्यान्वयन

जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली में अ.जा. और विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या क्रमशः 28.12 लाख और 2.35 लाख थी। अल्पसंख्यक जनसंख्या 21.72 लाख थी। विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाएं 10.78 लाख थीं। दिल्ली लेखों में 54 अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) दिल्ली की कुल जनसंख्या (1.67 करोड़) का लगभग 51 प्रतिशत है। केवल दिल्ली के तीन नगर निगमों में ही 64,000 सफाई कर्मचारी हैं। इस प्रकार लक्षित समूहों की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी थी जो कंपनी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न क्रेडिट योजनाओं के अंतर्गत लाई जा सकती थी। इन लक्षित समूहों को क्रेडिट प्रदान करने हेतु शीर्ष निगमों से पर्याप्त निधियां प्राप्त हुई थीं (तालिका 2.2.1 और 2.2.4 देखें)। यद्यपि, जैसा कि नीचे उल्लिखित है, कंपनी में इन क्रेडिट योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कोई शीघ्रता या चिंता नहीं देखी गई।

2.2.4.1 लक्ष्य व उपलब्धियां

वार्षिक आवंटनों के समय शीर्ष निगम राज्यवार और लाभार्थी श्रेणीवार भौतिक व वित्तीय लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं। एनएसएफडीसी के मामले में अ.जा. लाभार्थियों के लिए औसत ऋण धनराशि का लक्ष्य ₹ 0.45 लाख रखा गया। एनबीसीएफडीसी के मामले में पिछड़ा वर्ग लाभार्थियों को औसत ऋण धनराशि का लक्ष्य ₹ 0.45 लाख था। एनएचएफडीसी के मामले में विकलांग लाभार्थियों को औसत ऋण धनराशि का लक्ष्य ₹ 0.60 लाख रखा गया, जबकि एनएमएफडीसी के मामले में अल्पसंख्यक लाभार्थियों को औसत ऋण धनराशि का लक्ष्य ₹ 1.11 लाख रखा गया।

2012-17 के दौरान कंपनी के लक्ष्य व उपलब्धियां तालिका 2.2.3 में दिए गए हैं।

तालिका 2.2.3: लक्ष्यों व उपलब्धियों का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

मार्च में समाप्त वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि		उपलब्धि (%)	
	भौतिक (मामलों की संख्या)	वित्तीय (धनराशि)	भौतिक (मामलों की संख्या)	वित्तीय (धनराशि)	भौतिक (मामलों की संख्या)	वित्तीय (धनराशि)
अनुसूचित जातियों के लिए एनएसएफडीसी योजनाएं						
2013	701	277.46	207	368.88	30	133
2014	766	337.64	56	57.88	7	17
2015	833	375.99	16	15.90	2	4
2016	875	437.70	40	39.70	5	9
2017	*	615.55	140	219.34	ला.न.	36
कुल		2044.34	459	701.70		34
अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु एनबीसीएफडीसी योजनाएं						
2013	300	150	22	17.00	7	11.33
2014	250	150	12	3.40	5	2.27
2015	115	150	9	9.35	8	6.23
2016	430	200	12	1.90	3	0.95
2017	925	255.43	23	10.61	2	4.15
कुल	2020	905.43	78	42.26	4	4.67
विकलांगों के लिए एनएचएफडीसी योजनाएं						
2013	109	60.00	4	4.00	3	7
2014	127	70.00	2	4.75	2	7
2015	108	81.00	4	12.65	4	16
2016	141	105.00	5	8.89	4	8
2017	211	105.00	9	6.28	4	4
कुल	696	421	24	36.57	3	23
अल्पसंख्यक हेतु एनएमएफडीसी की योजनाएं						
2013	105	100	4	3.80	4	4
2014	105	100	6	6.50	6	6
2015	105	100	1	0.69	1	1
2016	67	100	7	12.58	10	13
2017	67	100	41	29.80	61	30
कुल	449	500	59	53.37	13	11

* आवंटन पत्र में भौतिक लक्ष्य का उल्लेख नहीं है।

यह पाया गया:

- (क) कि इस अवधि के दौरान एनएसएफडीसी के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या केवल दो से 30 प्रतिशत की श्रेणी में थी तथा केवल 34 प्रतिशत उपलब्ध निधियों का उपयोग किया गया;
- (ख) कि इस अवधि के दौरान एनबीसीएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या केवल दो से आठ प्रतिशत की श्रेणी में थी तथा केवल 4.67 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया;
- (ग) कि इस अवधि के दौरान एनएचएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या केवल दो से चार प्रतिशत की श्रेणी में थी तथा केवल 23 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया जा सका; और
- (घ) कि इस अवधि के दौरान एनएमडीएफसी के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या एक से 61 प्रतिशत की श्रेणी में थी तथा केवल 11 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया जा सका।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थियों को ऋण वितरण के लिए बिना किसी योजना या कार्यनीति के शीर्ष निगमों के ऊंचे लक्ष्य और अधिक निधि आवंटन को स्वीकार करना कंपनी के हाथों में एक नियमित लाभदायी साधन बन गया है जिससे वह निष्प्रयोजन निधियों पर ब्याज आय अर्जित कर अपने स्थापना व्यय की पूर्ति कर सके और जिन लक्षित समूहों के लाभ के लिए कंपनी की स्थापना हुई, उनके हित को दरकिनार कर अपनी आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध कर सके।

कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि इसने 2012-17 के दौरान लक्षित समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए परन्तु एक वर्ष से अधिक तक संस्वीकृत प्राधिकारी की गैर-उपलब्धता के कारण, दिल्ली स्वरोजगार योजना में किए जा रहे संशोधनों में लिया जाने वाला समय, आय मानदंड का गैर परिवर्तन जो यहां तक कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी की अपेक्षा कम है तथा 2013 व 2015 के बीच चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण यह लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसाकि यह केन्द्रीय स्तर संगठनों से उच्च लक्ष्यों तथा निधि आवंटनों की स्वीकृति की लेखापरीक्षा धारणा को संवितरण की योजना के बिना संबोधित करता है जिससे बैंकों में रखी अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज आय अर्जित की जा रही है। किसी भी योजना के न होने के परिणामस्वरूप ऋण गतिविधियों के लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई जो 2012-17 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 38.80 तथा 99.04 प्रतिशत के बीच की श्रेणी में थी।

2.2.4.2 शीर्ष निगमों से निधि आवंटन और उसका उपयोग

शीर्ष निगम वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिनके आधार पर कंपनी को प्रतिवर्ष निधियों का अवधारणात्मक आवंटन किया जाता है जिसके बाद कंपनी शीर्ष निगमों की संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों की संख्या और आवश्यक कुल निधि को दर्शाते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। तालिका 2.2.4 अ.जा. लाभार्थियों के लिए 2012-17 के दौरान एनएसएफडीसी द्वारा पिछड़े वर्ग हेतु एनबीसीएफडीसी द्वारा और विकलांग लाभार्थियों के लिए एनएचएफडीसी द्वारा समेकित निधि आवंटन, आहरित निधि और संवितरित ऋण को दर्शाती है।

**तालिका 2.2.4: 2012-17 के दौरान आवंटित, संस्वीकृत और आहरित
समेकित निधियों का विवरण**

(राशि ₹ लाख में)

शीर्ष निगम	शीर्ष द्वारा निधि आवंटन	कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव	शीर्ष नियमों द्वारा संस्वीकृत निधि	कंपनियों द्वारा लाभार्थियों के लिए आहरित धनराशि	संस्वीकृत निधियों के प्रति आहरित न की गई निधियां	
					धनराशि	(प्रतिशत में)
एनएसएफडीसी	2,338.37	2,225.50	2,044.34	795.16	1,249.18	61
एनबीसीएफडीसी	905.43	875.45	905.43	46.75	858.68	95
एनएचएफडीसी	421.00	414.50	421.00	49.46	371.54	88
कुल	3,664.80	3,515.45	3,370.77	891.37	2,479.40	74

तीनों शीर्ष निगमों ने 2012-17 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान मिलकर अ.जा./पि.व./विकलांग लाभार्थियों के लाभों के लिए ₹ 3,664.80 लाख का आवंटन किया। कंपनी ने ₹ 3,515.45 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिनमें से ₹ 3,370.77 लाख की संस्वीकृति दी गई। यद्यपि कंपनी ऋण के संवितरण के लिए मात्र ₹ 891.37 लाख (संस्वीकृत निधि का 26 प्रतिशत) ही आहरित कर सकी। पि.व. और विकलांग लाभार्थियों के मामले में क्रमशः 95 और 88 प्रतिशत संस्वीकृत निधि का आहरण नहीं किया गया। दिल्ली की जनसंख्या में इनकी पर्याप्त उपस्थिति होने के बावजूद कंपनी द्वारा तीनों श्रेणी के लाभार्थियों को ऋण संवितरित करने के लिए पूरी संस्वीकृत धनराशि का आहरण न करना कंपनी का अपने व्यक्त उत्तरदायित्वों का प्रभावी ढंग से निष्पादन करने में असफलता दर्शाता है। लक्षित समूह के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं।

(क) अनुसूचित जाति हेतु

2012-17 की अवधि के दौरान कंपनी की योजनाओं के अंतर्गत 3175 लाभार्थियों के लक्ष्य के प्रति 459 अ.जा. लाभार्थियों को ₹ 701.70 लाख ऋण प्रदान किया गया। एनएसएफडीसी द्वारा कंपनी को अ.जा. लाभार्थियों के संपूर्ण ऋण का 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्र, 40 प्रतिशत सेवा क्षेत्र और 10 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र को आवंटित करना आवश्यक है, और प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार/अल्प-रोजगार वाले, महिला और अन्य को क्रमशः 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की सीमा तक होना चाहिए। यद्यपि कंपनी ने अ.जा. लाभार्थियों को ऋण के संवितरण करते समय इन मानकों के पालन हेतु ऐसी प्राथमिकता का निर्वहन नहीं किया। इसे दिल्ली जैसे शहरी राज्य में किसी क्षेत्रवार परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं थी यदि निर्दिष्ट क्षेत्रीय आवंटन व्यवहार्य नहीं था, इसके अतिरिक्त एनएसएफडीसी ने फरवरी 2013 में 'सिंगल वुमन' हेतु योजना और दिसंबर

2014 में आय उपाजन के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने हेतु ई-रिक्शा, सौर पंप, इत्यादि के लिए ऋण के रूप वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 'हरित व्यवसाय योजना' (जीबीएस) आरंभ की। जीबीएस को जुलाई 2015 में कंपनी के बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त हुआ। यद्यपि कंपनी ने दोनों योजनाओं के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तक ऋण का संवितरण नहीं किया था। कंपनी ने इस लक्षित समूह के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु एनएसएफडीसी के रियायती ऋण को अन्य योजनाओं के साथ समरूपता सुनिश्चित करने हेतु समूह निर्माण हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए। एनएसएफडीसी ने एक व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) आरंभ की (फरवरी 2014) और इसका विवरण भी कंपनी को दिया गया। यह योजना लक्षित समूह हेतु छः माह से 24 माह के पाठ्यक्रमों को शामिल करती है, जिससे वेतन निर्धारण होता है। कंपनी को पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होने के लिए विस्तृत प्रचार और उन्हें 2014-15 से एनएसएफडीसी को प्रायोजित करना था जो कंपनी ने नहीं किया इस प्रकार अ.जा. लाभार्थियों को अभीष्ट लाभों से वंचित किया।

(ख) पिछड़ा वर्ग हेतु

2012-17 की अवधि के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के 2020 लाभार्थियों के लक्ष्य के प्रति 78 लाभार्थियों को कंपनी की योजनाओं के अधीन ₹ 42.26 लाख के ऋण दिये गये। 2014-15 और 2015-16 के दौरान कंपनी ने पिछड़ा वर्ग (पि.व.) लाभार्थियों के लाभ हेतु ₹ 350 लाख की संस्वीकृत धनराशि के विपरीत कोई धनराशि आहरित नहीं की। निधियां आवंटित करते समय एनबीसीएफडीसी ने वंचित और अशिक्षित लोगों में जागरूकता की कमी पर विचार किया और कंपनी को विशेष रूप से निर्देश दिया कि जागरूकता शिविर लगाए जाएं और योजनाओं का लक्षित समूहों में आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाए। लेकिन कंपनी ने इस संदर्भ में पर्याप्त कार्रवाई नहीं की और ऋणों का संवितरण मुख्यतः लाभार्थियों द्वारा कंपनी से सहायता मांगने के आधार पर किया गया, न कि कंपनी द्वारा पि.व. अभ्यर्थियों तक पहुंचने की किसी गतिविधि के आधार पर, जबकि 2012-17 के दौरान कंपनी के पास एनबीसीएफडीसी से प्राप्त निधि जो बैंक में जमा की गई थी, भी उपलब्ध थी (तालिका 2.2.4)।

(ग) विकलांग जनसंख्या हेतु

2012-17 की अवधि के दौरान कंपनी की योजनाओं के अंतर्गत 24 विकलांग लाभार्थियों को ₹ 36.57 लाख के ऋण दिये गये। 2.35 लाख

विकलांग जनसंख्या के विपरीत कंपनी 2003-04 से 2016-17 की अवधि के दौरान मात्र 887 लाभार्थियों को ऋण संवितरित कर सकी। कंपनी 2012-13 से 2016-17 के दौरान 696 के लक्ष्य के प्रति केवल 24 लाभार्थियों को ऋण संवितरित कर सकी। इस शीर्ष निगम ने सितंबर 2015 में कंपनी द्वारा खराब निष्पादन और विकलांग व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने में शिकायत इंगित की। एनएचएफडीसी ने कंपनी को लाभों को बढ़ाने के लिए अधिक प्रस्ताव भेजने का विशेष रूप से निर्देश दिया। कंपनी को एक विशेष अभियान द्वारा अशक्त व्यक्तियों के अधिक प्रस्तावों को प्रायोजित करने हेतु जिला कार्यालयों को संवेदनशील बनाना था। इसने कंपनी को विशेष रोजगार केंद्र तथा दिल्ली प्रशिक्षण संस्थान के डाटाबेस से बेरोजगार व्यक्तियों की एक सूची बनाने और भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के माध्यम से अशक्त व्यक्तियों को संपार्श्विक निशुल्क ऋण प्रदान करने की संभावना तलाशने का भी निर्देश दिया। लेकिन कंपनी ने 2012-17 के दौरान बैंकों में जमा एनएचएफडीसी से प्राप्त निधि उपलब्ध होने के बावजूद आवश्यक कदम नहीं उठाए (तालिका 2.2.4)।

(घ) अल्पसंख्यक हेतु

कंपनी ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 हेतु ₹ 332.95 लाख के आवंटन हेतु एनएमडीएफसी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके लिए कंपनी को ₹ 200 लाख की संस्वीकृति मिली, परंतु अल्पसंख्यक लाभार्थियों को ऋण संवितरण हेतु मात्र ₹ 25.50 लाख आहरित किए गए। कंपनी ने 2012-17 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान मात्र 59 अल्पसंख्यक लाभार्थियों को ऋण संवितरित किया जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं हैं क्योंकि दिल्ली रा.रा.क्षे. में बड़ी मात्रा में अल्पसंख्यक जनसंख्या है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएमएफडीसी ने कंपनी को न्यूनतम पांच जागरूकता शिविर/मेलों का आयोजन करने हेतु 2012-17 के दौरान वार्षिक रूप से ₹ 2.50 लाख अतिरिक्त रूप से आवंटित किया लेकिन कंपनी ने कोई जागरूकता शिविर नहीं लगाया। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों और संस्वीकृत आहरित धनराशि की सूचना प्रदान नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त शीर्ष निगम ने कंपनी को लाभार्थियों की मृत्यु/अशक्तता के लिए और वित्त प्रदान करते समय परिसंपत्तियों का बीमा करवाना आवश्यक कर दिया और कहा कि प्रीमियम की धनराशि को ऋण धनराशि का भाग होना चाहिए। इस प्रयोजन से कंपनी को लाभार्थियों और उनकी

परिसंपत्तियों का बीमा करने हेतु एक बीमा कंपनी से समझौता करना था। परंतु कंपनी अपने लाभार्थियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही।

कंपनी ने उपरोक्त क्रं. सं. (क) से (घ) के बिंदुओं को स्वीकार किया तथा संस्वीकृत निधियों के उपयोग में कमी के लिए आय मानदंड के गैर-संशोधन जो रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी से भी कम है तथा 2013 और 2015 के बीच चुनावों के दौरान मॉडल आचार संहिता के कार्यान्वयन को उत्तरदायी ठहराया। चुनाव समय के दौरान आदर्श आचार संहिता को चालू कल्याण योजनाओं के खराब कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता तथा यह कि कंपनी और रा.रा.क्षे.दि.स. का उत्तरदायित्व था कि आय मानदंड को संशोधित करें यदि उन्होंने इसे रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियत सांविधिक न्यूनतम मजदूरी से कम पाया।

(ड) सफाई कर्मचारियों हेतु

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) ने 2012-17 के दौरान ₹ 166.80 करोड़ आवंटित किया। जबकि कंपनी इस लाभार्थी समूह (₹ 1.20 लाख तक की वार्षिक आय वाले) हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मार्च 2016 में एनएसकेएफडीसी से मात्र ₹ नौ करोड़ (5.39 प्रतिशत) आहरित कर सकी जिसका उपयोग भी नहीं हुआ। लेखापरीक्षा में सफाई कर्मचारियों को अप्रयुक्त निधियों को संवितरित करने हेतु कोई कार्रवाई योजना भी नहीं देखी गई जो बैंक में निवेश करके रखी गई थीं।

कंपनी ने कहा कि निधि का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि शीर्ष निगम द्वारा निश्चित योग्यता दिशानिर्देश को सूचित नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी पांच वर्षों तक इस संबंध में शीर्ष निगम के साथ इस मुद्दे को प्राप्त करने अथवा हल करने में असफल रहा।

(च) अनुसूचित जनजातियों हेतु

जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली में कोई मूल/क्षेत्रीय अनुसूचित जनजाति नहीं थी। यद्यपि दिल्ली में रह रहे अन्य राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की उपस्थिति जानने हेतु और उनके आर्थिक विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को समझते हुए रा.रा.क्षे.दि.स. ने कंपनी के संधि ज्ञापन को संशोधित किया (25 जुलाई 2001) और इसे दिल्ली की अ.ज.जा. जनसंख्या के लाभ हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) से प्राप्त निधियों की चैनलाइजिंग एजेंसी भी घोषित किया। कंपनी ने अ.ज.जा. जनसंख्या को निधियां जारी करने के मामले पर

अक्टूबर 2002 में सीएमडी, एनएसटीएफडीसी से चर्चा की। लेकिन 2002 के बाद इस शीर्ष निगम से किसी चर्चा का कोई प्रमाण या इस संबंध में किए गए किसी प्रयत्न का कोई प्रमाण नहीं था और इसके फलस्वरूप दिल्ली में रह रही अ.ज.जा. जनसंख्या को कंपनी की विभिन्न क्रेडिट योजनाओं के अंतर्गत लाभ नहीं मिल सका।

कंपनी ने रा.रा.क्षे.दि.स. से स्पष्ट दिशानिर्देशों के अभाव तथा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिल्ली में अ.ज.जा. की गैर-पहचान को ऋण के गैर-संवितरण कारणों को उत्तरदायी ठहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने दिल्ली में 2002 के पश्चात् अ.ज.जा. जनसंख्या को निधियां प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। गैर-संवितरण के लिए उल्लिखित कारण रा.रा.क्षे.दि.स. के मानक के अंदर थे और उन्हें प्रभावी रूप से संबोधित किया जाना चाहिए था।

2.2.4.3 कंपनी द्वारा सरकारी निधियों से सृजित प्रशिक्षण संकाय में प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त अभ्यर्थियों को प्रायोजक न करना

कंपनी ने एपेरल डिज़ाइनिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर (एटीडीसी) के साथ इस लाभार्थी समूह को प्रशिक्षण देने हेतु ₹ 30 लाख के सरकारी अनुदान से प्रशिक्षण अवसंरचना का निर्माण करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (दिसंबर 2007) जिससे कपड़ा उद्योग में रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- क) इस अनुदान के नियमों और शर्तों के अनुसार कंपनी को लाभार्थी समूहों (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांग/सफाई कर्मचारी) से संबंधित 500 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष ऐसे प्रशिक्षण के लिए प्रायोजक करना था जबकि कंपनी ने लेखापरीक्षा में शामिल की गई 2012-2017 की अवधि के दौरान 2500 व्यक्तियों के लक्षित समूहों के लक्ष्य के विपरीत मात्र 342 अभ्यर्थी ही प्रायोजक/प्रशिक्षित किए। इस प्रकार सरकार के अनुदानों से प्रशिक्षण केंद्र चलाने का कथित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया। कंपनी ने कहा (जनवरी 2018) कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2015-16 तथा 2016-17 वर्षों के लिए निधियां प्रदान नहीं कीं। प्रबंधन के उत्तर ने पूर्व के वर्षों में लक्ष्य की गैर-उपलब्धि के लेखापरीक्षा विचार को संबोधित नहीं किया।
- ख) समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी को इस केंद्र की स्थापना हेतु कंपनी मुख्यालय में 5875 व.फी. कार्यालय स्थान ₹ एक प्रतिवर्ष के नाममात्र किराए पर प्रदान करना था। समझौता ज्ञापन के नियमों व शर्तों का उल्लंघन करते हुए कंपनी ने एटीडीसी को सक्षम प्राधिकारी से कोई

आधिकारिक समझौता हुए बिना दिसंबर 2007 से नवंबर 2013 के दौरान किराए वसूले बिना 4092 व.फी. का अतिरिक्त स्थान प्रयोग करने की अनुमति दी। इस प्रकार लक्षित समूह के प्रशिक्षण हेतु स्थान उपलब्ध कराने के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रदान की गई सुविधा को पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया गया। यद्यपि इस अतिरिक्त स्थान के लिए लो.नि.वि. द्वारा निर्धारित किराया ₹ 9.82 लाख प्रतिवर्ष था जो अप्राधिकृत अवधि के लिए प्राकलन करने पर ₹ 58,92,480 है और इसके लिए कंपनी ने वसूली की कोई मांग नहीं की।

2.2.4.4 ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियाँ

लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:

- (i) **सर्वेक्षण की कमी** - कंपनी ने गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) रह रहे लाभार्थियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया जिससे वित्तीय सहायता की योजना व प्रावधान हेतु आधार प्राप्त हो सके और चरणवार ढंग से संपूर्ण जनसंख्या को शामिल किया जा सके। कंपनी ने गरीबी रेखा के नीचे रह रही लक्षित लाभार्थियों की जनसंख्या के लिए व्यवहार्य व्यवसाय एवं व्यापार की पहचान हेतु कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया। परिणामस्वरूप वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके।
- (ii) **ऋण प्रदान करने की शर्तों का अनुपालन न होना** - संयुक्त ऋण और परिवहन ऋणों के संवितरण में निम्नलिखित प्रमुख विचलन पाये गये:
 - (क) 2012-17 के दौरान संवितरित कुल 501 संयुक्त ऋणों में से लेखापरीक्षा में ऐसे 60 ऋण मामलों की नमूना जांच की गई और यह पाया गया कि लाभार्थियों से कोई आपूर्तिकर्ता बिल प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि जारी ऋण को निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग होना प्रमाणित करने के लिए ऋण के नियमों व शर्तों के अंतर्गत अनिवार्य था।
 - (ख) कंपनी के नागरिक घोषणापत्र के अनुसार सभी ऋणों को संवितरित करने हेतु अधिकतम समयसीमा 52 दिन थी। लेखापरीक्षा में 22 परिवहन और 60 संयुक्त ऋण मामलों की नमूना जांच की गई और यह पता चला कि परिवहन बिलों के संवितरण में 766 से 1055 दिनों तक का विलंब हुआ जबकि संयुक्त ऋण योजना के मामलों में 13 से 393 दिनों तक का विलंब पाया गया। इनमें से 23 मामलों में 100 दिनों से अधिक का विलंब हुआ।

(ग) कंपनी के हित की सुरक्षा हेतु ऋण संवितरण की शर्तों में ऋण से प्राप्त वित्त से निर्मित परिसंपत्तियां के लिए एक बंधपत्र और बंधक परिसंपत्तियों का बीमा किया जाना शामिल था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन परिसंपत्तियों के बंधपत्र (परिवहन ऋण को छोड़कर) पर हस्ताक्षर ऋणों के संवितरण के बाद नहीं हुए थे। परिवहन ऋणों के मामले में लाभार्थियों ने पहले वर्ष हेतु विस्तृत बीमा नीतियाँ प्रस्तुत की थीं परन्तु बाद के वर्षों में ऐसी नीति का नवीकरण करना हालांकि सुनिश्चित नहीं किया गया।

कंपनी ने कहा कि संस्वीकृत पत्र के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन तथा नागरिक घोषणापत्र में निर्धारित समयसीमा की अनुपालना को जारी करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) दिल्ली स्वरोजगार योजना (डीएसवाई) के अंतर्गत ऋण - यह योजना 2012-13 के दौरान आरंभ की गई जिसे कंपनी द्वारा, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदत्त ₹ 100 करोड़ की कुल समग्र निधि में से प्रथम किश्त के रूप में दिए ₹ 50 करोड़ की समग्र निधि पर प्राप्त ब्याज में से वित्तपोषित किया जाना था। 25 डीएसवाई ऋण मामलों जिनको ₹ 75.20 लाख संवितरित किया गया, की नमूना जांच में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

क) कंपनी ने अपने नागरिक घोषणापत्र में परिकल्पित अधिकतम 52 दिनों की अवधि के विपरीत 175 और 938 दिनों के विलंब से ऋण संवितरण किए।

ख) जुलाई 2015 में कंपनी ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें शाखा/योजना प्रभारियों को अनुदेश दिए कि सभी ऋण लाभार्थियों को ₹ दो लाख प्रति की बीमा सुरक्षा नाममात्र प्रीमियम की दर जिसकी कटौती लाभार्थी के बैंक खाते से वार्षिक रूप से की जाएगी, कवर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। जबकि 25 में से 10 लेखापरीक्षित मामलों में ऋण लाभार्थियों को बीमा सुरक्षा प्रदान नहीं की गई।

ग) चूंकि कंपनी ने लेखों के समयपूर्व समापन के कारण हानियां वहन की, सीएमडी ने शाखा प्रभारियों को अनुदेश दिया (फरवरी 2015) कि संबंधित बैंक प्रबंधकों को पत्र जारी किये जायें कि यदि आवेदक/लाभार्थी ने कंपनी को पूरा ऋण वापस नहीं किया है, वे लाभार्थियों के खाते कंपनी को सूचना दिए बगैर बंद न करें।

हालांकि नमूना जांच किए गए मामलों में इन निर्देशों का पालन नहीं हुआ।

कंपनी ने कहा कि 54 लाभार्थियों जिन्होंने अपने बैंक खाते बंद किए, में से 17 लाभार्थियों ने अपने बकाया ऋणों का भुगतान किया था। हालांकि तथ्य यह है कि शाखा प्रभारियों द्वारा सीएमडी के अनुदेशों का पालन नहीं किया गया। कंपनी यह जांच कर सकती थी कि शाखा प्रभारियों ने इन अनुदेशों का पालन और उचित कार्रवाई क्यों नहीं की।

- घ) पांच मामलों में, ऋण से सृजित परिसंपत्तियों के बिल लाभार्थियों से प्राप्त नहीं हुए, जिससे सुनिश्चित हो सके कि ऋण/निधियों का उपयोग लाभार्थी ने उसी प्रयोजन से किया, जिसके लिए इसे जारी किया गया।
- ड) समग्र निधि का अलग बैंक खाता भी नहीं रखा गया क्योंकि डीएसवाई को समग्र निधि की ब्याज आय से संचालित करना था और इसे अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था।

(iv) सभी योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रस्ताव निरस्त करने में पारदर्शी प्रक्रिया का अभाव

निरस्त मामलों की सूची और अभिलेखों का उचित प्रकार से रखरखाव नहीं हो रहा था। यद्यपि हम 93 निरस्त मामलों की नमूना जांच कर सके और 2012-17 की अवधि से संबंधित निरस्त ऋण मामलों में निम्नलिखित कमियां पाई गईं। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:-

- (क) पांच मामलों में जिन्हें आरंभ में आवेदनों की प्राप्ति के बाद संचालित क्षेत्र सर्वेक्षण रिपोर्ट में ऋण के संवितरण के लिए उपयुक्त पाया गया, उन्हें बाद में उन्हीं पैमानों पर निरस्त किया गया, जिनपर क्षेत्र सर्वे रिपोर्ट में उन्हें उपयुक्त पाया गया। चार मामलों में, आवेदक को कई बार लंबे अंतराल पर त्रुटि ज्ञापन जारी किए गए जिनमें अलग-अलग कमियां इंगित की गईं। ये सभी कमियां एक बार में ही इंगित की जा सकती थीं।
- (ख) पांच मामलों में आवेदन आवश्यकताओं की गैर-पालना होने के आधार पर निरस्त किए गए, जिन्हें आवेदक ने पहले ही पूर्ण कर दिया था। आवेदनों को एक ऐसे मामले में इस आधार पर निरस्त किया गया कि आवेदक को प्रस्तावित कार्य का ज्ञान नहीं था

जिसमें आवेदक एक सामान्य प्रकृति का व्यवसाय अर्थात् रेडीमेड कपड़ों की बिक्री आरंभ करना चाहता है।

(ग) तीन मामलों में ऋण आवेदनों को निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक पारिवारिक आय का संदर्भ देकर निरस्त किया गया जो उचित नहीं था क्योंकि एक पिता (एक सरकारी कर्मचारी) की आय को भी एक विवाहित आवेदक की पारिवारिक आय में जोड़ा गया जो स्थापित मानदंड का उल्लंघन था।

(घ) पांच मामलों में आवेदनों को इस आधार पर निरस्त किया गया कि आवेदक ने त्रुटिपूर्ण परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की या उपयुक्त कार्यस्थल नहीं था। कंपनी ने आवेदकों को परियोजना रिपोर्ट का मानक प्रारूप प्रदान नहीं किया जिसके कारण आवेदकों को इन योजनाओं का वांछित लाभ नहीं मिल सका।

कंपनी ने कहा कि ऋण प्रस्तावों जिन्हें यहां तक कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान भी उचित पाया गया के निरस्तीकरण के मुख्य कारण निर्धारित औपचारिकताओं का पूर्ण न होना था जैसाकि योजना में बताया गया अथवा कार्यस्थल पर्याप्त नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने निरस्त मामलों को इंगित किया है जो वस्तुपरक ढंग से प्रक्रियारत नहीं थे।

2.2.5 वसूली निष्पादन

2.2.5.1 निराशाजनक वसूली निष्पादन

कंपनी लाभार्थियों को ऋण प्रदान करती है जिनकी पुनर्भुगतान अवधि शिक्षा ऋण के मामले को छोड़कर, तीन से पांच वर्षों के बीच होती है। ₹ 50,000 तक के ऋणों के लिए कंपनी द्वारा कोई प्रतिभूति नहीं ली जाती है जबकि ₹ 50,000 से अधिक ऋण के लिए ऋण धनराशि में से क्रय की गई परिसंपत्तियां कंपनी के पक्ष में बंधक बना दी जाती हैं। मूल राशि व ब्याज की लाभार्थियों द्वारा नकद/चेक/आगे की तिथि के चेक द्वारा समान मासिक किश्तों से वसूल होती है। वर्ष 2016-17 के दौरान की गई वसूलियों का विवरण तालिका 2.2.5 में दिया है।

तालिका 2.2.5: वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण वसूली का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

वसूली का मामला	1 अप्रैल 2016 को वसूली योग्य राशि	2016-17 के दौरान वसूल की गई	वसूली की %
1	2	3	4 = 3/2x100
चालू मामले	210.52	198.96	94.51
अतिविलंबित मामले	2,480.98	104.42	4.21
कुल	2,691.50	303.38	11.27

यह पाया गया कि कंपनी अतिविलंबित मामलों में धनराशि को वसूल नहीं कर सकी और 1 अप्रैल 2016 को बकाया ₹ 24.81 करोड़ के विपरीत, 2016-17 के दौरान मात्र ₹ 1.04 करोड़ वसूल किया जा सका। ऋणों की वसूली न होने से कंपनी द्वारा अन्य लक्षित लाभार्थियों को क्रेडिट प्रदान करने की योग्यता बाधित होती है।

कंपनी ने कहा कि बकाया ऋण की वसूली के लिए निदेशक मंडल ने अक्टूबर 2017 में एक समिति के गठन का निर्णय लिया है जोकि 'एक बार निपटान' योजना सहित उत्तम संभव तरीकों का सुझाव दे।

2.2.5.2 3533 ऋण मामलों की फाइलों में बकाया देयों की वसूली न होना

कंपनी ने अपनी स्थापना से मार्च 2017 तक 10,647 लाभार्थियों को ऋण संवितरित किया और 5,455 लेखाओं का निपटान कर दिया गया था तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। इस प्रकार कंपनी के पास 5,192 लाभार्थियों की ऋण फाइलें होनी चाहिए जिसके लिए वसूली प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए थी। यद्यपि मार्च 2017 तक वसूली विभाग ने मात्र 1,524 लाभार्थियों को नोटिस जारी किया जिसमें वसूली-योग्य धनराशि ₹ 9.19 करोड़ थी और विधिक विभाग ने ₹ 1.75 करोड़ की वसूलीयोग्य राशि के लिए 135 वसूली मुकदमे दायर किए। यह जांच का विषय है कि शेष 3,533 मामलों में जिनका निपटान नहीं हुआ, वसूली की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई।

कंपनी ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने गुम हुई फाइलों को ढूंढने तथा पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है। उत्तर दर्शाता है कि ऋण वसूली पर प्रबंधन की निगरानी कमजोर थी जैसाकि उन्हें इस मुद्दे को इंगित करने के लिए लेखापरीक्षा का इंतजार नहीं करना चाहिए था तथा अपने आप स्वयं ही कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए।

2.2.5.3 ऋण किश्तों की वसूली शून्य होने के कारण हानि

89 लाभार्थियों ने जिन्हें 2000 और 2017 के बीच ₹ 62.48 लाख का ऋण संवितरित किया गया था, अब तक एक भी किश्त जमा नहीं की थी। यद्यपि कंपनी ने ऋणों का संवितरण करते समय ऋणकर्ताओं से उत्तर दिनांकित चैक प्राप्त किए थे लेकिन चैक निकासी के समय अस्वीकृत हो गए। उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिन्होंने इन 89 ऋणों की संस्वीकृति के समय गारंटी दी थी। इसके

अतिरिक्त कंपनी ने न तो कोई वसूली सूचना/अनुस्मारक जारी किये, और न ही ऐसे मामलों को इन देयताओं की वसूली भूमि राजस्व के बकायों के रूप में करने के लिए राजस्व विभाग को सुपुर्द किये, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.48 लाख की हानि हुई जिसे तालिका 2.2.6. में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2.6: एक भी किश्त न भरने वाले लाभार्थियों का विवरण

वर्ष	लाभार्थियों की सं.	ऋण की राशि (रूपये में)
2000-01	1	1,36,487
2001-02	10	6,81,232
2002-03	17	11,97,087
2003-04	29	20,79,446
2004-05	9	6,71,705
2005-06	8	5,12,722
2006-07	6	4,00,664
2007-08	2	1,39,804
2009-10	2	41,484
2010-11	2	2,54,330
2015-16	1	80,816
2016-17	2	51,756
कुल	89	62,47,533

कंपनी ने कहा कि बकाया ऋण की वसूली के लिए निदेशक मंडल ने एक बार निपटान योजना सहित उत्तम संभव तरीकों के सुझाव के लिए एक समिति के गठन का निर्णय लिया (अक्टूबर 2017)।

इसके अतिरिक्त बोर्ड ने जुलाई 2015 में हुई अपनी बैठक में यह संकल्प किया कि उन 66 लाभार्थियों के विरुद्ध पुलिस शिकायत (एफआईआर) दर्ज कराई जाए जिन्होंने कंपनी से ऋण प्राप्त होने के बाद अपने बैंक खाते बंद करा दिए थे।

कंपनी ने कहा कि उसने एफआईआर दर्ज करने के लिए 25 सितंबर 2012 को रोहिणी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एक पत्र लिखा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न तो एफआईआर दर्ज कराई जा सकी और न ही की गई कार्रवाई की स्थिति को कंपनी ने बोर्ड के समक्ष रखा।

2.2.5.4 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 8.27 करोड़ की वसूली न होना

निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ उन मामलों से संबंधित हैं जिनमें कंपनी के अधिकारियों ने विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत बकाया ₹ 8.27 करोड़ की वसूली के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की और कंपनी ने भी इस संबंध में

उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध उनकी देयता निर्धारित करने के लिए कार्रवाई नहीं की।

(क) व्यावसायिक यातायात वाहनों के वित्तपोषण हेतु ग्रामीण परिवहन वाहन आरटीवी योजना/हरी भरी योजना के अंतर्गत 63 लाभार्थियों को ऋण दिये गये। कुल 25 लाभार्थियों ने अपने देयों का भुगतान किया और शेष 38 लाभार्थी चूककर्ता बने और ₹ 2.69 करोड़ की बकाया धनराशि को बोर्ड द्वारा ऋणकर्त्ता के अभिवेदन और/अथवा राजनीतिज्ञों की सिफारिशों पर बट्टे खाते में डाला गया (फरवरी 2016)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं किया कि कैसे और क्या ये ऋणकर्त्ता वास्तव में भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे, और कंपनी द्वारा वित्तपोषित वाहनों का क्या हुआ? इसके अतिरिक्त जो लाभार्थी ऋण का भुगतान कर चुके थे, उनका उत्साह कम होगा और इससे अन्य लाभार्थियों को उनके ऋण के पुनर्भुगतान में चूक को प्रोत्साहन मिलेगा। इस बीच कंपनी ने बट्टे खाते में डाली गई धनराशि की पूर्ति करने हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. से तीन करोड़ का सहायता अनुदान प्रदान करने का अनुरोध किया और इसपर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।

कंपनी ने कहा कि लाभार्थियों को दिल्ली के परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमत लाभदायक रूट नहीं दिए गए और इसके परिणामस्वरूप लाभार्थी ऋण का पुनर्भुगतान नहीं कर सके। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दिल्ली परिवहन प्राधिकरण रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत कार्य करता है और अनुमत रूट सौंपे जाने में कमियों को हल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ₹ 2.69 करोड़ को बट्टे खाते में डालने के निर्णय का तात्पर्य है कि ₹ तीन करोड़ के सहायता अनुदान के दावे से गैर-वसूली का प्रभाव अब सरकार को चला जाना था।

(ख) कंपनी ने अ.जा. लाभार्थियों को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु डीज़ल चालित डीलक्स बसों और टैपों ट्रेवलर्स हेतु 1997 और 2000 के बीच ऋण संवितरित किये जिनकी पुनर्भुगतान अवधि अदिनांकित चैकों के प्रति पांच वर्ष थी। ये ऋण इस तथ्य के बावजूद संवितरित किए गए कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1986-1998 के दौरान दिल्ली में प्रदूषण कम करने हेतु सीएनजी वाहनों के पक्ष में और 31 मार्च 2001 के बाद डीजल-चालित वाहनों को रोकने हेतु अनेक आदेश पारित किए। कंपनी द्वारा वित्तपोषित इन वाहनों का चलना 31 मार्च 2001 के बाद बंद हो गया और सभी अ.जा. लाभार्थियों ने कंपनी के ऋण का भुगतान रोक दिया। कंपनी की वसूली कार्रवाई पर उच्च न्यायालय की रोक वर्ष 2007 में रद्द हो गई जिससे कंपनी को ऋणों की वसूली हेतु चैक

प्रदान करने की अनुमति मिल गई। यद्यपि कंपनी ने अगले छः वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की और 2013 में ऋणकर्त्ताओं ने चैक प्रस्तुत किए जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया। यद्यपि कंपनी ने वसूली के लिए चूककर्त्ता ऋणकर्त्ताओं के विरुद्ध कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की और 2007 में स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद चैक प्रस्तुत न करने हेतु उत्तरदायी कार्मिकों पर जवाबदेही लागू की। इसके फलस्वरूप पिछले 11 वर्षों से ₹ 2.69 करोड़ के ऋण की वसूली नहीं हुई और यह अशोध्य हो गया है।

(ग) 2004 और 2008 के बीच 1991-92 और 1995-96 के बीच ₹ 1.43 करोड़ के 133 ऋण मामलों में पुनर्भुगतान हेतु एक मुकदमा कथित रूप से दायर किया गया। यद्यपि इस कानूनी कार्रवाई के संबंध में कानून अधिकारियों से परामर्श, न्यायालयी कार्रवाई न्यायालय निर्णय, यदि कोई हो, का कोई प्रमाण नहीं था। मार्च 2015 में सात वर्षों के बाद कंपनी के सीएमडी ने इन मामलों को एसडीएम कार्यालय के माध्यम से भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने के लिए वसूली अनुभाग भेजा और प्राथमिक पूछताछ रिपोर्ट के बाद उत्तरदायी कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। यद्यपि लेखापरीक्षा में किसी अनुपालना कार्रवाई जिसका आदेश सीएमडी द्वारा दिया गया, के लिए फाइल में कोई प्रमाण नहीं मिला।

(घ) कंपनी द्वारा देयों की वसूली हेतु दायर ₹ 1.09 करोड़ के 65 कानूनी मुकदमों में 2006 में कंपनी के पक्ष में आदेश दिया गया। लेकिन वसूली करने के लिए निष्पादन याचिका दायर नहीं की गई। याचिकाएं दायर न करने का कारण यह था कि कंपनी के पास न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं थीं। आठ वर्षों बाद जनवरी 2014 में ये मामले न्यायालय आदेश की प्रति प्राप्त करने और निष्पादन याचिकाएं दायर करने हेतु तीन वकीलों को सौंपे गए। इसके अतिरिक्त जनवरी 2014 में कार्य सौंपने के बाद याचिकाएं दायर करने के समर्थन में तीन वकीलों से न तो कोई लिखित अभिपुष्टि प्राप्त हुई न ही करीब तीन वर्ष बीत जाने के बाद मामले में कोई प्रगति होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ का अवरोध हुआ और इसपर मिलने वाले ब्याज की हानि हुई।

(ङ) जुलाई 2016 में 2005-07 के दौरान मंगोलपुरी शाखा में संवितरित 47 ऋण मामलों की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया। इन मामलों की संस्वीकृति के समय जीएम ने शंका व्यक्त की कि कुछ योग्यता प्रमाणपत्र फर्जी भी हो सकते हैं। शंका व्यक्त होने के बावजूद ₹ 23.75 लाख का ऋण संवितरित किया गया। आंशिक रूप से वसूली के बाद 31 मार्च 2017 को

₹ 21.76 लाख की धनराशि बकाया थी। जुलाई 2016 में जारी आदेशों के अनुसार कोई पूछताछ आयोजित/संपन्न नहीं की गई।

कंपनी ने उपरोक्त क्र.सं. (ख) से (ड) के संबंध में कहा कि अक्टूबर 2017 में निदेशक मंडल ने एक समिति के गठन का निर्णय लिया जिससे 'एक बार निपटान योजना' के जरिए विशेष वसूली अभियान सहित बकाया ऋणों की वसूली हेतु उत्तम संभव सुझाव मिल सकें।

2.2.6 जनशक्ति प्रबंधन

संचालनात्मक पदों में रिक्तियां

बोर्ड द्वारा मार्च 1996 में 155 कार्मिकों की संस्वीकृत संख्या का अनुमोदन किया गया जिसके प्रति 31 मार्च 2017 को विभिन्न पदों में 164 कार्मिक थे। 164 में से 67 नियमित मल्टी टास्क स्टाफ (एमटीएस) था जिनकी संस्वीकृत संख्या 32 थी जबकि संचालनगत पदों में बड़ी संख्या में रिक्तियां थीं। संस्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में एमटीएस रखने के लिए उत्तरदायी कार्मिकों की जवाबदेही लागू नहीं की गई। कंपनी ने उत्तर दिया कि सभी रिक्त पदों को समाप्त कर दिया गया है तथा वर्तमान में नियुक्त 73 एमटीएस सहित उनकी वर्तमान संस्वीकृत संख्या अब 164 कार्मिक हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच संस्वीकृत पदों के विपरीत केवल दो प्रबंधक तथा 31 संस्वीकृत पदों के विपरीत आठ अवर डिविज़नल क्लर्क थे। क्षेत्र निरीक्षक (आठ), सांख्यिकीय सहायक (तीन) तथा उप प्रबंधन, विधि (एक) के सभी पद रिक्त थे। कंपनी के कुल 164 कार्मिकों में से एमटीएस की संस्वीकृत संख्या 73 तक बढ़ाना सरकारी वित्त निगम के लिए व्यवहार्य संगठनात्मक अवसंरचना नहीं लगती है। रा.रा.क्षे.दि.स. को जांच करनी चाहिए कि क्या 73 एमटीएस की भर्ती वर्तमान नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार की गई तथा संगठन की उचित कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 164 कर्मचारियों में से 78 कर्मचारियों को ऋणों के संवितरण के लिए सीधे तौर से उत्तरदायी समझा जा सकता था जिन्होंने पांच वर्षों में 837 ऋण संवितरित किए गए। इस प्रकार औसतन प्रत्येक स्टाफ ने वर्ष में दो ऋण संवितरित किए। कंपनी को यह जांच करनी चाहिए कि रियायती ऋण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के संपूर्ण विषय में कर्मचारी-ऋण संवितरण अनुपात में कैसे सुधार किया जाए।

2.2.7 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण एक प्रबंधन उपकरण है जो विवेकपूर्ण ढंग से आश्वासन प्राप्त कराता है कि प्रबंधन के लक्ष्य कुशल प्रभावी और व्यवस्थित रूप से

प्राप्त हो रहे हैं। एक आंतरिक नियंत्रण ढांचे में कुशल और प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा विंग और इसके कार्यों के मार्गदर्शन हेतु नियम पुस्तिका व मानक संचालन क्रियाविधियां शामिल हैं। लेखापरीक्षा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:

- (क) कंपनी के पास क्रेडिट संवितरण और वसूली प्रचालनों का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए नीति, नियमावली और मानक प्रचालन क्रियाविधियां नहीं थी।
- (ख) यद्यपि कंपनी 1983 से लाभार्थियों को वित्तीय सहायता बढ़ाने में लगी है, इसने वर्तमान नियमों और विनियमों से अनुपालन का स्तर मूल्यांकित करने हेतु किसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का आरंभ नहीं किया है।
- (ग) ऋण किशतों/चूक की धनराशि की वसूली हेतु वसूली अनुभाग के कार्मिकों द्वारा किए गए दौरों के प्रमाण हेतु कोई अभिलेख नहीं था। इस प्रकार यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सकता था कि वसूली स्टाफ अपना कर्तव्य उचित ढंग से निभा रहा है या नहीं।
- (ङ) कंपनी, प्राप्तियों तथा जन शिकायतों के निपटान के अभिलेखों का रखरखाव नहीं कर रही है। ये शिकायतें और इनका निपटान कंपनी के एमडी के संज्ञान में नहीं लाया गया।

कंपनी ने कहा कि यह ऋणों के संवितरण में नागरिक घोषणापत्र का पालन करती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वहां आंतरिक लेखापरीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसकी प्रदत्त पूंजी ₹ 50 करोड़ से कम है। इसके अतिरिक्त कंपनी आवेदकों को उपयुक्त जवाब प्रेषित करती है तथा शिकायतों में आवश्यकता के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसाकि विभिन्न ऋण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कंपनी को मैनुअल, नीतियां तथा मानक संचालन प्रक्रियाएं बनानी थीं। आंतरिक लेखापरीक्षा वर्तमान नियमों तथा विनियमों के साथ अनुपालन के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। शिकायतों के अभिलेख नहीं रखे गए तथा ऐसी शिकायतों को कंपनी के एमडी के संज्ञान में भी कभी नहीं लाया गया।

2.2.8 निष्कर्ष

कंपनी के पास लक्षित समूहों को क्रेडिट प्रदान करने हेतु शीर्ष निगमों से प्राप्त पर्याप्त निधियां थीं, हालांकि यह अपने उत्तरदायित्वों को निष्पादित करने में विफल हो गई। वित्तीय सहायता प्रदान करने में कमियाँ थीं। इसने लक्षित

जनसंख्या का कोई सर्वेक्षण नहीं किया और ऋणों के संवितरण में बहुत अधिक विलंब था। वार्षिक वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी थी। 2012-17 के दौरान सभी शीर्ष निगमों से आहरित कुल निधियां ₹ 37.48 करोड़ थीं, जिसमें से कंपनी इस अवधि के दौरान ₹ 13.13 करोड़ संवितरित कर सकी। ऋण का संवितरण जो 2012-13 में कुल उपलब्ध निधियों का 45.41 प्रतिशत था, 2016-17 में कम होकर 12.90 प्रतिशत हो गया। कंपनी ने लक्षित समूहों के हितों को नुकसान पहुंचाते हुए रियायती ऋणों के संवितरण हेतु योग्य लाभार्थियों को ढूंढने की आऊटरीच पॉलिसी को अपनाने की बजाए निधियों को बैंकों में व्यर्थ रखा तथा उस पर अर्जित ब्याज को अपने स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए उपयोग किया।

लाभार्थियों से वसूली की प्रक्रिया असंतोषजनक थी। वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा की गई कुल वसूली मात्र 11 प्रतिशत थी और कंपनी के पास पिछले वर्षों की वास्तविक वसूली का कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। संवितरण के बाद की निगरानी भी कंपनी में नहीं थी और इस प्रकार, सृजित परिसंपत्तियों का गैर-सत्यापन, ऋण की कम वसूली और प्रभाव अध्ययनों का अभाव था। कंपनी ने लाभार्थियों को ऋण की संस्वीकृति तथा संवितरण पर नियंत्रण रखने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली आरंभ नहीं की है।

2.2.9 सिफारिशें

सरकार को विचार करना चाहिए:

कंपनी की स्थापना 1983 में की गई जब बैंकिंग प्रणाली प्रचलित नहीं थी। अब सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो उन बैंकों द्वारा चलाई जाती हैं जिनके पास आवश्यक अवसंरचना है तथा परियोजना मूल्यांकन से वसूली स्तर तक व्यवहार ज्ञान का अधिकार है इसलिए इसे इस क्षेत्र में चलाने के लिए कंपनी की प्राप्य राशियों की समीक्षा की सलाह मुख्यतः तब दी गई जब यह उसे पूरा करने में विफल रहा है।

कंपनी को विचार करना चाहिए:

(क) प्रत्येक लक्षित समूह में संभावित लाभार्थियों का प्रोफाइल बनाने के लिए आऊटरीच गतिविधियां संचालित करना तथा उन व्यवसाय व व्यापारों जिन्हें ऋण दिया जा सकता था की आर्थिक व्यवहार्यता निश्चित करने के लिए उनका डाटाबेस तैयार करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उनके बीच कंपनी की योजनाओं के बारे में जानकारी उत्पन्न करना।

- (ख) सुनिश्चित करना कि शीर्ष निगमों द्वारा आवंटित और संस्वीकृत निधियों को पूर्ण रूप से आहरित किया गया है तथा इनका अभीष्ट लाभार्थियों के लाभों के लिए उपयोग किया गया है।
- (ग) ऋण वसूली के निष्पादन में सुधार हेतु ऋण वसूली तंत्र तथा संबंधित अभिलेख प्रबंधन को सुदृढ़ करना।
- (घ) अभीष्ट लाभार्थियों के उत्कृष्ट हितों में कंपनी के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा निगरानी तंत्र का सुधार करना।

मामला सरकार को भेजा गया (नवंबर 2017), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

पावर विभाग

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

2.3 दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा न्यूनतम वैकल्पिक कर देयता का निर्धारण समय से करने में असफलता के फलस्वरूप अग्रिम कर के गैर-भुगतान के कारण ₹ 60.01 लाख के दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ा

रा.रा.क्षे.दि.स. ने 20 नवंबर 2001 की अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली विद्युत बोर्ड की सभी देयताओं को धारक कंपनी अर्थात् दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल) को हस्तांतरित व उसमें निहित कर दिया, जो अन्य उत्तराधिकारी संस्थाओं जैसे जेनको, ट्रांस्को और डिस्कॉम को आवंटित नहीं की गई थीं। इसके अतिरिक्त, डीपीसीएल को केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) के ₹ 3,376.69 करोड़ (8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित) की देयता के निपटान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया जो कि एनटीपीसी, बीटीपीएस, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल और एनपीसीआईएल को देय थे। सीपीएसयू की देयता का निपटान डीपीसीएल रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनुमोदित अनुदान से करता है।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 115 जेबी यह बताती है कि प्रत्येक करदाता कंपनी के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) देय है यदि किसी वर्ष के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुल आय पर परिकल्पित आयकर (सरचार्ज व उपकर सहित) बुक प्रॉफिट का 18.50 प्रतिशत से कम है। जिस करदाता का कर देय है, उसे अपनी वर्तमान आय की गणना करके स्वयं अग्रिम कर अदा करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 208

यह बताती है कि अग्रिम कर किश्तों में अदा किया जाएगा, जो 15 जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च को देय होगी। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी एक प्रतिशत प्रति माह या माह के भाग की दर से साधारण ब्याज लगाने का प्रावधान करती है, जहां करदाता अग्रिम कर अदा करने में विफल हो या करदाता द्वारा जमा किया गया अग्रिम कर परिकलित कर के 90 प्रतिशत से कम हो। धारा 234सी अग्रिम कर की किश्त (किश्तों) के भुगतान में चूक हेतु ब्याज लगाने का प्रावधान करती है।

वित्त वर्ष 2009-10 हेतु मैट के भुगतान में देरी और इसके बाद धारा 234बी व 234सी के अंतर्गत जुलाई 2014 में दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 2.02 करोड़ के भुगतान को 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा 2.4 में इंगित किया गया। इसलिए डीपीसीएल प्रबंधन से यह आशा थी कि वह सजग हो तथा समान गलती भविष्य में नहीं हो। हालांकि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि डीपीसीएल को वित्त वर्षों 2015-16 और 2016-17 के लिए क्रमशः ₹ 14.63 करोड़ एवं ₹ 20.76 करोड़ के ब्रुक प्रॉफिट पर मैट देयता परिकलित करने में विफलता के कारण धारा 234बी और 234सी के अंतर्गत ₹ 60.01 लाख दंडात्मक ब्याज (2015-16 के लिए ₹ 37.63 लाख और 2016-17 के लिए ₹ 22.38 लाख) अदा करना पड़ा।

अधिनियम के बार-बार उल्लंघन, जिस पर दंडात्मक ब्याज लगाया जाता है, के लिए उत्तरदायी कार्मिकों की जवाबदेही के प्रवर्तन तय करने के बजाय डीपीसीएल प्रबंधन ने फाईलों पर इन उल्लंघनों को यह बताते हुए नियमित कर दिया कि अग्रिम कर की अदायगी में देरी के लिए दंडात्मक ब्याज की धनराशि, राष्ट्रीकृत बैंकों में सावधि जमा के रूप में आरक्षित निधि पर अर्जित ब्याज से अधिकांश रूप से पूर्ण हो गया। प्रबंधन का यह तर्क अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन को उचित सिद्ध करने के लिए न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त, सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज धारा 234बी व 234सी के अधीन अदा किए गए दंडात्मक ब्याज से ₹ 25.41 लाख कम था।

इस प्रकार, डीपीसीएल द्वारा मैट देयता के समय से निर्धारण में असफलता के फलस्वरूप अग्रिम कर की गैर-अदायगी के कारण ₹ 60.01 लाख दंडात्मक ब्याज का भुगतान हुआ जो परिहार्य था।

मामला सरकार को भेजा गया (अक्टूबर 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

दिल्ली ट्रांस्को लि.

2.4 भूमि की खरीद पर निष्फल निवेश

प्रस्तावित उपकेंद्र हेतु भूमि की उपयुक्तता सुनिश्चित किए बिना ₹ 1.34 करोड़ की वार्षिक आवर्ती लागत पर और वर्ष 2022 तक इसकी स्थापना की किसी निश्चित योजना के बिना 2014 में भूमि का क्रय किया गया जिसके फलस्वरूप इस भूमि के लिए जुलाई 2017 तक भुगतान किए गए ₹ 4.08 करोड़ पर, जो अभी तक अवरूद्ध हैं एवं अलाभकारी हो गए हैं, इसके ऋणों पर दिये जा रहे ब्याज के अनुसार, ₹ 79.92 लाख के राजस्व की हानि हो गई

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मोलार बंद पर 10800 व.मी. की एक साईट पावर विभाग (डीओपी), रा.रा.क्षे.दि.स. को देने का प्रस्ताव दिया (दिसम्बर 2009), जिसपर 66 के.वी.ए. ग्रिड उपकेंद्र की स्थापना कर डीडीए के नए आने वाले 690 लोअर इनकम ग्रुप घरों में बिजली प्रदान की जानी थी। दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, (डी.टी.एल.) ने (दिसम्बर 2010) इस भूमि को निजी पावर वितरण कंपनी, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) के साथ अपने 220/60 के.वी. ग्रिड उपकेंद्र (डीटीएल द्वारा) और 66/11 के.वी. वितरण उपकेंद्र (बीआरपीएल द्वारा) को स्थापित करने हेतु संयुक्त रूप से प्राप्त करने के लिए सहमति दी। पावर विभाग (डीओपी) ने डीडीए को इसकी सूचना दे दी (मई 2011)।

डीडीए की भूमि नीति के अनुसार जो भूमि डीओपी को आवंटित की जाती है वह इसे पावर संस्थानों को वार्षिक लाइसेंस शुल्क लगाकर 'उपयोग के अधिकार' के आधार पर प्रदान कर सकती है। यद्यपि डीडीए ने केवल 8550 व.मी. तक की ही भूमि आवंटित की (नवंबर 2012) जिसके लिए डीओपी ने डीडीए को ₹ 11.16 करोड़ का भुगतान किया (मार्च 2013)। इसके बाद, डीओपी ने डीटीएल (5133 व.मी) और बीआरपीएल (3417 व.मी) को यह भूमि हस्तांतरित की (दिसम्बर 2014)।

चालू बिजली संबंधी परियोजनाओं की स्थिति के आकलन करते हुए योजना संचालन समिति²³ (पीएससी) को सूचित किया गया (अक्टूबर 2015) कि भूमि का उक्त टुकड़ा 220/66 के.वी. ग्रिड उपकेंद्र (डीटीएल द्वारा) और 66/11 के.वी. वितरण उपकेंद्र की स्थापना हेतु उपयुक्त नहीं था क्योंकि यह

²³ योजना संचालन समिति को दिल्ली बिजली विनियमन आयोग (स्टेट ग्रिड कोड) विनियम 2008 के अनुसार गठित किया गया। डीटीएल के महाप्रबंधक (योजना) इस समिति के अध्यक्ष हैं जिसमें डिस्कॉम के प्रतिनिधि भी हैं।

त्रिकोणाकार है और आवाजाही में कठिनाई है जिससे इन-फिड और आउटलेट में समस्या होगी। डीटीएल ने अंततः 19 माह के विलंब के बाद अप्रैल 2017 में प्रस्तावित सुविधाओं की स्थापना न करने और यह भूमि डीओपी को लौटाने का निर्णय लिया। इस बीच डीटीएल ने डीओपी को वार्षिक लाइसेंस शुल्क देना जारी रखा। इसने ₹ 4.08 करोड़ (जुलाई 2017 तक) अदा किये जो अलाभकारी हो गए। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

1. अक्टूबर 2015 में इसी भूमि को अनुपयुक्त पाया जाना और अप्रैल 2017 में प्रस्तावित उप केंद्रों की आवश्यकता न पाये जाने का यह अर्थ है कि डीओपी और डीटीएल ने डीडीए से भूमि अधिग्रहण करने में और पावर भार अनुमान लगाने में पर्याप्त सतर्कता और सावधानी नहीं बरती। डीटीएल ने भूमि अधिग्रहण से पहले उपकेंद्र की स्थापना की व्यवहार्यता का आकलन नहीं किया। वास्तव में 12 दिसंबर 2013 को की गई पीएससी बैठक में उपकेंद्र की स्थापना हेतु 8550 व.मी. भूखण्ड के खाके की उपयुक्तता पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन डीटीएल ने फिर भी डीओपी के निर्देशों के अधीन भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया।

2. डीटीएल ने 23 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण किया और इसलिए इसको वर्ष 2014-15 हेतु सामानुपात आधार पर 99 दिनों (23 दिसंबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक) के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान देय था लेकिन डीओपी के आग्रह के कारण डीटीएल को पूरे 2014-15 वर्ष के वार्षिक शुल्क का भुगतान करना पड़ा जबकि डीओपी ने बीआरपीएल को मात्र 99 दिनों का भुगतान करने की अनुमति दी। इस प्रकार डीटीएल ने ₹ 36.34 लाख के दायित्व के स्थान पर ₹ 1.34 करोड़ का भुगतान किया।

3. पीएससी को यह सूचना (अक्टूबर 2015) देने के बावजूद कि यह भूमि उपकेंद्रों के लिए उपयुक्त नहीं थी, डीओपी आगे की अवधि के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर अड़ा रहा और 2016-17 के वार्षिक शुल्क के भुगतान में विलंब हेतु 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ₹ 6.42 लाख का ब्याज वसूला।

इस प्रक्रिया में डीटीएल को अब भी अवरोधयुक्त भूमि के क्रय हेतु व्यय किए गए ₹ 4.08 करोड़ पर ₹ 79.92 लाख²⁴ के ब्याज की हानि हुई।

डीटीएल ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2017) कि बदली हुई परिस्थितियों के कारण इसे भूमि की आवश्यकता नहीं है और डीटीएल को आवंटित भूमि का टुकड़ा लाइसेंस उपयोग हेतु बीआरपीएल को सौंप दिया गया है (5 सितम्बर

²⁴ 10.50 प्रतिशत की दर से प्राक्कलित, जोकि उक्त अवधि में डीटीएल की ऋण दर है।

2017)। इसके अतिरिक्त जो भुगतान डीटीएल द्वारा डीओपी को भूमि के उसके भाग के लिए किया गया है वह बीआरपीएल के साथ निपटाया जा रहा है। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मान भी लिया जाए कि डीटीएल भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क बीआरपीएल से वसूल करेगी, डीटीएल ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की है कि वह 2014-17 के दौरान लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए प्रयोग की गई निधि की लागत भी वसूल करेगी।

इस प्रकार, ₹ 1.34 करोड़ की वार्षिक आवर्ती लागत पर 2014 में एक भूमि प्रस्तावित उपकेंद्र के लिए, बिना इस भूमि की उपयुक्तता सुनिश्चित किए और बिना वर्ष 2022 तक इसकी स्थापना की किसी योजना के खरीदना उचित नहीं था। इसके फलस्वरूप इस भूमि के लिए जुलाई 2017 तक भुगतान किए गए ₹ 4.08 करोड़ पर, जो अभी तक अवरोद्ध हैं एवं अलाभकारी हो गए हैं, इसके ऋणों पर दिये जा रहे ब्याज के अनुसार, ₹ 79.92 लाख के राजस्व की हानि हो गई।

मामला सरकार को भेजा गया (अगस्त 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

पर्यटन विभाग

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम

2.5 मयूर विहार में दिल्ली हाट के निर्माण पर ₹ 39.66 लाख का निष्फल व्यय

सर्वोच्च न्यायालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्देशों के अतिलंघन में तथा डीडीए द्वारा अक्टूबर 2013 में भूमि उपयोग के बदलाव को अस्वीकृत करने और यूटीटीआईपीईसी द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद मयूर विहार में दिल्ली हाट के निर्माण को प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप ₹ 39.66 लाख का निष्फल व्यय हुआ

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए (मई 2006)²⁵ कि विकास के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले पर्यावरण पर विकास के परिणाम तथा प्रतिकूल प्रभाव को समुचित रूप से समझना चाहिए तथा विकास के लिए ऐसी भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए जो पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को भारी क्षति न पहुँचाए। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के यूनीफाईड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग) सेंटर (यूटीटीआईपीईसी) की शासकीय निकाय ने किसी भी एजेंसी द्वारा दिल्ली में नालियों के ढकने

²⁵ कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास मंडल बनाम सी.केनचप्पा व अन्य {अपील (सिविल) 2000 का 7405} के मामले में

पर प्रतिबंध लगाया (फरवरी 2010)²⁶। लेखापरीक्षा में यह पाया गया है (मार्च 2017) कि संसद के एक सदस्य के सुझाव पर दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीडीसी) ने मयूर विहार में शाहदरा लिंक ड्रेन के एक हिस्से को कवर करते हुए दिल्ली हाट के निर्माण के प्रस्ताव को प्रारंभ किया (मई 2012) तथा डीडीए को भूमि उपयोग²⁷ के बदलाव हेतु आवेदन किया (अक्टूबर 2012)। रा.रा.क्षे.दि.स. के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएफसीडी) ने डीटीडीसी को मयूर विहार में शाहदरा लिंक ड्रेन की 27,000 वर्ग मीटर (व.मी.) भूमि को 99 वर्षों के लिए पट्टा आधार पर हस्तांतरित किया। लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ निम्नवत हैं:

1. डीटीडीसी ने भूमि उपयोग के बदलाव के लिए अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना संरचनात्मक डिजाइन, संरचनात्मक डिजाइन की प्रमाणिक जाँच तथा वास्तुगत परामर्श के लिए तीन सलाहकारों को क्रमशः जून, अगस्त तथा सितंबर 2013 में नियुक्त किया। भूमि उपयोग के बदलाव हेतु निवेदन हालांकि डीडीए के जाँच एवं सुनवाई मंडल ने 24 अक्टूबर 2013 को अस्वीकार कर दिया। कंपनी ने हालांकि परामर्श समझौतों को रद्द नहीं किया तथा मई 2015 तक उनकी सेवाएं लेना जारी रखा।

2. डीडीए द्वारा प्रारंभ की गई भूमि उपयोग के बदलाव की कार्यवाहियों पर रोक के लिए 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में किये गये आवेदन²⁸ पर अंततः निर्णय जनवरी 2015 में आया जिसने दिल्ली में किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी नाली के निर्माण और/अथवा कवरेज को निषेध कर दिया। कंपनी ने अप्रैल/मई 2015 में परामर्श समझौतों को रद्द कर दिया। इस समय तक कंपनी ने परियोजना पर पहले ही ₹ 39.66 लाख का व्यय कर दिया था जो निष्फल हो गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2017) कि परियोजना की पूर्वयोजित गतिविधियों को प्रारंभ करने में कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। मयूर विहार में दिल्ली हाट के निर्माण के लिए शाहदरा लिंक ड्रेन के कथित हिस्से की कवरिंग हेतु भूमि के हस्तांतरण का अनुमोदन दिल्ली के उप-राज्यपाल (एलजी) द्वारा प्रदान किया गया था। परियोजना की पूर्व-योजित गतिविधियों की समीक्षा दिल्ली के मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव द्वारा कई बार की गई थी। भूमि उपयोग के बदलाव की अनुमति पर डीडीए की तकनीकी समिति की बैठक में विचार किया गया (अप्रैल 2013)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव

²⁶ यूटीटीआईपीईसी के शासकीय निकाय की 21 वीं बैठक का कार्यवृत्त

²⁷ प्रस्तावित स्थल क्योंकि एक खुली नाली पर था, भूमि उपयोग का बदलाव आवश्यक था।

²⁸ श्री मनोज कुमार मिश्रा द्वारा फाईल की गई 2013 की सं. 300 तथा 2013 की एम.ए. सं. 877

आरम्भ से ही गलत था तथा भूमि उपयोग में बदलाव को अक्टूबर 2013 में डीडीए द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और इसे निम्नलिखित तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि भूमि के हस्तांतरण हेतु एलजी के अनुमोदन पत्र में कहा गया था कि डीटीडीसी को स्वयं ही डीडीए के साथ भूमि उपयोग के बदलाव के मामले को उठाना चाहिए तथा भूमि पर अस्थायी ढांचे को बनाने से पहले सभी नियामक एजेंसियों की पूर्व संस्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। अतः डीटीडीसी को डीडीए से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना सलाहकारों की नियुक्ति करके स्वयं को वित्तीय रूप से वचनबद्ध नहीं करना चाहिए था।

सरकार ने इस प्रकार यूटीआईआईपीईसी के फरवरी 2010 के किसी भी एजेंसी द्वारा नालियों को न ढकने के निर्णय एवं सर्वोच्च न्यायालय और सक्षम निकायों की घोषणाओं के उल्लंघन में, एक संसद सदस्य के सुझाव के आधार पर कंपनी को परियोजना शुरू करने का आदेश देकर गलत किया एवं ₹ 39.66 लाख का निष्फल व्यय किया जबकि उनको पहले सभी मंजूरी प्राप्त कर लेनी चाहिए थीं।

मामला सरकार को जून 2017 में भेजा गया तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

2.6 ब्याज की हानि

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम ने ग्राहक विभाग से डिपोजिट की पूर्व प्राप्तियों को सुनिश्चित किए बिना डिपोजिट कार्य पर व्यय करने के कारण ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज की हानि को वहन किया

रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व विभाग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) मैनुअल/सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के अनुसार सभी सांहितिक औपचारिकताओं तथा संबंधित अनुदेशों के अनुपालन के अध्याधीन डीटीडीसी को डिपोजिट कार्य आधार पर ई-उप- रजिस्ट्रार कार्यालय (आरओ) बसई दारापुर, दिल्ली का निर्माण तथा उन्नयन का कार्य सौंपा (अगस्त 2011)।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल की धारा 3.4(1) व (6) बताता है कि जब कभी डिपोजिट कार्य किया जाना हो, कार्य पर किसी देयता को उठाने से पहले डिपोजिट वसूल किया जाना चाहिए तथा कभी भी ग्राहक विभाग से अपने कार्य हेतु प्राप्त डिपोजिट्स को अन्य कार्यों में विपथित नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 15.09 करोड़ की कुल निर्माण लागत में से केवल ₹ 1.95 करोड़ की वसूली ठेके की समाप्ति से पहले की गई। डीटीटीडीसी ने कार्य की समाप्ति के पश्चात, जुलाई 2013 से जनवरी 2017 के दौरान, दो से 44 महीनों के बीच के विलंब से ₹ 12.79 करोड़ (कुल लागत का 85 प्रतिशत) प्राप्त किए और ₹ 34.74 लाख जुलाई 2017 तक अप्राप्य रहे।

इसके अतिरिक्त, डीटीटीडीसी डिपोजिट कार्यों की कुल लागत पर पाँच प्रतिशत विभागीय प्रभार तथा एक से तीन प्रतिशत परामर्श शुल्क लगाता है। इस कार्य में डीटीटीडीसी ने परामर्श शुल्क नहीं लगाया तथा विभागीय प्रभारों से इसका राजस्व ₹ 71.88 लाख था। व्यय करने से पहले आवश्यक डिपोजिट की गैर-प्राप्ति में निहित था कि डीटीटीडीसी ने कार्यों के निष्पादन के लिए अपनी स्वयं की निधियों का उपयोग किया था। डीटीटीडीसी बैंको में जमा अपनी अतिरिक्त निधियों से औसत ब्याज लगभग 6.5 प्रतिशत अर्जित करता है तथा डिपोजिट्स की पूर्व प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना डिपोजिट कार्यों पर व्यय करने का तात्पर्य है कि डीटीटीडीसी ने ₹ 1.18 करोड़ की ब्याज आय का परित्याग किया। इस प्रकार डीटीटीडीसी को इस कार्य को करने में निवल हानि थी।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2017) कि कार्य रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेशों पर किया गया था। उसने आगे यह कहा कि बसई दारापुर परियोजना के लिए प्रयुक्त निधियाँ समान शीर्ष में से थी अर्थात् अन्य ई-उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों के प्रति राजस्व विभाग डिपोजिट्स की थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन था तथा डीटीटीडीसी ने इस कार्य के निष्पादन के दौरान अपनी स्वयं की निधियों का उपयोग किया।

इस प्रकार, डीटीटीडीसी ने ग्राहक विभाग से डिपोजिट्स की पूर्व प्राप्ति को सुनिश्चित किए बिना डिपोजिट कार्य पर व्यय करने के कारण ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज की हानि को वहन किया।

2.7 व्यर्थ व्यय

डीटीटीडीसी की ओर से यथोचित कर्मठता तथा योजना की अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप भूमि को कथित उपयोग हेतु विकसित करने में 12 वर्ष का परिहार्य विलंब तथा ₹ 23.19 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, भूमि में निवेश की व्यर्थता होने का अभिप्राय है कि डीटीटीडीसी को ₹ 1.79 करोड़ की अवरुद्ध निधियों पर ₹ 1.27 करोड़ की ब्याज की हानि के साथ कोई अनुकूल राजस्व उत्पत्ति नहीं हुई

डीटीटीडीसी ने निदेशक कार्यालय (पंचायत), रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 1.38 करोड़ के वन-टाईम प्रीमियम तथा ₹ 3.44 लाख प्रतिवर्ष के भूमि किराये की लागत पर 99 वर्ष के पट्टे पर 5.22 एकड़ भूमि को सैदु-उल-अजब गांव, नई दिल्ली में विद्यमान अपने 20 एकड़ गार्डन, 'गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस' के विस्तार के लिए प्राप्त किया (अप्रैल 2005)।

डीटीटीडीसी ने पहले पांच वर्षों के दौरान (2005-2010) भूमि के विकास हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इसने वैलनेस सेंटर एंड रिक्रिएशन क्लब (डब्ल्यू सीआरसी) की स्थापना का निर्णय (2010-12) बिना इस जांच के लिया कि क्या विद्यमान गार्डन के विस्तार के लिए आवंटित भूमि पर डब्ल्यूसीआरसी का निर्माण डीडीए द्वारा फरवरी 2007 में अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान (डीएमपी)- 2021 के अंतर्गत अनुमत था। डीटीटीडीसी ने 'सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) पद्धति पर डब्ल्यूसीआरसी के 'निर्माण, संचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा स्थानांतरण' के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीए) को नियुक्त किया (अक्तूबर 2012)।

पीडीए ने हालांकि डीटीटीडीसी को अपना व्यवहार्यता अध्ययन तथा व्यापार योजना प्रस्तुत करते समय (फरवरी 2013) संदेह जताया कि क्या डब्ल्यूसीआरसी का निर्माण डीएमपी -2021 के अंतर्गत अनुज्ञेय होगा। परन्तु इस स्तर पर भी डीटीटीडीसी ने इस बारे में डीडीए से कोई जांच नहीं की तथा पीडीए को पीपीपी साझेदार की नियुक्ति हेतु निविदा प्रक्रिया करने के लिए आदेश दिया।

पूर्व-निविदा बैठक (जनवरी 2014) में निविदाकारों के डीटीटीडीसी को यह बताने पर, कि डब्ल्यूसीआरसी के निर्माण के लिए भूमि उपयोग में बदलाव आवश्यक होगा एवं इसको स्पष्ट करने के आवेदन के बाद, डीटीटीडीसी ने डीडीए से स्पष्टीकरण मांगा (फरवरी 2014)। डीडीए ने स्पष्ट किया (अप्रैल 2014) कि डब्ल्यूसीआरसी का निर्माण डीएमपी-2021 के अंतर्गत अनुमत नहीं है तथा भूमि उपयोग के बदलाव के लिए रिज प्रबंधन बोर्ड तथा भारतीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय सशक्त समिति से अनापत्ति प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा। डीटीटीडीसी ने भूमि उपयोग के बदलाव की अनुमति नहीं मांगी तथा पीडीए के साथ अनुबंध को रोक दिया (अक्टूबर 2015) तथा डब्ल्यूसीआरसी के निर्माण का प्रस्ताव भी छोड़ दिया (जून 2016)। इस प्रकार, पीडीए को परामर्श के लिए प्रदत्त ₹ 15.19 लाख तथा निविदा विज्ञापन के लिए ₹ 8 लाख व्यर्थ व्यय हो गया। इसके अतिरिक्त डीटीटीडीसी ने ₹ 1.79 करोड़²⁹ की अवरुद्ध निधियों पर ₹ 1.27 करोड़³⁰ (जुलाई 2017 तक) की ब्याज की हानि को वहन किया जिस पर कोई अनुकूल राजस्व अर्जन व्यापार योजना में परिकल्पित नहीं था।

प्रबंधन ने कहा (मई 2017) कि सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा भूमि को अब सांकेतिक संरचना के साथ बड़े समारोह करने के लिए विकसित किया जाएगा तथा उसके लिए इसने 2016-17 में ₹ 36.59 लाख की योजना निधियाँ प्राप्त की हैं। भूमि के चारों ओर चारदीवारी पहले ही बना दी गई है तथा इसको विकसित करने हेतु एक वास्तुशिल्प सलाहकार नियुक्त किया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीटीटीडीसी ने पहले पाँच वर्षों के दौरान (2005-2010) भूमि के विकास हेतु कोई कार्रवाई नहीं की, तथा इसका तदंतर विलम्ब तथा व्यर्थ व्यय परिहार्य था यदि वे डब्ल्यूसीआरसी परियोजना को आरंभ करने से पहले भूमि उपयोग की अनुज्ञेयता की जाँच कर लेते।

इस प्रकार, डीटीटीडीसी की ओर से यथोचित कर्मठता तथा योजना की अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप भूमि को कथित उपयोग हेतु विकसित करने में 12 वर्ष का परिहार्य विलंब तथा ₹ 23.19 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, भूमि में निवेश की व्यर्थता होने का अभिप्राय है डीटीटीडीसी को ₹ 1.79 करोड़ की अवरुद्ध निधियों पर ₹ 1.27 करोड़ (जुलाई 2017 तक) की ब्याज की हानि को वहन करना पड़ा जिस पर कोई अनुकूल राजस्व अर्जन व्यापार योजना में परिकल्पित नहीं था।

मामला सरकार को भेजा गया (अगस्त 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

²⁹ उस ब्याज की दर पर गणना की गई जो डीटीटीडीसी 2005-06 से 2016-17 की अवधि के दौरान 6.25 से 8 प्रतिशत के बीच में अपने अतिरिक्त निवेश पर अर्जित कर रहा था।

³⁰ ₹1.38 करोड़ की भूमि लागत तथा 12 वर्ष के लिए ₹ 0.41 करोड़ का भूमि किराया।

परिवहन विभाग

दिल्ली परिवहन निगम

2.8 वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार से नुकसान की गैर-वसूली

ठेका प्रबंधन में कमी एवं प्रबंधन द्वारा देरी से की गई कार्रवाई के कारण डीटीसी टाटा मोटर्स लिमिटेड से 17 बसों के घाटे जिनका घटा हुआ मूल्य ₹ 5.86 करोड़ था, के जलने से हुए घाटे को वसूल नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, 17 बसों की अनुपलब्धता के कारण डीटीसी को अंशदान का वार्षिक नुकसान ₹ 1.13 करोड़ तथा जून 2017 तक कुल ₹ 2.82 करोड़ का नुकसान हुआ। 2682 बसों के लिए बीमा नहीं कराने का मतलब है टाटा मोटर्स लिमिटेड को बीमा की लागत के बराबर का अनुचित लाभ देना

मैं. टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बीच हस्ताक्षरित एक ठेका (अक्टूबर 2008) के तहत टीएमएल ने 2007-11 के दौरान पूरी तरह से निर्मित निम्न तल वाली 2682 बसों की आपूर्ति हेतु 92 प्रतिशत बसों की सम्पूर्ण समय संचालन हेतु उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए वारंटी अवधि से परे 7,50,000 किमी तक वार्षिक अनुरक्षण के उत्तरदायित्व के साथ किया। प्रचलन के अनुसार डीटीसी अपने बेड़े के लिए केवल तीसरे पक्ष का बीमा कवर लेता है जो किसी तीसरे पक्ष के नुकसान को कवर करने के लिए सार्वजनिक स्थानों में अपने बेड़े के उपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिम/देयता को कम करता है लेकिन मोटर वाहन को हुए नुकसान को कवर नहीं करता। जबकि मोटरवाहन के नुकसान से रक्षा के लिए जब बसें अनुरक्षण के लिए डिपो में अनुरक्षण ठेकेदार की अभिरक्षा में रहती हैं, टीएमएल के साथ किए वार्षिक अनुरक्षण ठेके (एएमसी) के खंड 46.20 के अनुसार कि टीएमएल अपनी अभिरक्षा में रखी बसों के अनुरक्षण के लिए समुचित बीमा कवर लेगा, जिसमें एएमसी के दौरान अनुरक्षण के लिए डिपो में खड़ी बसें शामिल होंगी जो बसों को हुए नुकसान (आग सहित) के कारण डीटीसी को किसी नुकसान से बचा सके।

इन बसों में से ₹ 10.34 करोड़ के कीमत की सत्रह बसें 1 जनवरी 2015 को डीटीसी के अम्बेडकर नगर डिपो में लगी आग में जल गई। दिल्ली सरकार द्वारा गठित (जनवरी 2015) एक उच्चस्तरीय समिति³¹ (एचपीसी) ने निष्कर्ष निकाला (जुलाई 2015) कि आग की वजह कोई बदनीयत नहीं थी तथा आग

³¹ इसकी अध्यक्षता उपायुक्त (दक्षिण) द्वारा की गई और समिति के दो अन्य सदस्य थे संयुक्त आयुक्त (परिवहन) एवं उप मुख्य महाप्रबंधक (यांत्रिक) दि.प.नि.।

लगने की सटीक वजह का पता नहीं चला। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है:

1. एएमसी के तहत बसों का अनुरक्षण/देख-रेख डीटीसी डिपो में होना था तथा टीएमएल की एएमसी सुविधाएं डीटीसी डिपो में उस स्थान पर सह-स्थित होनी थी जो डीटीसी द्वारा टीएमएल के कार्य फोर्स, स्पेयर्स, प्लांट, मशीनरी, टूल्स इत्यादि के लिए उपलब्ध कराया गया था। टीएमएल कर्मियों को दैनिक/नियमित रूप से³² प्रत्येक बस के निर्धारित प्रस्थान से पहले डिपो में बसों की जांच तथा निवारक अनुरक्षण करना था। एएमसी के इन प्रावधानों का सामूहिक अर्थ है कि डिपो के भीतर बसें टीएमएल के प्रभावकारी अभिरक्षण में रहेंगी जब तक कि बसें संचालन हेतु तैयार स्थिति में डिपो से निकल न जाए। एचपीसी के प्रतिवेदन की जांच के लिए डीटीसी द्वारा गठित (अप्रैल 2016) समिति ने भी निष्कर्ष निकाला (मई 2016) कि जब आग लगी तब बसें टीएमएल के अभिरक्षण में थी।
2. लेखापरीक्षा में पाया गया कि एएमसी के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी डीटीसी के प्राधिकारी ने सुनिश्चित नहीं किया कि टीएमएल ने 2682 निम्न तल बसों में से किसी का भी टीएमएल के साथ अनुरक्षण ठेका के दौरान आवश्यक बीमा कवर लिया था। इस घटना के बाद भी टीएमएल ने बीमा कवर नहीं लिया है, जिससे डीटीसी ऐसी घटनाओं में होने वाली नुकसान को सहन करने वाला बन गया है, और डीटीसी द्वारा इस संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, बसों के लिए बीमा कवर की लागत जो टीएमएल ने एएमसी का मूल्य उद्धरण करते समय घटक रखी होगी और 2682 बसों के लिए बीमा कवर लेने को सुनिश्चित न करके डीटीसी ने टीएमएल को बीमा कवर के कीमत जिसे टीएमएल ने बचाया होगा, के बराबर अनुचित लाभ दिया।
3. इस मामले में प्रशासनिक विलम्ब था तथा डीटीसी के तरफ से इस पर ध्यान देने में निष्क्रियता थी। एचपीसी का प्रतिवेदन जुलाई 2015 में उपलब्ध था परन्तु डीटीसी ने आगे की कार्रवाई करने के लिए अप्रैल 2016 तक दिल्ली सरकार से प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करने में नौ

³² डीटीसी के इस्तेमाल के लिए टीएमएल द्वारा सुबह की पाली के लिए (पैराग्राफ 46.5 को पैराग्राफ 46.24 के साथ पढ़ा जाए)। बस उपलब्ध कराने का अधिकतम समय था सुबह 8.00 बजे। डीटीसी को डिपो के सभी बसों की भौतिक स्थिति, फिटिंग इत्यादि का निरीक्षण करना था तथा टीएमएल को किसी भी चूक या गुम वस्तुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना था (पैराग्राफ 46.30)। डीटीसी डिपो में बसों को केवल टीएमएल कर्मियों द्वारा ही संचालित/नियंत्रित किया जाना था (पैराग्राफ 46.32)।

महीने लगा दिए। यद्यपि, डीटीसी एएमसी के पैराग्राफ 46.20 के अधीन टीएमएल को डिपो में बसों का संरक्षक मानता है और जली हुई बसों के मरम्मत करने के लिए वही जिम्मेदार था, यह बसों के गैर-मरम्मत के लिए टीएमएल के विरुद्ध एएमसी के खंड 46.7 (i)³³ के अनुसार कार्रवाई करने में असफल रहा, इसके बजाय यह टीएमसी से जली हुई बसों के मरम्मत के लिए आग्रह³⁴ करता रहा। फलस्वरूप, आग लगने की घटना से ढाई वर्ष (जनवरी 2015 से जून 2017) के अन्तराल के बाद भी टीएमएल से जली हुई बसों की मरम्मत नहीं करवाई जा सकी।

4. टीएमएल ने डिप्टी कमिश्नर (दक्षिण) की अध्यक्षता वाली एच पी सी के प्रतिवेदन के अभाव में मरम्मत करने या नुकसान की पूर्ति करने से इन्कार कर दिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि टीएमएल के लगातार मांग करने के बावजूद डीटीसी ने अक्टूबर 2017 में जांच प्रतिवेदन की प्रति टीएमएल को भेजी।

प्रबंधन ने कहा (जून 2017) कि उसने टीएमएल को बीमा पॉलिसी का विवरण जो उनके द्वारा लिया गया है प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजा है परन्तु उनका उत्तर प्रतीक्षित है। क्षति के कारण किसी भी हानि को टीएमएल द्वारा वहन किया जाएगा। आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि डीटीसी ने आग लगने की घटना के बाद बीमा कवर के अस्तित्व के बारे में पूछा, जिसे वे अपने हित की रक्षा के लिए अक्टूबर 2008 में ठेका पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद सुनिश्चित कर सकते थे। डीटीसी अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के दौरान अर्थात् आग की घटना के बाद टीएमएल को किए गए ₹ 346.26 करोड़ के एएमसी भुगतान में से भी अपनी हानि की वसूली करने में विफल रहा और जली हुई सभी 17 बसें ढाई से अधिक वर्षों तक बेमरम्मत पड़ी रही।

ठेका प्रबंधन में अपर्याप्तता के कारण एवं देरी से की गई कार्रवाई जिसके लिए डीटीसी प्रबंधन उत्तरदायी था, डीटीसी टीएमएल से 17 बसों, जिनका घटा हुआ मूल्य ₹ 5.86 करोड़ था, के जलने से हुए घाटे को वसूल नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, 17 बसों की अनुपलब्धता के कारण डीटीसी को

³³ खंड 46.7 (i) - त्रुटि/यांत्रिक विफलता/बस की आग के कारणों से दुर्घटनाओं की वजह से मरम्मत करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। दुर्घटना का कारण जैसे त्रुटि/यांत्रिकी विफलता या अन्य के संबंध में खरीददार का निर्णय अंतिम होगा।

³⁴ 25 मई, 5 अगस्त, 11 सितम्बर, 16 सितम्बर 2015, 29 जनवरी, 29 फरवरी, 27 दिसम्बर 2016

अंशदान³⁵ का वार्षिक नुकसान ₹ 1.13 करोड़³⁶ तथा जून 2017 तक कुल ₹ 2.82 करोड़ का नुकसान हुआ। 2682 बसों के लिए बीमा नहीं कराने का मतलब है टाटा मोटर्स लिमिटेड को बीमा की लागत के बराबर का अनुचित लाभ देना।

मामला सरकार को भेजा गया (जुलाई 2017), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

2.9 बिजली प्रभार का परिहार्य भुगतान

कार्यकारी एजेंसी अपर्याप्त नियोजन से जुड़े द्वारका-VIII बस डिपो के विकास हेतु सौंपे गए डिपोजिट वर्क की प्रगति की निगरानी करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.72 लाख के बिजली प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

परिवहन विभाग (प.वि.), रा.रा.क्षे.दि.स. ने जुलाई 2007 में राष्ट्रमण्डल खेल (सीडब्ल्यूजी) - 2010 के दौरान बसों की पार्किंग हेतु डीटीसी के लिए कुल ₹ 6.73 करोड़ में बस डिपो के निर्माण की स्वीकृति दी जिसे बाद में संशोधित कर ₹ 9.31 करोड़ कर दिया गया। डीटीसी ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को अगस्त 2007 में डिपोजिट वर्क के तौर पर काम सौंपा। कार्य में लोक निर्माण तथा बस डिपो में बिजली के सब स्टेशन (इएसएस) को 18 महीनों के भीतर स्थापित करना शामिल है।

पीडब्ल्यूडी ने अक्टूबर 2009 में डिपो के सिविल निर्माण कार्य पूरा किया। इएसएस का कार्य बाद में (अक्टूबर 2009) पीडब्ल्यूडी द्वारा सौंपा गया जो जुलाई 2017 तक पूरा नहीं हुआ। चूँकि इएसएस का कार्यान्वयन समय से पूरा नहीं हो सका, डीटीसी को डिपो के लिए इसे समय पर परिचालन करने हेतु जुलाई 2009 में अस्थायी बिजली कनेक्शन सीडब्ल्यूजी कार्यक्रम के लिए लेना पड़ा। आगे, डीटीसी जुलाई 2017 तक अस्थायी कनेक्शन पर डिपो का संचालन करता रहा था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.72 लाख (93 महीनों के लिए) के बिजली प्रभार का अतिरिक्त भुगतान हुआ क्योंकि बिजली वितरण कंपनियों ने सामान्य टैरिफ दर से बढ़कर अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए

³⁵ राजस्व प्रति किलोमीटर कम परिवर्तनीय लागत प्रति किलोमीटर

³⁶ बसों की संख्या: 17 x औसतन 188 कि.मी. प्रति बस प्रति दिन x ₹ 9.675 का अंशदान प्रति कि.मी. एसी लो फ्लोर बसों के लिए x दिन 01.01.2015 से 30.06.2017 तक जो कि ₹ 1.13 करोड़ सालाना और ₹ 2.82 करोड़ द्वाँ वर्षों के लिए। (अंशदान स्रोत - 2015-16 (वास्तविक) और 2016-17 (अंतिम) के लिए डीटीसी के भौतिक और वित्तीय परिणाम)।

30 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया। द्वारका-VIII बस डिपो में अस्थायी बिजली कनेक्शन का उपयोग प्रतिमाह ₹ एक लाख की परिहार्य आवर्ती लागत से जारी रहा।

डीटीसी द्वारा किए गए ₹ 50.72 लाख का कुल अतिरिक्त व्यय निम्नलिखित कारणों से परिहार्य था।

- 1) डीटीसी ने लोक निर्माण चरण के दौरान ऐसे महत्वपूर्ण कार्य की प्रगति की निगरानी नहीं की और नतीजतन वे इस तथ्य से चूक गए कि कार्यकारी एजेंसी बस डिपो के समय से अर्थात् डिपोजिट कार्य के सौंपे जाने की तिथि से 18 महीने में पूर्ण करने को सुनिश्चित करने के लिए अनुबंधित किए गए सिविल और इलेक्ट्रीकल कार्य को सिंक्रनाइज नहीं किया।
- 2) डीटीसी ने इएसएस के लिए कार्य की व्यापकता का निर्धारण करते समय अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली वितरण कंपनी को शामिल नहीं किया। इएसएस सुविधा के निर्माण के दौरान बिजली आपूर्ति विनिर्देशों और मानकों के अनुसार संशोधन किया जाना था। जिससे इसकी तत्परता में आगे देरी हुई।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2017) कि डीटीसी ने इएसएस का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए मामले का कार्यकारी एजेंसी के साथ नियमित रूप से अनुसरण किया। तथापि, पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार से उनके विवाद के कारण इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बिल्डिंग में अभी तक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन उपकरण नहीं लगाया है तथा द्वारका-VIII अभी तक अस्थायी कनेक्शन से चल रहा है। अस्थायी बिजली कनेक्शन के कारण डिस्कॉम को चुकाई गयी अतिरिक्त रकम की गणना की गई है जो द्वारका डिपो- VIII के लिए ₹ 48.84 लाख (मई 2017) है। एजेंसियों की ओर से देरी होने के कारण डीटीसी हानि नहीं उठाएगा और इसने पीडब्ल्यूडी से वसूली शुरू कर दिया है। जवाब मान्य नहीं है और इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि वे जनवरी 2009 तक काम की प्रगति का पता लगाने में विफल रहे जब उनको एहसास हुआ कि इएसएस कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। डीटीसी ने डिपोजिट वर्क अनुबंधित करने के लिए कोई औपचारिक समझौता नहीं किया था जिसके तहत वे क्षतिपूर्ति या कार्यकारी एजेंसी की ओर से देरी होने के कारण डीटीसी द्वारा उठाए गए बिजली प्रभार के अतिरिक्त बोझ की वसूली कर सके।

इस तरह, द्वारका - VIII बस डिपो के विकास हेतु कार्यकारी एजेंसी को सौंपे गए डिपोजिट कार्य की निगरानी में विफलता के साथ-साथ अपर्याप्त योजना के परिणामस्वरूप ₹ 50.72 लाख के बिजली प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

पावर विभाग

2.10 दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा

2.10.1 प्रस्तावना

2.10.1.1 दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के संचालन की मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावकारिता का आकलन करने हेतु संगठन के क्रियाकलापों को शामिल करते हुए 2007-08 से 2011-12 की अवधि में निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी तथा इसे मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किया गया- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (वर्ष 2013 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1)। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल में 2 अप्रैल 2013 को प्रस्तुत किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया:

- अपूर्ण योजना एवं परियोजना प्रबंधन के कारण वृहद परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी;
- क्रियाकलापों के सिंक्रनाइजेशन की कमी;
- क्षमता अनुवृद्धि के लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति;
- निर्णय लेने में देरी, अविवेकपूर्ण निर्णय तथा सब-स्टेशनों एवं लाईनों के अनुरक्षण एवं संचालन को प्रभावित करने वाला अनुबंध;
- आपदा की अपर्याप्त तैयारी; तथा
- सामग्री एवं इनवेन्टरी की खरीद में कमियां।

निष्पादन लेखापरीक्षा में पांच सिफारिशें तथा 48 अभ्युक्तियाँ थी जिनमें से 34 कार्रवाई योग्य थी।

2.10.1.2 अब कार्रवाई योग्य इन 34 अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता का आकलन करने हेतु अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई जिसके परिणामों की चर्चा नीचे की गई है। सिफारिशों एवं संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति को तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है- 'निरर्थकता' अथवा 'प्रगति नहीं', 'आंशिक कार्यान्वयन' एवं 'पूर्ण कार्यान्वयन'।

सरकारी उपक्रमों की समिति द्वारा जून 2017 तक निष्पादन लेखापरीक्षा पर कोई चर्चा नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा प्राप्ति

2.10.2 लेखापरीक्षा सिफारिशों/अभ्युक्तियों का कार्यान्वयन

पांच सिफारिशों के अंतर्गत 34 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों जिन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किए गए, के क्रियान्वयन की श्रेणीवार स्थिति नीचे दिए गए हैं:

क) निरर्थकता अथवा प्रगति नहीं

पूर्व लेखापरीक्षा में दी गई अभ्युक्तियों के सार	की गई सिफारिश	कंपनी द्वारा दी गई सूचना की वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा प्राप्ति/टिप्पणियां
1. 220 केवी गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस) के आयात पर गैर- उद्ग्रहणीय प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) के भुगतान की वजह से सीमा शुल्क के अतिरिक्त भुगतान के कारण ₹ 16.91 करोड़ की हानि हुई। (पैरा सं. 7.7.7.1)	ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब-स्टेशनों की परियोजनाएँ उपकरण एवं निधियों की निष्क्रियता को दूर करने के लिए सिंक्रनाइज की जाती हैं।	डीटीएल ने कहा कि सीवीडी के छूट के संबंध में नियम मौन थे; इसने 2012 के बाद ऐसे किसी उपकरण का आयात नहीं किया है; तथा जब कभी ऐसे उपकरण का आयात होगा विशेषज्ञ की सलाह ली जाएगी और कस्टम विभाग से संपर्क किया जाएगा।	डीटीएल ने 2012 के बाद ऐसे किसी उपकरण का आयात नहीं किया है।
2. डीटीएल के 220 केवी लाईनों के लिए पॉलीमर इन्सुलेटर्स की गैर-खरीद के परिणामस्वरूप ग्रिड में गड़बड़ी हुई तथा चीनी मिट्टी की एन्टी फॉग इन्सुलेटर्स की अनुचित खरीद में ₹ 0.23 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। (पैरा सं. 7.8.5.3)	ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए लाइनों तथा सबस्टेशनों की सुरक्षा हेतु तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल का संस्थापन।	डीटीएल ने कहा कि 220 केवी ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए पॉलीमर इन्सुलेटर की खरीद प्रक्रियाधीन है।	जून 2017 में पॉलीमर इन्सुलेटर की आपूर्ति हेतु खरीद आदेश जारी किया जा चुका है परन्तु इसे खड़ा करने, जांच करने तथा चालू करने (इटीसी) के आदेश अभी तक प्रक्रियाधीन है परिणामस्वरूप चीनी मिट्टी का इन्सुलेटर पॉलीमर से प्रतिस्थापित नहीं हुआ है।
बड़ी संख्या में ट्रिपिंग जो जनवरी 2010, दिसम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 में संज्ञान में आयी, को नियंत्रित करने के लिए फरवरी 2012 में पॉलीमर इन्सुलेटर खरीदने तथा 220 केवी ट्रांसमिशन लाईनों पर चीनी मिट्टी के इन्सुलेटर प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया।			

<p>लेखापरीक्षा में देखा गया कि ये 2012 तक उत्तरी क्षेत्रीय पावर समिति (एन.आर.पी.सी)/ केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए) के निर्देशानुसार क्रय नहीं किए गए।</p> <p>3. पीजीसीआईएल को डीटीएल के 400 केवी ट्रांसमिशन लाईनों के लिए पॉलीमर इन्सुलेटर की खरीद में परामर्श शुल्क के प्रति ₹ 1.11 करोड़ का परिहार्य व्यय का भुगतान किया गया। (पैरा सं. 7.8.5.4)</p> <p>उत्तरी क्षेत्र में धुंध भरी परिस्थिति में ट्रिपिंग की बड़ी संख्या को नियंत्रित करने के लिए 2008 में पॉलीमर इन्सुलेटर को खरीदने तथा 400 केवी ट्रांसमिशन लाईनों पर वर्तमान चीनी मिट्टी के इन्सुलेटर को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य के लिए, डीटीएल ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (पीजीसीआईएल) के माध्यम से 2008-09 में परामर्श शुल्क (₹ 1.11 करोड़) चुका कर पॉलीमर इन्सुलेटर खरीदा जिसकी जरूरत नहीं थी जबकि डीटीएल के पास सम्पूर्ण मैटेरियल मैनेजमेंट और स्टोर डिविजन था।</p>			<p>कंपनी ने 2012 के बाद पीजीसीआईएल से कोई सामग्री नहीं खरीदी है, परन्तु एनआईटी निकालने तथा पॉलीमर इन्सुलेटर खरीदने हेतु क्रय आदेश देने में विलम्ब हुआ था जैसा कि ऊपर कहा गया है।</p>
<p>4. अनिर्धारित विनिमय शुल्क (पैरा सं. 7.9.5)</p> <p>ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति में अंतर वास्तविक उत्पादन या वास्तविक आहरण तथा निर्धारित उत्पादन या निर्धारित आहरण के बीच की ओर ले जाता है जिसका लेखा अनिर्धारित विनिमय शुल्क (यूआई) के माध्यम से होता है जिसे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) ने प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लॉक में किया। यूआई शुल्क की उगाही कम आवृत्ति की स्थिति में कम प्रविष्टि या अधिक आहरण को रोकने के लिए एक वाणिज्यिक</p>	<p>ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/ शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल का संस्थापन।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि यूआई राशि का संग्रहण एवं संवितरण हेतु एसएलडीसी एक मात्र नोडल एजेंसी है। यूआई पूल अकाउंट में उपलब्ध अधिशेष राशि की उपयोगिता का निर्णय दिल्ली बिजली विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा किया जाना है। एसएलडीसी ने डीईआरसी से संपर्क किया है, परन्तु उनका निर्णय प्रतीक्षित है।</p>	<p>यूआई पूल अकाउंट में उपलब्ध निधि का उपयोग व्यवस्था सुधार हेतु किसी स्कीम में उपयोग नहीं हुआ जबकि शेष राशि बढ़कर ₹ 453.24 करोड़ (मार्च 2017) हो चुकी है। आगे, डीटीएल ने अगस्त 2013 के बाद डीईआरसी से दिल्ली में रणनीतिक महत्त्व के आगामी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट</p>

<p>निवारक की तरह कार्य करता है। संग्रहित किया गया यूआई शुल्क यूआई पूल अकाउण्ट फण्ड में जमा किया जाता है। लेखापरीक्षा ने बताया कि 31 मार्च 2012 को पूल अकाउण्ट फण्ड में ₹ 165 करोड़ शेष पड़े थे जिसका व्यवस्था सुधार हेतु किसी स्कीम में उपयोग नहीं किया गया इत्यादि।</p>			<p>हेतु उपलब्ध निधि की स्वीकृति लेने हेतु (सिवाय अक्टूबर 2017 में लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दा उठाये जाने के पश्चात) कोई पहल नहीं की।</p>
<p>5. ट्रेफिक निर्धारण (पैरा सं. 7.10.3)</p> <p>डीटीएल ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) पर डीइआरसी द्वारा वास्तविक मंजूरी से अधिक व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप ओ एण्ड एम व्यय का ₹ 22.43 करोड़ तक कम प्राप्त हुआ जिसका वहन कंपनी द्वारा अपने स्रोत से किया गया और इन व्ययों को कम करने की जरूरत थी।</p>	<p>उधार निधि पर निर्भरता को कम करने के लिए व्यय की कटौती तथा डिस्कॉम से बकाया की वसूली करना।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि इस मुद्दे को बिजली के अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीई) में 2011 में चुनौती दी गई थी, हालांकि एटीई ने 2013 में डीईआरसी के निर्णय को बरकरार रखा।</p>	<p>डीटीएल ने 2012-13 एवं 2016-17 के बीच अपने ओ एण्ड एम खर्च को नियंत्रित नहीं किया तथा इस अवधि में डीइआरसी द्वारा मंजूर किए गए व्यय से अधिक ₹ 27.77 करोड़ खर्च किया जिसे कम्पनी को अपने स्रोतों से वहन करना पड़ा। डीइआरसी के निर्णय को 2013 में एटीई द्वारा बरकरार रखने के बाद भी कंपनी ने इन खर्चों में कटौती करने का प्रयास नहीं किया।</p>
<p>6. निविदाओं के निर्धारण में देरी (पैरा सं. 7.11.2.1)</p> <p>निविदा निकालने की तिथि से अनुबंध निर्धारण में उल्लेखनीय देरी था। कंपनी ने डीटीएल क्रय नीति में मंजूर किए गए पांच महीनों की समयावधि की जाये के विरुद्ध एनआईटी निकालने की तिथि से छः से 19 महीने लिए।</p>	<p>ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब स्टेशनों की परियोजनाओं का सिंक्रनाइज सुनिश्चित करने के लिए डीटीएल कदम उठाने पर विचार करें जिससे कि उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि निविदाओं के निर्धारण में समय को कम करने का प्रयास किया जा चुका है।</p>	<p>2012 के बाद परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ क्योंकि मैटीरियल मैनेजमेन्ट डिवीजन ने 2015-16 से 2016-17 के दौरान मांग पत्र प्राप्त होने के बाद ट्रांस-मिशन लाईनों तथा सब-स्टेशन स्कीम के संबंध में 15 क्रय आदेश की नौ से 32 महीनों में तथा अन्य सामग्री मर्दों के संबंध में 70 क्रय आदेश पांच से 11 महीनों में निर्धारित और प्रदान किए।</p>

<p>7. क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर के निपटान में देरी के कारण ₹ 2.54 करोड़ की हानि (पैरा सं. 7.11.2.2)</p> <p>डीटीएल ट्रांसफॉर्मर को रद्दी माल के रूप में घोषित करने का अनुसरण करता रहा है, यदि एक बार इसे मरम्मत से परे घोषित कर दिया गया। इसके बाद स्क्रेप डिस्पोज़ल समिति क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर का आरक्षित मूल्य निर्धारित करता है तब ई-निलामी के माध्यम से बेचा जाता है। लेखापरीक्षा ने बताया कि इन ट्रांसफॉर्मरों को निर्धारित समय सीमा के अभाव में छः महीने की उचित समयावधि पर विचार करने के बाद देरी (80 महीने तक) से निपटान किया। इसके परिणामस्वरूप अवरुद्ध निधि पर ₹ 2.54 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।</p>	<p>ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब स्टेशनों की परियोजनाओं का सिंक्रनाइज सुनिश्चित करने के लिए डीटीएल कदम उठाने पर विचार करें जिससे कि उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि काफी देरी हुई परन्तु निपटान प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद देरी को कम किया गया है। यदि एक बार रद्दी निपटान नीति मंजूर हो जाती है निपटान प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाएगी।</p>	<p>सितम्बर 2017 में रद्दी निपटान नीति मंजूर हो चुकी है, फिर भी, समयावधि जिसके दौरान रद्दी सामग्री का निपटान किया जाना था, जिसे अब तक कथित नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। रद्दी सामग्री निपटान में देरी को 2016 के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन में दर्शाया गया। इसके बाद भी एक ट्रांसफॉर्मर का 2016-17 में 26 महीनों की देरी से निपटान (₹ 1.23 करोड़) किया गया।</p>
<p>8. ट्रांसफॉर्मरों में स्थापित करने के लिए नाइट्रोजन, इंजेक्शन फायर प्रीवेंशन -कम-एक्सटिंग्युसिंग सिस्टम (एनआईएफपीडिएएस) के खरीद में देरी (पैरा सं. 7.11.2.7)</p> <p>डीटीएल ने 220 केवी सब-स्टेशन पर 100 एमवीए ट्रांसफॉर्मर के लिए 64 एनआईएफपीडिएएस की आपूर्ति, संस्थापन तथा चालू करने हेतु फरवरी 2010 में आमंत्रित किए गए एनआईटी के विरुद्ध एक क्रय आदेश दिसम्बर 2010 में एम/एस एसइआरजीआई को जारी किया। एक दूसरे निर्माता ने एम/एस एसइआरजीआई के विरुद्ध मुकदमा दायर किया और एम/एस एसइआरजीआई को एनआईएफपीडिएएस डीटीएल को बेचने से रोकने के अदालत के आदेश फरवरी 2010 में प्राप्त</p>	<p>डीटीएल आपदा प्रबंधन हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय एवं अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पर विचार करें।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि एम/एस एसइआरजीआई के विरुद्ध मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में उप न्यायिक है तथा एनआईएफपीडिएएस अब तक खरीदा नहीं गया।</p>	<p>डीटीएल ने आग को रोकने के लिए सीडए के दिशानिर्देश के अनुसार 100 एमवीए के ट्रांसफॉर्मर के साथ स्थापित करने के लिए अब तक एनआईएफपीडिएएस नहीं खरीदा है।</p>

किया। डीटीएल इस तथ्य से अवगत था, परन्तु, तब भी एसइआरजीआई को क्रय आदेश दिया, परिणामस्वरूप एनआईएफपीइएस अभी तक खरीदा और स्थापित किया नहीं जा सका जो सीइए के दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक था।			
---	--	--	--

ख) आंशिक कार्यान्वयन

पूर्व लेखापरीक्षा में दी गई अभ्युक्तियों के सार	की गई सिफारिश	कंपनी द्वारा दी गई सूचना की वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा प्राप्ति/टिप्पणी
<p>1. ट्रांसमिशन नेटवर्क और इसका विकास (पैरा सं. 7.7.2)</p> <p>डीटीएल ने 255.01 सीकेएम की लाईनों और 7420 एमवीए के ट्रांसमिशन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया जिसके प्रति 2007-08 से 2011-12 के दौरान 87.75 सीकेएम की लाईनों और 2380 एमवीए की ट्रांसमिशन क्षमता को जोड़ा/बढ़ाया गया।</p> <p>2. ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रबंधन की परियोजना (पैरा सं. 7.7.3 और 7.7.4)</p> <p>पूरा करने के निर्धारित मानदण्ड क्रमशः 28 माह और 24 माह के विरुद्ध प्रमुख ट्रांसमिशन लाईनों परियोजनाओं में 13 माह से 60 माह की तथा सब स्टेशन परियोजनाओं में 23 माह से 64 माह की देरी थी। आगे, 31 मार्च 2012 को अपूर्ण लाईनों परियोजनाएं और सब स्टेशन परियोजना क्रमशः 16 माह से 64 माह तथा 21 माह से 78 माह विलम्ब थी। विलम्ब के कारण थे:-</p>	<p>भा.स. के टास्क फोर्स की सिफारिशों और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर सीइए/ डीइआरसी के निर्देशों का अनुसरण किया जाना है।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि इसके योजनाओं/कार्यों के नियमन में न्यूनतम समय को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के नियमन, निविदा तथा कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया को काफी सुव्यवस्थित किया है।</p>	<p>2012 के बाद, डीटीएल ने 2012-13 एवं 2016-17 के बीच 9255 एमवीए ट्रांसमिशन क्षमता तथा 374.36 सीकेएम लाईनों के लक्ष्य के विरुद्ध क्रमशः 4610 एमवीए की ट्रांसमिशन क्षमता और 173.373 सीकेएम की लाईनों को जोड़ा (50 एवं 46)। इससे यह पता चलता है कि डीटीएल लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा। निर्माण की योजना/कार्य तथा ट्रांसमिशन लाईनों (पांच सं.) को चालू करने एवं सब-स्टेशनों (पांच सं.) जो 31 मार्च 2012 को कार्यान्वयन के अधीन थे सफलतापूर्वक पूरा किया गया तथा प्रवर्तन में लाया गया, यद्यपि सात माह से 34 माह का विलंब था। सब स्टेशन (लौधी रोड) आंशिक रूप से नवम्बर 2014 में चालू किया गया था जिसे 50 महीनों की देरी से जुलाई 2017 में पूर्ण रूप से पूरा करना निर्धारित था। तथापि, 2014-15 से शुरू की गई नई योजनाओं/ कार्यों के संबंध में, आंशिक सुधार है क्योंकि 15 सब स्टेशन प्रोजेक्ट (सब स्टेशनों की स्थापना के तीन और संवर्धन कार्य के 12) तथा सात केबल लिंक प्रोजेक्ट (लाईनों निर्माण कार्य के तीन</p>

<p>i) एनआईटी आमंत्रित करने में देरी, ii) बोली के मूल्यांकन तथा टर्नकी परियोजनाओं के प्रदान प्रक्रिया में लिया गया अतिरिक्त समय, iii) भूमि अधिग्रहण में देरी, iv) सिविल एजेंसियों से राईट ऑफ वे (आरओ डब्ल्यू) अनुमति की व्यवस्था में देरी।</p>			<p>तथा संवर्धन कार्य के चार) के संबंध में देरी को क्रमशः एक माह से 19 माह के बीच कम किया गया है। देरी होने के कारणों अर्थात् एनआईटी आमंत्रित करने तथा उसकी प्रक्रिया में निविदा तथा पीओ का प्रदान/कार्य आदेश और आरओडब्ल्यू की अनुमति इत्यादि यद्यपि अभी तक जारी है।</p>
<p>3. ट्रांसमिशन लाईनों और एसएस परियोजनाओं के गैर-सिंक्रनाइजेशन के कारण निधियों का अवरोध (पैरा सं. 7.7.6) नियोजन की कमी के परिणामस्वरूप उप-स्टेशनों और चार ट्रांसमिशन लाईनों के कार्यान्वयन के परस्पर संबद्ध परियोजना गतिविधि के गैर-सिंक्रनाइजेशन से ₹ 287.09 करोड़ की सीमा तक निधि अवरोध हुआ जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है: 4. लोनी रोड (हर्ष विहार) के ईस्ट में 400 केवी जीआईएस की स्थापना (पैरा सं. 7.7.6.1) 5. 220 केवी 1000 वर्ग मीमी यू/जी एक्सएलपीई केबल का शालीमार बाग सब-स्टेशन से प्रस्तावित वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र सब-स्टेशन का लिंक (₹ 24.78 करोड़) (पैरा सं. 7.7.6.3)</p>	<p>ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब स्टेशनों की परियोजनाओं का सिंक्रनाइज सुनिश्चित करने के लिए डीटीएल कदम उठाने पर विचार करें जिससे कि उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि इसने भविष्य की परियोजनाओं के लिए भूमि की व्यवस्था के साथ ही कार्य को प्रदान करने में उचित सावधानी बरती है। डीटीएल ने कहा (जून 2017) कि इसने परस्पर संबद्ध परियोजनाओं के सिंक्रनाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए 2011 से योजनाओं के नियमन, निविदा तथा कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया को काफी सुव्यवस्थित किया है।</p>	<p>सब-स्टेशन सफलतापूर्वक पूरा तथा चालू हो चुका है, यद्यपि 18 माह का विलंब था। तथापि, 15 नये कार्य/योजनाएं 2014-15 से शुरू किए गए हैं और भूमि मामले के मुद्दे की वजह से कार्य प्रदान करने के पश्चात् कार्य रुका हुआ नहीं था। लिंक की गई परन्तु 14 महीनों की देरी के साथ (कुल 78 महीनों की देरी)। तथापि, 2014-15 से शुरू नयी योजनाओं/कार्यों में देरी को कम किया गया है। केवल बसंत कुंज और आर.के. पुरम के बीच ट्रांसमिशन लाईनों के निर्माण के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि लाईन</p>

<p>6. महारानी बाग सब स्टेशन और गाजीपुर सब स्टेशन के बीच 220 केवी भूमिगत सह भूमि के ऊपर ट्रांसमिशन लिंक (₹ 6.97 करोड़) (पैरा सं. 7.7.6.4)</p>		<p>डीटीएल ने कहा कि अनुमोदन प्राप्त करने में अवधि को कम करने के लिए इसने वन, आईएण्ड एफसीडी, पी एण्ड टी, सीइए इत्यादि जैसी एजेंसियों के साथ विभिन्न स्तर पर मुद्दे उठाए हैं। एलजी कार्यालय ने भी इन ट्रांसमिशन योजनाओं के लिए समर्पित कॉरिडोर की अनुपस्थिति में शीघ्र मंजूरी के लिए डीटीएल के साथ सहयोग करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं।</p>	<p>आंशिक रूप से उपयोग में हैं क्योंकि आर.के. पुरम में 220 केवी सब स्टेशन अब तक निर्माणधीन है।</p> <p>कथित लिंक पूरा और चालू किया गया परन्तु अपेक्षित पूर्णता तिथि (मार्च 2013) से 15 महीने की देरी के साथ। देरी के कारण कंपनी ने ₹ 52.72 लाख के मूल्य अंतर का परिहार्य भुगतान किया।</p>
<p>7. पीजीसीआईएल को परामर्श शुल्क के रूप में ₹ 7.97 करोड़ के परिहार्य व्यय का भुगतान (पैरा सं. 7.7.7.2)</p> <p>डीटीएल ने टर्नकी परियोजना के रूप में महारानी बाग सब-स्टेशन (अगस्त 2005) पर पीजीसीआईएल को आठ बे के निर्माण के कार्य को परामर्श शुल्क तथा 13.50 प्रतिशत सेवा चार्ज देकर आवंटित किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि डीटीएल स्वयं 2005-06 में समान तरह की परियोजना कार्य को टर्नकी आधार पर कर रहा था। पीजीसीआईएल को समान तरह के कार्य आवंटित करने के कारण ₹ 7.97 करोड़ के परामर्श शुल्क का परिहार्य व्यय हुआ।</p>	<p>भा.स. के टास्क फोर्स की सिफारिशों और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर सीइए/ डीइआरसी के निर्देशों का अनुसरण किया जाना है।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि यह आमतौर पर विभिन्न जीआईएस स्टेशनों के लिए स्वयं निविदाएं जारी करता है परन्तु कुछ मामलों में जहां निर्णय पावर मंत्रालय भा.स./सीइए के स्तर पर लिया जाता है वहां पीजीसीआईएल के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जाता है।</p>	<p>कैपिटल वर्क्स तथा ट्रांसमिशन प्रणाली को बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्देशित ट्रांसमिशन लाईनों, सब-स्टेशन और संबद्ध कार्य को छोड़कर डीटीएल ने 2012 के बाद स्वयं पीजीसीआईएल के माध्यम से कोई खरीद नहीं की है,</p>

<p>8. ट्रांसफॉर्मर की निष्पादन क्षमता (पैरा सं. 7.8.2.1)</p> <p>2007-08 से 2011-12 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान एक से चार ट्रांसफॉर्मर हर साल असफल हो गए थे, (13 ट्रांसफॉर्मर पांच वर्ष की अवधि के दौरान असफल हुए)।</p>	<p>डीटीएल ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/ शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल के संस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पर विचार करें।</p>	<p>डीटीएल ने कहा (जून 2017) कि विफलता दर को कम करने के लिए उपाय जैसे ट्रांसफॉर्मर की आवधिक आंतरिक जांच की जाती है। किए गए अन्य उपायों में आग के कारण नुकसान को रोकने के लिए नाईट्रोजन ईजेक्शन फायर प्रिवेंशन सह एक्सटींग्विशिंग सिस्टम (एनआईएफपीइएस) के साथ नये ट्रांसफॉर्मर की खरीद शामिल है। इसने यह भी कहा कि ट्रांसफॉर्मर का प्रारंभिक स्थापन, परीक्षण और चालू करने का कार्य मूल उपकरण निर्माता (ओइएम) द्वारा स्वयं किया जा रहा है।</p>	<p>ट्रांसफॉर्मर की विफलता दर में सुधार हुआ है क्योंकि 136 ट्रांसफॉर्मर में से 2012-13 और 2016-17 के बीच केवल नौ ट्रांसफॉर्मर असफल रहे, जिनमें से केवल सात सामान्य कार्यचालन जीवन काल में क्षतिग्रस्त हुआ।</p>
<p>9. वोल्टेज प्रबंधन (पैरा सं. 7.8.2.2)</p> <p>सीइए विनियमन के अनुसार, 400 केवी सब स्टेशनों के लिए 420 केवी और 380 केवी के बीच तथा 220 केवी सब-स्टेशनों के लिए 245 केवी और 198 केवी के बीच वोल्टेज को बनाये रखने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क की जरूरत है। यह देखा गया कि निर्धारित वोल्टेज स्तर को नहीं बनाए रखा गया जो उपभोक्ताओं के बिजली के उपकरणों को प्रभावित कर सकता है। मांग के अनुसार वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए और वोल्टेज को गिरावट से बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंकों/शन्ट रिएक्टरों को स्थापित करने की जरूरत है। आगे देखा</p>	<p>ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/ शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल का संस्थापन ।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि पीजीसीआईएल सीइए और अन्य स्टेक धारकों के परामर्श से आवश्यकता को समझा जा रहा है।</p>	<p>कंपनी ने 2012 के बाद वोल्टेज स्तर काफी सुधारने का प्रबंध किया क्योंकि 220 केवी एवं 400 केवी सबस्टेशनों पर अधिकतम और न्यूनतम वोल्टेज निर्धारित सीमा के भीतर था सिवाय 400 केवी सब स्टेशन में उच्च वोल्टेज के। सीपीआरआई द्वारा किए गए हालिया अध्ययन के अनुसार स्थापित कैपेसिटर बैंकों की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्षतिग्रस्त कैपेसिटर बैंक की स्थिति 7.98 प्रतिशत से सुधार कर 2016-17 में 2.15 प्रतिशत हो गई है जिससे आगे वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार लाने में मदद मिली है, तथापि, 400 केवी सबस्टेशनों पर शन्ट रिएक्टर अभी तक स्थापित नहीं हुआ है।</p>

<p>गया कि क्षति होने के कारण कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए (754.48 एमवीएआर की क्षमता का 7.98 प्रतिशत) की कमी थी और शन्ट रिएक्टरों को इसके ट्रांसमिशन सिस्टम में स्थापित नहीं किया गया।</p>			
<p>10. बस बार प्रोटेक्शन पैनल (बीबीपीपी) (पैरा सं. 7.8.2.3) बीबीपीपी पूरे पावर नेटवर्क पर बस बार गड़बड़ी के प्रभाव को सीमित करता है जो अनावश्यक ट्रिपिंग को रोकता है। ग्रिड मानदंडों के अनुसार, बीबीपीपी को सभी 220 केवी सब स्टेशन पर ग्रिड की गड़बड़ी के दौरान सिस्टम की स्थिरता बनाए रखने के लिए सेवा जारी रखना था और त्रुटि का तीव्र समायोजन करना था। लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि 28 सबस्टेशनों में से दो सबस्टेशनों में बीबीपीपी मुहैया नहीं कराए गए थे, दो सबस्टेशनों पर ये कार्य नहीं कर रहे थे तथा चार सब स्टेशनों पर ये अपने जीवन काल से 25 वर्ष से अधिक के हो गए थे। अतः बीबीपीपी के बिना तथा पुराने/अप्रचलित बीबीपीपी पर प्रणाली चलने का मतलब प्रणाली खतरे में थी।</p>	<p>ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/ शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल का संस्थापन ।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि 400 केवी और 220 केवी के विभिन्न सबस्टेशनों पर 26 बीबीपीपी आपूर्ति एवं इटीसी के लिए योजना स्वीकृत हो चुकी है तथा स्वचालन के लिए संख्यात्मक बीबीपीपी के साथ पुराने एवं अप्रचलित बीबीपीपी को बदलने के लिए निविदा शुरू की गई है।</p>	<p>आंशिक सुधार है क्योंकि 35 सबस्टेशनों में से एक सब स्टेशन पर बीबीपीपी स्थापित नहीं हुआ है, दो सबस्टेशनों पर ये कार्य नहीं कर रहे हैं, तीन सबस्टेशनों पर ये उपयोगी जीवन काल से अधिक के हो गए हैं। डीटीएल ने स्वचालन के लिए नए संख्यात्मक बीबीपीपी से पुराने बीबीपीपी बदलने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।</p>
<p>11. ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रबंधन (पैरा सं. 7.8.3) ट्रांसमिशन सिस्टम का नियमित और आवधिक रखरखाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तथा भारत</p>	<p>ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि 2013-14 से यह आन्तरिक थर्मोविजन स्कैनिंग के माध्यम से हॉट लाईनों का रखरखाव कर रहा है और रखरखाव हेतु अन्य सर्वोत्तम पद्धति जैसे सीबीएम; टेन डेल्टा;</p>	<p>आंशिक सुधार हुआ क्योंकि डीटीएल 2013-14 से कुछ अन्य तकनीकों से पृथक आंतरिक थर्मो विजन स्कैनिंग कर रहा है जिससे प्रणाली स्थिरता को सुधारने तथा ट्रांसमिशन (99 प्रतिशत) सिस्टम की उपलब्धता में</p>

<p>सरकार ने लाईनों के रखरखाव के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों के तहत कुछ तकनीकों का निर्धारण किया है। लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि डीटीएल के पास समिति द्वारा अनुमोदित अलग हॉटलाईनों मेन्टेनेंस डिविजन और ट्रांसमिशन की अन्य सर्वोत्तम पद्धतियाँ नहीं थी जैसे हॉट लाईनों पंचर, डिटेक्शन ऑफ इन्सुलेटर, पोर्टबल अर्थिंग हॉटलाईनों उपकरण के इस्तेमाल कर निवारक रखरखाव लाईनों वाशिंग, लाईनों का कंपन मापक इत्यादि जो डीटीएल में नहीं किया जा रहा था।</p>	<p>कैपेसिटर बैंक/ शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल का संस्थापन ।</p>	<p>डीजीए; डीसीआरएम; डीसीआरएम; वेट क्लिनिंग इत्यादि का अनुसरण कर रहा है। आगे कहा गया कि एनआरपीसी डीटीएल के 12 प्रमुख स्थानों पर प्रदूषण मैपिंग भी कर रहा है।</p>	<p>सहायता मिली परन्तु अभी तक निर्धारित तकनीकों में से कुछ जैसे पोर्टबल अर्थिंग हॉटलाईनों का इस्तेमाल करके निवारक रखरखाव एवं लाईनों का कंपन माप अपनाने की जरूरत है।</p>
<p>12. ग्रिड समन्वय समिति बैठक (पैरा सं. 7.9.4)</p> <p>दिल्ली ग्रिड कोड समन्वय समिति के नियम, 2008, के अनुसार ग्रिड समन्वय समिति बैठक (जीसीसी) कम से कम तीन महीने में एक बार किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि बैठकें नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर नहीं की गईं और लगभग 12 महीनों से 18 महीनों के अन्तराल के बाद आयोजित की गईं जिसके परिणामस्वरूप निरंतर पर्यवेक्षण/निगरानी और प्रणाली संबंधी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई विफल हो गया।</p>	<p>ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/ शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल का संस्थापन ।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि जीसीसी की बैठकें अब नियमित अन्तराल पर आयोजित की जा रही हैं।</p>	<p>डीटीएल ने वर्ष के आरंभ में एक बार के प्रति 2012-13 में तीन बैठकें, 2013-14 में दो बैठकें, 2014-15 में एक बैठक, 2015-16 में दो बैठकें और 2016-17 में तीन बैठकें आयोजित की।</p>
<p>13. समझौते के प्रावधानों के गैर अनुपालन के कारण निजी डिस्कॉम</p>	<p>व्यय में कटौती करना और उधार निधि पर निर्भरता</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि मामले को यह नियमित रूप से सीधे बीआरपीएल</p>	<p>बीआरपीएल और बीवाईपीएल से वसूली योग्य बकाया राशि 31 मार्च 2017 तक बढ़कर</p>

<p>(बीआरपीएल और बीवाईपीएल), को अनुचित लाभ पहुंचाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 700 करोड़ से अधिक की लंबित बकाया राशि की गैर वसूली हुई। (पैरा सं. 7.10.4)</p> <p>डीटीएल डिस्कॉम्स (बीआरपीएल, बीवाईपीएल, एनडीपीएल, एनडीएमसी और एमइएस) पर व्हीलिंग शुल्क और अन्य उद्ग्रहणों के लिए मासिक ट्रांसमिशन बिल तैयार करता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने उजागर किया कि बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल अक्टूबर 2010 से और उसके आगे भुगतान में नियमित नहीं थे तथा 31 मार्च 2012 तक ₹ 705.70 करोड़ (₹ 431.11 करोड़ बीआरपीएल से और ₹ 274.59 करोड़ बीवाईपीएल से) वसूली हेतु बकाया थे।</p>	<p>को कम करने के लिए डिस्कॉम से अपनी बकाया राशि की वसूली करना।</p>	<p>एवं बीवाईपीएल के साथ उठाता रहा है साथ ही रा.रा.क्षे.दि.स./डी.इ.आर.सी. के साथ भी। इसने एटीइ के समक्ष याचिका दायर की (जनवरी 2014) तथा डिस्कॉम्स के साथ कुछ अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस मुद्दे को भी उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया (2014)। मामला लंबित है और नियमित सुनवाई अभी भी चल रहा है।</p>	<p>₹ 2,269.97 करोड़ हो गया है (बीवाईपीएल से ₹ 900.40 करोड़ तथा बीआरपीएल से ₹ 1,369.57 करोड़) यद्यपि डीटीएल नियमित रूप से कोशिश कर रही है। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में भी विचाराधीन है।</p>
<p>14. भण्डारण का भौतिक सत्यापन (पैरा सं. 7.11.1)</p> <p>महरौली भण्डारण का भौतिक सत्यापन 2009-10 तक किया गया। आगे, डीटीएल ने रद्दी/ अप्रचलित सामग्री को पहचानने और निपटान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।</p>	<p>ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब-स्टेशनों की परियोजनाएं समकालिक बनाई जाये जिससे कि उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि महरौली भण्डारण का 2015-16 के लिए भौतिक सत्यापन कर लिया गया है जबकि 2016-17 तक यह प्रक्रियाधीन है।</p>	<p>मार्च 2016 तक भौतिक सत्यापन हो गया है तथा डीटीएल ने 2012-13 और 2016-17 के बीच रद्दी सामग्री बेच दिया है।</p>
<p>15. एसीएसआर जेब्रा कन्डक्टर के खरीद के लिए ठेके में आपूर्तिकर्ता का अनुचित पक्ष तथा डिफॉल्ट आपूर्तिकर्ता के जोखिम व</p>	<p>ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब-स्टेशनों की परियोजनाएं समकालिक बनाई जाये जिससे कि</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि 170.655 केएम की शेष मात्रा को प्रथम पक्ष के जोखिम व लागत पर उपार्जन कर लिया गया है।</p>	<p>कंपनी ने प्रथम पक्ष के जोखिम व लागत पर शेष मात्रा की खरीद कर ली है तथा गारंटी को भुनाकर अपने हितों की पूरी तरह से रक्षा की</p>

<p>लागत पर खरीद शुरू करने में देरी ।</p> <p>(पैरा सं. 7.11.2.4)</p> <p>डीटीएल ने 227 केएम का एसीएसआर जेब्रा कन्डक्टर खरीदने के लिए आदेश किया (दिसम्बर 2009)। ठेकेदार ने मात्र 56.345 केएम कन्डक्टर ही दे पाया परन्तु डीटीएल द्वारा पार्टी के जोखिम और लागत पर बाकी मात्रा के उपार्जन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, परफार्मेंस गारंटी की जमा राशि ₹ 19.36 लाख भुनाने को छोड़कर (अक्टूबर 2011)।</p>	<p>उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।</p>		<p>है तथा प्रथम पक्ष द्वारा किए गए आंशिक आपूर्ति के लिए भुगतान जारी नहीं किया है। तथापि, कुल वसूली के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है जिसके लिए समिति बनाई गई है (फरवरी 2017)।</p>
<p>16. जोखिम लागत पर सामग्री खरीद के संबंध में ठेकेदार से ₹ 0.61 करोड़ की गैर वसूली</p> <p>(पैरा सं. 7.11.2.6)</p> <p>डीटीएल ने एम/एस अल्फा को ₹ 1.62 करोड़ मूल्य के सामग्री की आपूर्ति हेतु खरीद आदेश दिया (नवम्बर 2009), तथापि, निरीक्षण के दौरान सामग्री स्वीकार्य नहीं पायी गयी एवं डीटीएल द्वारा अस्वीकार कर दी गई। बाद में डीटीएल ने दूसरे आपूर्तिकर्ता से प्रथम पक्ष के जोखिम व लागत पर ₹ 2.30 करोड़ मूल्य की सामग्री का उपार्जन किया। डीटीएल प्रथम पक्ष से मात्र ₹ 7.30 लाख बैंक गारंटी को भुनाकर वसूल कर पाया तथा शेष रकम ₹ 0.61 करोड़ वसूली हेतु बकाया थी।</p>	<p>ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब-स्टेशनों की परियोजनाएँ समकालिक बनाए गए हैं जिससे कि उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि एम/एस अल्फा के जोखिम व लागत पर ₹ 0.61 करोड़ के खरीद की वसूली का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।</p>	<p>मामला 2015 से दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।</p>

<p>17. एलडीसी के लिए आपदा प्रबंधन (पैरा सं. 7.12.1)</p> <p>आपदा के समय नुकसान से बचाव के लिए एसएलडीसी का पिछला आंकड़ा अलग बैंकअप साईट के जगह उसी परिसर पर एकत्र किए गए।</p> <p>18. सब-स्टेशनों के लिए आपदा प्रबंधन (पैरा सं. 7.12.2)</p> <p>डीटीएल में अलग से कोई आपदा प्रबंधन केंद्र/कक्ष नहीं था। अक्टूबर 2009 से दो व्यक्तियों की क्षमता वाला मात्र अग्नि एवं सुरक्षा कक्ष मौजूद था। केवल आठ सब-स्टेशनों पर कभी-कभी मॉक ड्रिल इत्यादि आयोजित किए गए। डीटीएल ने सीडए के दिशानिर्देशों के अनुसार आग आदि को रोकने के लिए 220 केवी सब स्टेशन पर 100 एमवीए ट्रांसफॉर्मर के साथ एनआईएफपीइएस प्रदान नहीं किया है। आगे, अन्य सुरक्षा उपायों जैसे फायरवॉल, तेल गढ़दे और रेत की बाल्टी भी 28 में से क्रमशः 15, पांच और पांच सब-स्टेशनों पर मुहैया नहीं कराए गए थे। 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान आग की चार घटनाएं हुईं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.31 करोड़ का नुकसान हुआ।</p>	<p>आपदा प्रबंधन हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय एवं बुनियादी ढांचे।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है:</p> <p>i) एनआईएफपीइएस के साथ-साथ सभी नये ट्रांसफॉर्मर खरीदे गए हैं।</p> <p>ii) अप्रैल 2015 में 18 हाईप्रेशर वाटर मिस्ट फायर एस्टिंग्युशर को खरीदा गया तथा अन्य आवश्यकता खरीद की प्रक्रिया में है।</p> <p>iii) चार अधिक कार्मिकों को नियुक्त कर अग्नि एवं सुरक्षा कक्ष को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया चल रही है।</p>	<p>बैंकअप एसएलडीसी (नियंत्रण डाटा) योजना की स्थापना दिसम्बर 2015 में पूरी हुई थी।</p> <p>डीटीएल ने अभी तक अलग आपदा प्रबंधन कक्ष स्थापित नहीं किया था।</p> <p>तथापि, आंशिक सुधार है क्योंकि 2012-13 और उसके बाद एनआईएफपीइएस के साथ-साथ 51 नये ट्रांसफॉर्मरों खरीदे गए। इस निवारक प्रणाली को अभी तक उपार्जन और पुराने ट्रांसफॉर्मरों के साथ स्थापित नहीं किया गया है। इसके बजाए डीटीएल ने डीटीएल के विभिन्न सब-स्टेशनों (18 संख्या) के लिए अन्य तरह के फायर एस्टिंग्युशर को खरीदा और मुहैया कराया।</p> <p>आगे, अन्य सुरक्षा उपायों में सुधार देखा गया है क्योंकि फायरवॉल, तेल गढ़दे और रेत की बाल्टियां क्रमशः 24, 33 और 36 सब-स्टेशनों पर अब उपलब्ध थे (कुल 39 सब स्टेशन)। इसके अलावा, 2012-13 से 2016-17 के दौरान आग की कोई घटना नहीं हुई इससे दक्षता में सुधार और घाटे में कटौती करने में मदद मिली।</p>
<p>19. आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा (पैरा सं. 7.13.2)</p> <p>डीटीएल के पास अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा नियम</p>	<p>पर्याप्त सुरक्षा उपाय</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा त्रैमासिक आधार पर किया जा रहा है तथा सभी डिविजनों को शामिल</p>	<p>डीटीएल ने 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः चार, तीन, चार, तीन और चार लेखापरीक्षा समिति बैठकें</p>

<p>पुस्तिका नहीं है जो क्षेत्र, दायरा और आवधिकता इत्यादि को निर्धारित कर सके। आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य 2007-08 से निजी चार्टर्ड एकाउंटेंट को आऊटसोर्स किया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा को 2010-11 तक पूरा नहीं किया गया।</p> <p>20. लेखापरीक्षा समिति (पैरा सं. 7.13.3) लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने/चर्चा करने में हुई देरी और आंतरिक लेखापरीक्षकों के 18 बैठकों में से केवल सात बैठकों में उपस्थिति होने पर प्रकाश डाला।</p>		<p>करते हुए सितम्बर 2016 तक का लेखापरीक्षा को पूरा कर लिया गया है।</p>	<p>की गई। आगे, 2016-17 के प्रथम छमाही तक आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर इन लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में चर्चा की गई परन्तु लेखापरीक्षा समिति की बैठक में आंतरिक लेखापरीक्षकों की उपस्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ था क्योंकि 2012-13 से 2016-17 के दौरान आयोजित की जाने वाली 18 बैठकों में से केवल आठ बैठकों में उपस्थित हुए। आगे, आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली अभी तक नहीं बनायी गयी हैं।</p>
---	--	--	--

ग) पूर्ण कार्यान्वयन

पूर्व लेखापरीक्षा में दी गई अभ्युक्तियों के सार	की गई सिफारिश	कंपनी द्वारा दी गई सूचना की वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा प्राप्ति/टिप्पणी
<p>1. ट्रांसमिशन लाइनों के कार्यान्वयन में हुई देरी के कारण मांग की गई मात्रा से अधिक एचडीपीड पाइपों के उपयोग पर ₹ 24.86 करोड़ का परिहार्य व्यय (पैरा सं. 7.7.5)</p>	<p>भा.स. के टास्क फोर्स की सिफारिशों और ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर सीइए/ डीइआरसी के निर्देशों का अनुसरण किया जाना है।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि भविष्य की योजनाओं के लिए डीटीएल के नियोजन विभाग ने सिविल कार्यों और साइट परिस्थितियों के मानदंडों को ध्यान में रखकर पाइप की मात्रा को सुनिश्चित किया है।</p>	<p>2012 के बाद डीटीएल ने एनआईटी/टर्नकी परियोजना/योजना में उल्लिखित ट्रांसमिशन लाइन के प्रति किमी दर के तहत मात्रा के बिल के अनुसार पाइप का इस्तेमाल किया। अब ऐसा कोई मामला लेखापरीक्षा के संज्ञान में नहीं आया है।</p>
<p>2. ट्रांसमिशन लाइनों और एसएस परियोजनाओं के गैर सिंक्रनाइजेशन के कारण धन का अवरोध (पैरा सं. 7.7.6)</p> <p>220 केवी 1000 वर्ग मिमी यू/जीएक्स एलपीड केबल लिंक (i) मुण्डका से पीरागढ़ी सब-स्टेशन और (ii) पीरागढ़ी से वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र सब-स्टेशन</p>	<p>ट्रांसमिशन लाइनों तथा सब स्टेशनों की परियोजनाओं का सिंक्रनाइज सुनिश्चित करने के लिए डीटीएल कदम उठाने पर विचार करें जिससे कि उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।</p>	<p>डीटीएल ने कहा (नवम्बर 2017) विदेशी बोलीकर्ता जिनकी भारत में परियोजना कार्यालय है के मुद्दे को कंपनी के बोलीकर्ता (आईटीबी) निर्देश दस्तावेजन में अब शामिल किया गया है।</p>	<p>डीटीएल ने 2012 के बाद किसी भी विदेशी बोलीकर्ता को टर्नकी आधार पर कोई कार्य नहीं दिया, तथापि इसने अपने नवीनतम आईटीबी में कथित खण्ड को समाविष्ट किया था।</p>

<p>(₹ 102.18 करोड़) (पैरा सं. 7.7.6.2)</p>			
<p>3. ट्रांसमिशन हानियाँ (पैरा सं. 7.8.4)</p> <p>2007-08 से 2011-12 के दौरान ट्रांसमिशन हानियाँ डीइआरसी द्वारा स्वीकृत 0.95 प्रतिशत के मानदंडों के प्रति 1.21 प्रतिशत और 1.59 प्रतिशत के बीच थीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.54 करोड़ मूल्य के 503 एमयू का नुकसान हुआ।</p>	<p>ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल का संस्थापन।</p>	<p>डीटीएल द्वारा 2012-13 से 2016-17 के लिये ट्रांसमिशन हानियों का विवरण दिया गया है।</p>	<p>2013-14 से 2016-17 के दौरान कंपनी ट्रांसमिशन घाटे को कम करने में कामयाब रही और 0.95 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर थी जो करीब 99 प्रतिशत उपलब्धता पर ट्रांसमिशन को प्रबंधित व संचालित कर प्राप्त किया गया है।</p>
<p>4. आवृत्ति प्रबंधन द्वारा ग्रिड डिसिप्लिन (पैरा सं. 7.9.2)</p> <p>लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने उजागर किया कि एसएलडीसी (अक्टूबर 2008) दिल्ली ग्रिड प्रणाली में कम आवृत्ति के तहत बिजली के अधिक भार को नियंत्रित नहीं कर सका जिसके लिए केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण (सीइआरसी) ने ₹ 2.5 लाख का जुर्माना लगाया।</p>	<p>ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल का संस्थापन।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि डीइआरसी 2013 में एसएलडीसी के व्यय को संतुलित करते हुए जुर्माने की अनुमति दी है। पावर के अधिक भार व कम भार को नियंत्रित करने के लिए सीइआरसी द्वारा किए गए विभिन्न पहल के कारण ग्रिड डिसिप्लिन में सुधार हुआ है।</p>	<p>सीइआरसी/डीइआरसी ने डीटीएल पर किसी ग्रिड इनडिसिप्लिन के लिए 2012-13 से 2016-17 के दौरान कोई जुर्माना नहीं लगाया।</p>
<p>5. निर्देशों का परामुख होना (बीडीआई) (पैरा सं. 7.9.3)</p> <p>एसएलडीसी ने उत्पादक कंपनियों द्वारा बीडीआई का अनुपालन करने और इसके लिए जुर्माना लगाने का भी अलग से कोई अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया। जिसके अभाव में बीडीआई जारी करने का उद्देश्य पराभूत हो गया।</p>	<p>ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल का संस्थापन।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (आरएलडीसी) अंतर्राज्यीय जेनरेशन स्टेशनों (आईएसजीएस) के लिए जेनरेशन शेड्यूल का अनुरक्षण कर रहा है तथा एसएलडीसी मासिक ऊर्जा खातों की तैयारी के लिए वास्तविक समय के आधार पर अनुसूची तैयार कर रहा है। अर्थात् सभी शेड्यूलिंग/बैंकिंग डाउन निर्देशों को वेब आधारित मॉड्यूल के माध्यम से किया जाता है।</p>	<p>दिल्ली प्रणाली में पावर की सभी शेड्यूलिंग को अब वास्तविक समय के आधार पर बनाया जा रहा है तथा सभी निर्देशों का नियंत्रण वेब आधारित मॉड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है और लेखांकन उद्देश्य से किसी भी समय देखा जा सकता है।</p>

<p>6. ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा (पैरा सं. 7.9.6)</p> <p>डीटीएल ने केंद्रीय ग्रिड से प्राप्त पावर के आवक बिन्दु पर उपयोगिता ट्रांसमिशन के लिए इंटरफेस मीटर स्थापित नहीं किया है इसके बदले पावर लेखांकन के लिए पीजीसीआईएल द्वारा स्थापित मीटरों पर निर्भर है। डीटीएल ने डीटीएल के 66/33 केवी सब-स्टेशनों से 230 आऊटगोईंग डिस्कॉम फीडर में से 147 ऑडिट मीटर उपलब्ध कराए हैं।</p>	<p>ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल का संस्थापन।</p>	<p>डीटीएल ने कहा कि शेष आऊटगोईंग डिस्कॉम फीडर पर अब ऑडिट मीटर लगाए जा चुके हैं।</p>	<p>शेष फीडरों पर अब ऑडिट मीटर लगा दिए गए हैं।</p>
---	---	---	---

2.10.3 निष्कर्ष

- लाइनों और सब-स्टेशनों के निर्माण तथा शुरुआत की प्रमुख परियोजनाएं जो 31 मार्च 2012 तक कार्यान्वयन के अधीन थे उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया गया और काम में लाया गया यद्यपि आगे सात माह से 34 माह की देरी थी। देरी में एक माह से 19 माह के बीच में कटौती की गई है और 2014-15 से की गई नयी प्रमुख परियोजनाओं के संबंध में सिंक्रनाइजेशन में सुधार हुआ है (केबल लिंक कार्य के अल्प उपयोग के एक मामले को छोड़कर) तथापि, देरी के मुख्य कारण जैसे निविदा आमंत्रित करने का नोटिस (एनआईटी) आमंत्रित करना और आदेश प्रदान करना, राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) अनुमति इत्यादि अभी भी कायम है।
- डीटीएल वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन लाइनों के क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को क्रमशः 50 प्रतिशत और 54 प्रतिशत तक हासिल करने में विफल रहा, यद्यपि लक्ष्य की उपलब्धि का घाटा कम कर दिया गया है क्योंकि समीक्षा अवधि के दौरान यह क्रमशः 68 प्रतिशत और 66 प्रतिशत था।
- ऑपरेशन और अनुरक्षण में सुधार हुआ है जिससे ट्रांसमिशन हानियों में 2007-08 से 2011-12 के दौरान औसतन 1.40 प्रतिशत (1.21 से 1.59 प्रतिशत की सीमा तक) से 2012-13 से 2016-17 के दौरान 0.92 प्रतिशत (1.15 से 0.70 प्रतिशत की सीमा तक) की कमी आई है; 220 केवी में वोल्टेज स्तर में सुधार, ट्रांसफॉर्मर की कम विफलता तथा ट्रांसमिशन क्षमता की 99 प्रतिशत की उपलब्धता।
- आपदा प्रबंधन के तहत सुधार हुआ है। डीटीएल ने एनआईएफपीडिएस के साथ नये सब-स्टेशन स्थापित करना और नये ट्रांसफॉर्मर की खरीद

करना शुरू किया और अधिक सब-स्टेशनों पर रेत की बाल्टियां, फायरवॉल और तेल कुआं उपलब्ध कराए। डीटीएल, हालांकि, पुराने ट्रांसफॉर्मरों के साथ एनआईएफपीइएस स्थापित करने में विफल रहा।

- खरीद और इन्वेंटरी नियंत्रण की व्यवस्था में कमी बनी हुई है क्योंकि एनआईटी की प्रक्रिया और खरीद आदेशों को प्रदान करने में देरी देखी गयी है।

इस प्रकार, पांच सिफारिशों के तहत 34 कार्रवाई योग्य अभ्युक्तियों में से छः अभ्युक्तियों का पूर्ण कार्यान्वयन, 20 अभ्युक्तियों के संबंध में आंशिक कार्यान्वयन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आठ अभ्युक्तियों के संबंध में नगण्य प्रगति हुई। अतः डीटीएल के कामकाज पर पूर्व प्रतिवेदन में उजागर अपर्याप्तता में आंशिक रूप से सुधार हुआ है और लेखापरीक्षा सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जाना अभी बाकी है।

मामला सरकार को भेजा गया (अगस्त 2017), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

नई दिल्ली
दिनांक: 19 मार्च 2018



(सुशील कुमार जायसवाल)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 21 मार्च 2018



(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक